भारतीय रेल

अगस्त-सितम्बर 2020

₹10

नए दौर में भारतीय रेल



FLUID CONTROLS®
ENGINEERING CONNECTIONS EVERYDAY



Design & Engineering

High Performance Connectors

Onsite Installation

Swaging Services

Pre-Piped Assemblies

ENGINEERING COMPREHENSIVE SOLUTIONS FOR **RAIL & METRO BRAKE PIPING**

Fluid Controls® has over 45 years of experience in engineering connections for Rail & Metro brake piping assemblies. We offer customers comprehensive solutions for locomotive, coach & metro brake piping arrangements – from design and engineering services to supply of high performance connectors and installation services.

DOUBLE FERRULE FITTINGS • DIN SINGLE FERRULE CONNECTORS
ACROSS FRAME™ CONNECTORS • THREADED ADAPTORS • FLEXIGRIP™ CONNECTORS
QUICK RELEASE CONNECTORS • VALVES • CLAMPS

+91-22-68238000 railways@fluidcontrols.com fluidcontrols.com

भारतीय रेल

रेल मंत्रालय की एकमात्र हिन्दी मासिक पत्रिका

अगस्त–सितम्बर 2020 | आरंभ : 1960 | वर्ष : 61 | अंक : 1–2 | मूल्य : ₹10

संपादक मंडल

श्री विनोद कुमार यादव
अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रेलवे बोर्ड

श्रीमती मंजुला रंगराजन
सदस्य (वित्त), रेलवे बोर्ड

श्री सुशांत कुमार मिश्रा
सचिव, रेलवे बोर्ड

श्री राजेश दत्त बाजपेई
कार्यकारी निदेशक, सूचना एवं प्रचार

योगेश अवस्थी
संपादक

संपादकीय कार्यालय

संपादक, भारतीय रेल,
कमरा नं. 337-बी, रेल भवन,
रायसीना रोड, नई दिल्ली-110001
editorbhartiyarailrb@gmail.com
editorbhartiyarail@gmail.com

विज्ञापन व सदस्यता हेतु संपर्क

श्री प्रशान्त कुमार पट्टनायक
व्यापार प्रबंधक
कमरा नं. 310, रेल भवन
रायसीना रोड, नई दिल्ली-110001
टेलीफोन: 23303665, 23382531
bmpr310rb@gmail.com

सदस्यता शुल्क

सर्वसाधारण - ₹250
रेलकर्मियों के लिए - ₹200
(1 अक्टूबर, 2020 से प्रभावी)

संपादन सहयोग

श्री रणमत सिंह

आवरण

गोवा की जुवारी नदी पर बने रेल पुल से गुजरती रो-रो ट्रेन का दृश्य

फॉलो करें

Twitter : @bhartiyarailrb
Facebook : bhartiyarailpatrika
Instagram : bhartiyarailpatrika

इस पत्रिका में छपी हर सामग्री का सम्बन्ध, जब तक विशेषत: स्पष्ट न लिखा जाए, किसी सरकारी सूत्र से न समझा जाए।

© भारतीय रेल



किसानों के हित में पटरी पर दौड़ने लगी किसान रेल 6

8 भारतीय रेल ने बांग्लादेश को 10 रेल इंजन सौंपे
9 आईआरसीटीसी और एसबीआई कार्ड ने रुपे प्लेटफॉर्म पर क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया
9 रेल मंत्री ने माल ढुलाई में मजबूत साझेदारी हेतु लॉजिस्टिक कंपनियों के संग बैठक की
10 रेल मंत्री द्वारा डीएफसी के कार्यों की समीक्षा
11 रेल मंत्रालय द्वारा पहली बार वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर सेवानिवृत्ति समारोह का आयोजन



हुबली का नया रेल संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित 12

17 रेल मंत्री का उद्योगपतियों को भारतीय रेल की परिवर्तन की यात्रा में साथ आने का आमंत्रण
19 कर्नाटक के मुख्यमंत्री और रेल राज्य मंत्री ने नेलमंगला से बाले तक पहली रो-रो सेवा...
23 भारतीय रेल को 2030 तक 'हरित रेलवे' बनाने का लक्ष्य
25 कोविड के बावजूद रेलवे ने मिशन मोड पर ज्यादा माल ढुलाई की
26 भारतीय रेल 2030 तक 33 बिलियन यूनिट से अधिक की ऊर्जा खपत को पूरा करेगी
29 रेलकर्मियों के लिए ई-पास की सुविधा शुरू
32 पोस्ट कोविड कोच
34 राष्ट्रपति ने विशिष्ट सेवा हेतु आरपीएफ कर्मी को पुलिस पदक से सम्मानित किया
34 राष्ट्रपति द्वारा आरपीएफ के तीन जवान 'जीवन रक्षा पदक' से सम्मानित
36 भारतीय रेल ने सुरक्षा के लिए ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किया

डीसी को नई एसी बिजली लाइन में बदलने की रोचक जानकारी
श्री विमलेश चन्द्र
37

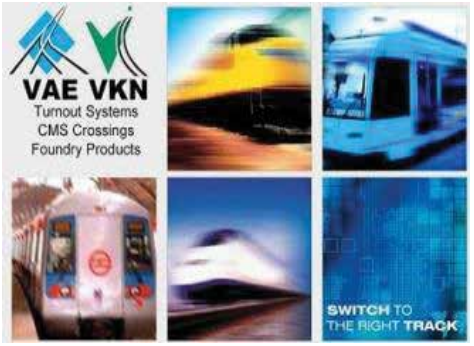


41 भारतीय रेल और मनरेगा — *श्री प्रथम अग्रवाल*
43 रेलों के अंचल से
57 आध्यात्मिक नगरी अयोध्या — *श्री अनिल सक्सेना*
62 आम आदमी, खास काम — *डॉ. बरुण कुमार*
65 औषधि - वाटिका — *डॉ. प्रसून कुमार त्रिपाठी*
71 किरदार भी, इन्सान भी — *श्री अविनाश त्रिपाठी*
73 पर्यावरण संरक्षण पर इतना काम... — *डॉ. आशीष दुबे*

VAE VKN
Turnout Systems
CMS Crossings
Foundry Products

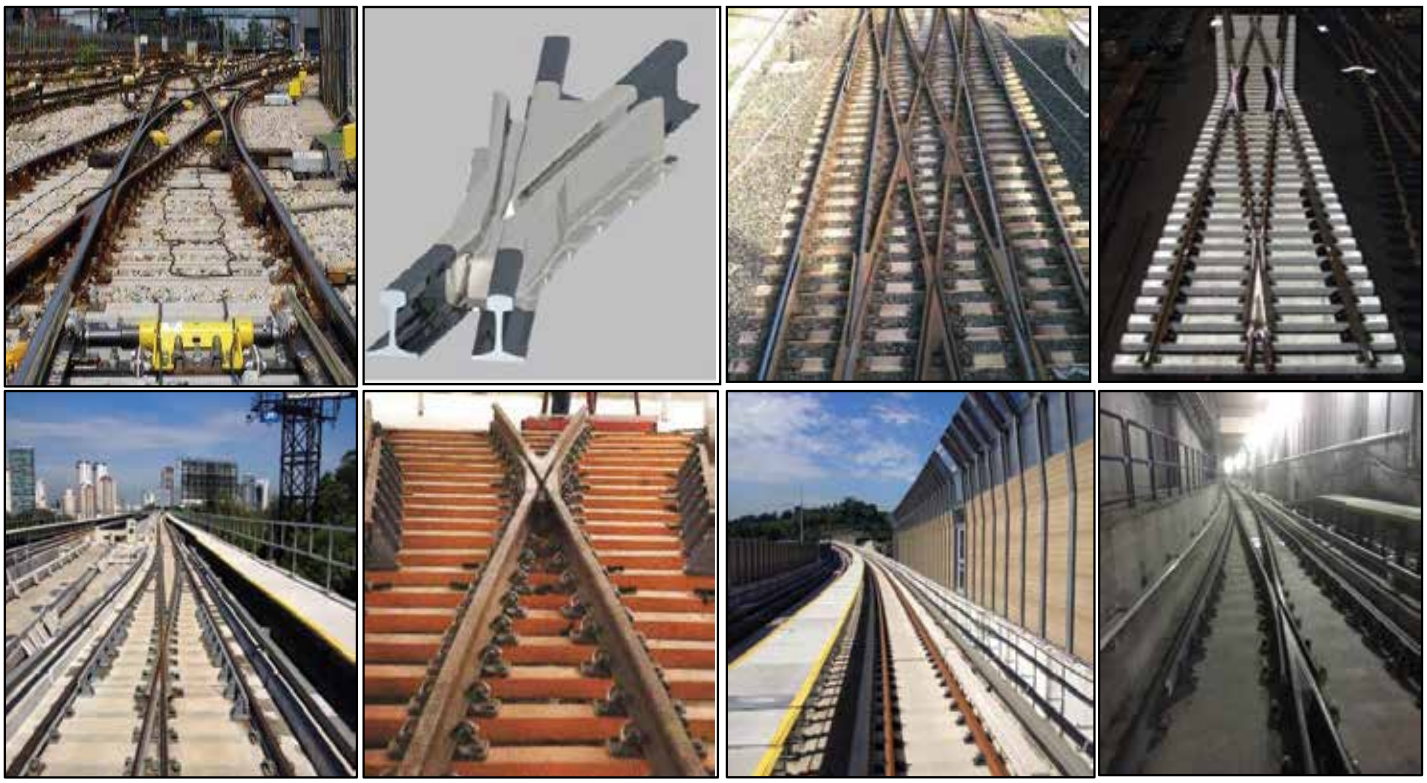
Product Range

- **CMS Crossings with welded leg extensions, EDH**
- **Switches /Thick Web Switches**
- **Diamond Crossings in CMS**
- **Scissor Crossover in CMS**
- **Turnout Solutions for MRTS**
- **Heavy Haul Turnout Solutions**
- **Castings of different steel grades ranging from 20 KG to 5 MT**



voestalpine VAE VKN India Pvt. Ltd., Sonepat (Haryana) is a joint venture, multinational company in collaboration with voestalpine VAE GmbH, Austria, globally renowned and a pioneer company in the field of Railway Track Systems and its affiliate company JEZ Sistemas Ferroviarios S.L., Spain, specialized in manufacture of CMS Crossings for conventional, heavy-haul and high-speed applications.

The Company is managed by competent, well qualified technical, commercial and managerial professionals merging international and local Indian expertise. VAE VKN is well equipped with most modern and state of the art infrastructure and technical back up by VAE and their associates all over the world over to produce and meeting quality requirement of the customers in all respects.



Works:
42 Milestone, GT Road, Bahalgarh
Sonepat (Haryana) – 131 001
INDIA
Tel.: +91 130 2381298 2380369
Fax: +91 130 2381698

Registered Office:
24/5, Sri Ram Road
Civil Lines, Delhi -110 054
INDIA
Tel.: +91 11 23965651
Fax: +91 11 23965653



संपादकीय



मिशन मोड से देश के आर्थिक विकास को गति देती भारतीय रेल

कोविड महामारी के बावजूद भारतीय रेल देश की आर्थिक विकास यात्रा को आगे बढ़ाने के पूरे प्रयास कर रही है। इस महामारी को एक चुनौती मानते हुए भारतीय रेल ने 'मिशन मोड' पर कार्य किया, जिसके परिणामस्वरूप माल ढुलाई तथा आय में अच्छी वृद्धि देखी जा रही है।

अनलॉक की परिस्थिति में भी यात्री रेलगाड़ियाँ निश्चित संख्या में ट्रैक पर दौड़ रही हैं। इस समय मालगाड़ियों की सेवा तथा गति में वृद्धि की गई है। बाजार से अधिक माल ढुलाई रेलवे की ओर लाने के लिए व्यावसायिक इकाइयों की स्थापना की गई है और रेल परिवहन को अधिक आकर्षक बनाया गया है। माल ढुलाई में मजबूत साझेदारी हेतु लॉजिस्टिक कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल स्वयं बैठक कर संवाद कर रहे हैं, जिसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। डी.एफ.सी. की परियोजना निर्धारित समय पर पूर्ण हो, इसके लिए भी रेल मंत्री द्वारा समय-समय पर समीक्षा बैठक की जा रही है। साथ ही, किसानों को अतिरिक्त लाभ पहुंचाने तथा जल्दी नष्ट होने वाली उपभोग की वस्तुओं को जल्द गंतव्य तक पहुँचाने हेतु 'किसान रेल' चलाई जा रही हैं। प्रथम किसान रेल ट्रेन को रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था।

भारतीय रेल हमेशा से पर्यावरण हितैषी रही है। भारतीय रेल को वर्ष 2030 तक हरित रेलवे बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तेज गति से किए जा रहे विद्युतीकरण कार्य को वर्ष 2023 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। भारतीय रेल द्वारा अपनी खाली जमीन तथा स्टेशनों की छत आदि पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जा रहे हैं। इससे वर्ष 2030 तक 33 बिलियन यूनिट से अधिक की ऊर्जा खपत होगी, जिसको अपने संसाधनों से पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। कुल 505 जोड़ी ट्रेनों में 'हेड ऑन जेनरेशन' तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इससे प्रति वर्ष लगभग 70 मिलियन लीटर डीजल व 450 करोड़ रुपये की बचत की संभावना है। कार्बन उत्सर्जन को कम करने तथा ईंधन और समय की बचत आदि में उपयोगी रोल ऑन रोल ऑफ ट्रेन सेवा चलाई जा रही है। हाल ही में रेल राज्य मंत्री श्री सुरेश अंगडी तथा कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री बी. एस. येदियुरप्पा ने नेलंगला से बाले तक पहली रो-रो सेवा को हरी झंडी दिखाई।

भारतीय रेल अपने कर्मियों का समान सम्मान करती है। इसी कड़ी में भारतीय रेल में पहली बार वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आभासी सेवानिवृत्ति समारोह का आयोजन किया गया। इसमें सेवानिवृत्त हो रहे 2,320 रेलकर्मियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में रेल मंत्री श्री गोयल ने इन रेलकर्मियों से संवाद कर उन्हें प्रोत्साहित किया।

दोस्तों, 'भारतीय रेल' पत्रिका के साथ आप का अटूट रिश्ता बना हुआ है। हमारी पूरी टीम का पूरा प्रयास होता है कि हम अपने पाठकों को श्रेष्ठतम दें। पिछले कुछ अंकों से आप सभी पत्रिका की लेखन सामग्री, डिजाइन, प्रिंट, आर्ट पेपर आदि की गुणवत्ता में सुधार को महसूस कर रहे हैं और इसकी खुलकर प्रशंसा भी कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों से पत्रिका की छपाई तथा अन्य खर्चों में काफी वृद्धि हुई है, लेकिन पत्रिका के सदस्यता शुल्क में वर्षों से बढ़ोत्तरी नहीं की गई थी, लेकिन अब सदस्यता शुल्क में वृद्धि करना अपरिहार्य हो गया था। हम अभी भी पत्रिका के कुल खर्च का कुछ भाग ही अपने पाठकों से सदस्यता शुल्क के रूप में ले रहे हैं।

हमें विश्वास है आप सभी सुविज्ञ पाठक हमारा साथ देंगे। साथ ही, हम यह भी बताना चाहेंगे पाठक अब पत्रिका के सदस्यता शुल्क का भुगतान आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन भी कर सकते हैं।

कोविड जैसी विषम परिस्थिति के चलते भारतीय रेल पत्रिका का प्रकाशन ई-पत्रिका के रूप में नियमित रूप किया गया था। अनलॉक शुरू होते ही इन पत्रिका का प्रिंट वर्जन हम अपने पाठकों को पहुँचा रहे हैं। इस माह पत्रिका की डेडलाइन सेट करने के लिए हम अगस्त एवं सितम्बर माह का संयुक्त अंक प्रकाशित कर रहे हैं। हम अपने वार्षिक सदस्यों को उनकी सदस्यता की अवधि समाप्त होने के बाद भी एक अतिरिक्त अंक प्रदान करेंगे।

आपको हमारा यह अंक कैसा लगा, हमें जरूर बताएँ। आपके सुझाव ही हमारे मार्गदर्शक हैं। ■



किसानों के हित में पटरी पर दौड़ने लगी किसान रेल

देश की पहली किसान रेल को श्री नरेंद्र सिंह तोमर और श्री पीयूष गोयल ने हरी झंडी दिखा कर रवाना की





देवलाली-दानापुर किसान रेल को कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर तथा रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल और रेल राज्य मंत्री श्री सुरेश अँगडी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया

भारतीय रेल ने 7 अगस्त, 2020 को देवलाली से पहली 'किसान रेल' का शुभारम्भ किया, जो देवलाली (महाराष्ट्र) से दानापुर (बिहार) तक चलेगी। केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर तथा रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस कार्यक्रम में रेल राज्य मंत्री श्री सुरेश अँगडी, पंचायती राज, कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला, कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री श्री राव साहेब पाटिल दानवे, महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता श्री देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र सरकार के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता सुरक्षा मंत्री श्री छगन भुजबल एवं अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

इस अवसर पर श्री तोमर ने कहा, "किसान रेल की घोषणा बजट में की गई थी। कृषि उत्पादों को सर्वश्रेष्ठ संभावित वितरण और रिटर्न की आवश्यकता होती है। किसान रेल कृषि उत्पादों को देश के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाना सुनिश्चित करेगी। इस ट्रेन से किसानों और उपभोक्ताओं, दोनों को ही फायदा होगा।" इस अवसर पर श्री गोयल ने कहा कि

किसान रेल से लाभ

- सडक परिवहन की तुलना में कम समय व लागत
- छोटे किसानों को अपनी उपज की अच्छी कीमत प्राप्त हो सकेगी
- परिवहन के दौरान उपज का कम नुकसान
- मौसबी, अनार, खरबूजा, पपीता, अमरूद, टमाटर आदि फल और सब्जियों के व्यापार से संबंधित छोटे किसान तथा व्यापारियों को लाभ
- देश भर में फल और सब्जियों की आपूर्ति में संतुलन



"भारतीय रेल ने किसानों की सेवा में ट्रेनें लगाई हैं। यह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का मार्गदर्शन और प्रेरणा ही है, जो भारतीय रेल ने 'किसान रेल' का शुभारम्भ किया है। यह ट्रेन किसानों की आय दोगुनी करने में एक मील का पत्थर साबित होगी।'' भारतीय रेल और किसान कोविड चुनौतियों से निपटने में अग्रणी रहे थे। इस अवधि के दौरान खाद्यान्न की ढुलाई दोगुनी हो गई थी। भारतीय किसानों के हित को खासी प्राथमिकता दी जा रही है, जो पहले कभी नहीं हुआ। मध्य रेल का भुसावल मंडल प्राथमिक रूप से कृषि आधारित मंडल है।

नासिक और उसके आसपास के क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में ताजी सब्जियां, फल, फूल, अन्य जल्द सड़ने वाले उत्पाद, जैसे प्याज और अन्य कृषि उत्पाद पैदा होते हैं। जल्द सड़ने वाले इन खाद्य पदार्थों की मुख्य रूप से पटना, प्रयागराज, कटनी, सतना आदि क्षेत्रों के लिए ढुलाई की गई है।

देश की दूसरी व दक्षिण भारत की पहली किसान रेल का शुभारंभ





अनंतपुर-आदर्श नगर किसान रेल का शुभारंभ कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर और आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री वाय.एस. जगनमोहन रेड्डी तथा रेल राज्य मंत्री श्री सुरेश अँगडी ने हरी झंडी दिखा कर किया

देश की दूसरी और दक्षिण भारत की पहली किसान रेल का शुभारंभ कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर और आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री वाय.एस. जगनमोहन रेड्डी के मुख्य आतिथ्य में हुआ। समारोह की अध्यक्षता रेल राज्य मंत्री श्री सुरेश अँगडी ने की। यह विशेष गाड़ी दक्षिण मध्य रेलवे के गुंतकल मंडल के अनंतपुर (आंध्र प्रदेश) से आदर्श नगर (दिल्ली) के लिए रवाना हुई। इस अवसर पर श्री तोमर ने कहा कि किसान रेल से कृषि की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, वहीं श्री रेड्डी ने कहा कि इसके माध्यम से आंध्र प्रदेश के मशहूर फल देश में सुगमता से पहुंचेंगे।

श्री तोमर ने कहा कि गांव-गरीब-किसान हमेशा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता पर रहे हैं। खेती की व्यवस्था में किसानों को मुनाफा हो, उनकी आय दोगुनी हो, इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रधानमंत्री हर बजट में प्रयत्न करते रहे हैं, जो सफल भी हो रहे हैं। बजट में किसान रेल व किसान उड़ान की सुविधाओं की घोषणा की गई थी, ताकि फल-सब्जियां कम समय में एक से दूसरे स्थान पर भेजी जा सकें। गत 7 अगस्त को देवलाली से दानापुर तक पहली किसान रेल प्रारंभ की गई,



जिसकी मांग बढ़ने पर रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल ने इसके फेरे भी बढ़ा दिए हैं। अब दूसरी किसान रेल चलने से आंध्रप्रदेश से दिल्ली तक रास्ते के सभी राज्यों के किसानों को भी इसका लाभ होगा। अनंतपुर में 2 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में फल-सब्जियों की खेती की जाती है, किसान रेल चलने से इन किसानों को लाभ होगा।

श्री रेड्डी ने कहा कि बागवानी में आंध्रप्रदेश का महत्त्वपूर्ण स्थान है। टमाटर, पपीता, कोको व चिली के उत्पादन में देश में आंध्रप्रदेश का पहला स्थान है। कोविड संकट के चलते ये उपज दिल्ली तक पहुंचाना मुश्किल हो रहा था, इसलिए प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया गया था। उन्होंने किसानों की सुविधा के लिए इसकी व्यवस्था कराई। आंध्रप्रदेश, दक्षिण भारत का बड़ा फल उत्पादक राज्य है। लॉकडाउन में 11 विशेष रेलगाड़ी अनंतपुर से मुंबई चलाई गईं ताकि यहां के फल देश के विभिन्न स्थानों तक पहुंच सकें।

श्री अँगडी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य किसानों की आय दोगुनी करना है। जहां किसानों को परिवहन की सुविधा नहीं है, वहां किसान रेल प्रारंभ करके उनकी सहायता की जा रही है। अब आंध्र से दिल्ली तक कम समय में किसानों के उत्पाद पहुंच जाएंगे। केंद्र सरकार के नए अध्यादेश से किसान उनके उत्पाद वहां बेच सकते हैं, जहां उन्हें उसकी सही कीमत मिले। यह गाड़ी दक्षिण भारत के किसानों को उत्तर भारत से जोड़ने का काम करेगी। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री श्री परषोत्तम रूपाला व श्री कैलाश चौधरी, आंध्र प्रदेश के मंत्री श्री बी. सत्यनारायण, श्री एम. शंकरनारायण व श्री के. कन्नाबाबू, अनंतपुर के सांसद श्री टी. रंगय्या, क्षेत्रीय विधायक व अन्य जनप्रतिनिधि, कृषि मंत्रालय के सचिव श्री संजय अग्रवाल तथा साउथ सेंट्रल रेलवे के महाप्रबंधक श्री गजानन मलैया भी उपस्थित थे। ■

भारतीय रेल ने बांग्लादेश को 10 रेल इंजन सौंपे

दिनांक 27 जुलाई को बांग्लादेश को इंजन सौंपे जाने के लिए आयोजित एक समारोह में विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर और रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, श्री पीयूष गोयल ने 10 ब्रॉडगेज इंजनों को बांग्लादेश के लिए रवाना किया। इस कार्यक्रम में रेल राज्यमंत्री श्री सुरेश अँगडी भी उपस्थित थे। बांग्लादेश के रेल मंत्री नूरुल इस्लाम सुजान और विदेश मंत्री डॉ. अबुल कलाम अब्दुल मोमेन ने बांग्लादेश सरकार की ओर से इन रेल इंजनों को प्राप्त किया।

भारत सरकार की ओर से अनुदान सहायता के अंतर्गत इन रेल इंजनों को सौंपा जाना अक्टूबर, 2019 में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत यात्रा के दौरान की गई एक महत्त्वपूर्ण प्रतिबद्धता को पूरा करता है। बांग्लादेश रेलवे की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेल द्वारा इंजनों में जरूरी संशोधन किए गए हैं। ये इंजन बांग्लादेश में यात्रियों की संख्या बढ़ाने और मालगाड़ी के परिचालन को बेहतर बनाने में सहायता प्रदान करेंगे।

इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने कहा कि मुझे यह जानकर खुशी महसूस हो रही है कि दोनों देशों के बीच पार्सल और कंटेनर ट्रेनों की शुरुआत कर दी गई है। इससे हमारे कारोबारियों के लिए नए अवसर खुलेंगे। रेलवे द्वारा व्यापार के आवागमन को सुनिश्चित किया गया है। कोविड-19 महामारी के दौरान, विशेष रूप से रमजान के पवित्र महीने में अनिवार्य आपूर्तियां सुनिश्चित की गईं।

इस अवसर पर श्री गोयल ने कहा, "बांग्लादेश रेलवे द्वारा उपयोग करने के लिए 10 ब्रॉडगेज रेल इंजन सौंपने में मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये इंजन भारत और बांग्लादेश के बीच मालगाड़ी परिचालन को संभालने में उपयोगी साबित होंगे। हमारे पड़ोस की नीति प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'सबका साथ, सबका विकास' वाले दर्शन का अनुसरण करती है। भारत और बांग्लादेश, दोनों का नेतृत्व दोनों देशों के बीच सन् 1965 से पहले के रेल संपर्कों को पुनर्जीवित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उस समय के मौजूदा 7 रेल संपर्कों में से वर्तमान में 4 क्रियाशील हैं। इस क्षेत्र में रेल संपर्कों को और मजबूत करने के लिए भारत के अगरतला और बांग्लादेश के अखौरा के बीच एक नए रेल संपर्क का निर्माण किया जा रहा है, जिसे भारत की अनुदान सहायता के अंतर्गत वित्तपोषित किया जा रहा है। बांग्लादेश में बेनापोल के रास्ते पार्सल ट्रेन और कंटेनर ट्रेन सेवाएं शुरू की गई हैं। इन दोनों सेवाओं की शुरुआत जुलाई माह में की जा चुकी है। अपने संबोधन के दौरान श्री गोयल ने भारतीय रेल की ओर से बांग्लादेश रेल नेटवर्क के विकास में बांग्लादेश को पूर्ण, उदार और असीमित सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। ■

- ये इंजन बांग्लादेश में यात्रियों की संख्या बढ़ाने और मालगाड़ी के परिचालन को बेहतर बनाने में सहायता करेंगे
- विदेश मंत्री श्री एस. जयशंकर ने भारत-बांग्लादेश संबंधों की प्रगाढ़ता को रेखांकित किया, जो आपसी विश्वास और सम्मान पर आधारित है
- रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने बांग्लादेश रेल नेटवर्क के विकास में बांग्लादेश को पूर्ण, उदार और असीमित सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया



27 जुलाई को रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, श्री पीयूष गोयल और विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बांग्लादेश को 10 ब्रॉडगेज इंजन सौंपे

आईआरसीटीसी और एसबीआई कार्ड ने रुपे प्लेटफॉर्म पर क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया

आईआरसीटीसी और एसबीआई कार्ड ने मिलकर रुपे प्लेटफॉर्म पर अपना नया सह-ब्रांडेड संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया, जिसे 28 जुलाई, 2020 को रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने राष्ट्र को समर्पित किया।

इस अवसर पर श्री गोयल ने कहा कि यह रेलवे द्वारा की गई कई 'मेक इन इंडिया' गतिविधियों में से एक है।

नया रुपे क्रेडिट कार्ड नियर फील्ड कम्युनिकेशन (एनएफसी) तकनीक से लैस है। अत: इसके उपयोगकर्ता कार्ड को स्वाइप करने की बजाय पीओएस मशीनों पर कार्ड को टैप कर अपने लेन-देन की प्रक्रिया में तेजी ला सकते हैं।

यह नया सह-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड अक्सर रेल से सफर करने वाले यात्रियों को खुदरा, भोजन और मनोरंजन के साथ-साथ लेन-देन शुल्क में छूट पर विशेष लाभ के साथ रेल यात्रा पर अधिकतम बचत प्रदान करता है।

कार्डधारकों को आईआरसीटीसी की वेबसाइट से एसी प्रथम, एसी द्वितीय, एसी तृतीय, एग्जीक्यूटिव चेयर कार और एसी चेयर कार की बुकिंग करने पर कुल किराए की 10% राशि वापस कर दी जाएगी। इस कार्ड का इस्तेमाल करने पर ऑनलाइन लेन-देन शुल्क माफी (लेन-देन की राशि का 1%), 1% ईंधन अधिभार छूट और एक वर्ष में रेलवे स्टेशनों पर 4 प्रीमियम लाउंज का मुफ्त उपयोग (प्रति तिमाही एक) करने की



प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल इंडिया एवं मेक इन इंडिया विजन के तहत आईआरसीटीसी एवं एसबीआई का सहब्रांडेड रुपे क्रेडिट कार्ड राष्ट्र को समर्पित करते हुए रेल मंत्री एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति

सुविधा मिलेगी। कार्ड के उपयोगकर्ताओं को न्यूनतम खर्च के साथ कार्ड को सक्रिय करने पर 350 बोनस रिवॉर्ड पॉइंट्स प्राप्त होंगे, जिसे वे आईआरसीटीसी की टिकट वेबसाइट से ट्रेन टिकट खरीदते वक्त भुना सकते हैं। रेल यात्रा पर बचत के अलावा, आईआरसीटीसी एसबीआई कार्ड ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल्स के लिए भी कई लाभ प्रदान करता है। ■

रेल मंत्री ने माल ढुलाई में मजबूत साझेदारी हेतु लॉजिस्टिक कंपनियों के संग बैठक की

केन्द्रीय रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने रेलवे से माल ढुलाई और पार्सल सेवाओं में बेहतरीन साझेदारी की सुविधा के लिए देश में कुरियर और लॉजिस्टिक सेवाएं देने वाली शीर्ष कंपनियों के साथ बैठक की।

बैठक में यह जानकारी दी गई कि रेलवे की ओर से लॉजिस्टिक / कुरियर एजेंसियों के लिए विश्वसनीय, तेज, सस्ती और सुलभ पार्सल सेवाओं की पेशकश की जा रही है।

यह बैठक भारतीय रेल के माध्यम से निजी पार्सल सेवाओं के कारोबार के विस्तार की संभावनाओं पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई थी।

इसके लिए सर्वोत्तम दिशा-निर्देश तय करने तथा कारोबारी सुगमता के लिए रेलवे अधिकारियों और लॉजिस्टिक्स / कुरियर प्रदाताओं के प्रतिनिधियों से मिलकर जल्द ही एक संयुक्त कार्यदल का गठन किया जाएगा।

श्री गोयल ने बैठक के अवसर पर कहा कि इसके लिए एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें सभी के लिए सतत व्यापार सुनिश्चित हो सके।

उल्लेखनीय है कि 22 मार्च, 2020 से लेकर 2 सितंबर, 2020 तक भारतीय रेल द्वारा कुल 5,292 पार्सल ट्रेनें चलाई गईं जिनमें से 5,139 रेलगाड़ियां समय सारिणी के आधार पर संचालित



की गईं। इन ट्रेनों के जरिए कुल 3,18,453 टन सामान की ढुलाई की गई जिससे 116.19 करोड़ रुपये की आमदनी हुई।

25 मार्च, 2020 से 01 सितंबर 2020 के बीच भारतीय रेल ने कुल 141049 रेलगाड़ियों के जरिए 451.38 मिलियन टन माल की ढुलाई की। रेल के जरिए माल ढुलाई को आकर्षक बनाने के लिए भारतीय रेल की ओर से कई तरह की रियायतें/ छूट दी जा रही हैं। माल ढुलाई गतिविधियों को संस्थागत रूप देने के लिए आगामी 'जीरो बेस्ड टाइम' टेबल में इन्हें शामिल किया जाएगा। ■

रेल मंत्री द्वारा डीएफसी के कार्यों की समीक्षा

रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने 24 अगस्त, 2020 को डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड (डीएफसीसीआईएल) के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों ने परियोजना की वर्तमान स्थिति की जानकारी दी। उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश के दादरी को मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट (जेएनपीटी) से जोड़ने वाला पश्चिमी गलियारा और साहनेवाल, लुधियाना (पंजाब) से शुरू होकर पश्चिम बंगाल के दानकुनी में समाप्त होने वाला पूर्वी गलियारा, दिसंबर, 2021 तक पूरे हो जाएंगे। श्री गोयल ने कोविड के दौरान लॉकडाउन के कारण समय में हुई क्षति की भरपाई के लिए डीएफएफसीआईएल प्रबंधन टीम को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को सबसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्र की पहचान करने और इसके लिए मिशन मोड में समाधान प्रस्तुत करने की सलाह दी। उन्होंने

- सभी ठेकेदारों के कामों की सख्त निगरानी की जाएगी
- राज्यों के साथ समन्वय समेत सभी मुद्दों के समाधान मिशन मोड में किए जाएंगे
- परियोजना की साप्ताहिक प्रगति की निरंतर निगरानी के लिए नया तंत्र विकसित किया जाएगा



सुझाव दिया कि युवाओं को शामिल करने के कदम को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ताकि सर्वोत्तम समाधान प्राप्त किए जा सकें।

बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया कि सभी ठेकेदारों के काम की सख्त निगरानी की जाए। राज्यों के साथ समन्वय सहित सभी मुद्दों का समाधान मिशन मोड पर किया जाना चाहिए। परियोजना की साप्ताहिक प्रगति की निरंतर निगरानी के लिए नया तंत्र विकसित किया जाएगा।

डीएफसी भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सबसे बड़ी रेल अवसंरचना परियोजनाओं में से एक है। इसकी कुल लागत 81,459 करोड़ रुपये आंकी गई है। ■

भारतीय रेल की अधिसूचित रिक्तियों हेतु 'कंप्यूटर आधारित टेस्ट' 15 दिसंबर से

भारतीय रेल 15 दिसंबर 2020 से अधिसूचित रिक्तियों के लिए कंप्यूटर आधारित टेस्ट लेना शुरू कर देगी। भारतीय रेल ने 3 प्रकार की रिक्तियां अधिसूचित की थीं। इनमें एनटीपीसी के लिए 35,208 रिक्तियां (गैर तकनीकी प्रचलित श्रेणियां, जैसे कि गार्ड, कार्यालय क्लर्क, वाणिज्यिक क्लर्क इत्यादि), 1,663 रिक्तियां पृथक एवं मंत्रिस्तरीय श्रेणियों (स्टेनो इत्यादि) के लिए और 1,03,769 लेवल 1 रिक्तियां (ट्रैक मेंटेनर्स, प्वाइंट्समैन इत्यादि) थीं। सभी आरआरबी ने एनटीपीसी श्रेणियों, लेवल-1 पदों और पृथक एवं विविध श्रेणियों के लिए कुल मिलाकर 1.40 लाख रिक्तियों को अधिसूचित किया था। उपरोक्त रिक्तियों के लिए आरआरबी को 2.40 करोड़ से भी अधिक आवेदन प्राप्त हुए थे। उपर्युक्त रिक्तियों के लिए कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) को कोविड-19 महामारी और इस वजह से पूरे देश में लागू किए गए लॉकडाउन के कारण स्थगित करना पड़ गया था।

आवेदनों की जांच (स्क्रूटनी) पूरी हो गई थी, लेकिन कोविड के मद्देनजर लगाई गई पाबंदियों के कारण परीक्षा से जुड़ी आगे की प्रक्रिया में देरी हो गई थी। रेलवे के आरआरबी सभी अधिसूचित रिक्तियों हेतु 'सीबीटी' आयोजित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और वे महामारी से जुड़ी जमीनी स्थिति का सक्रिय रूप से आकलन करते रहे हैं। अब चूंकि आईआईटी के लिए जेईई और नीट आयोजित करने का अनुभव है, इसलिए ऐसे में यह महसूस किया गया कि रेलवे भी परीक्षा प्रक्रिया शुरू कर सकती है, जिसे कोविड महामारी के कारण रोकना पड़ा था।

इतने बड़े पैमाने पर परीक्षा आयोजित करने के लिए मानक परिचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) तैयार की जा रही हैं। विभिन्न केंद्रीय और राज्य प्राधिकरणों द्वारा निर्दिष्ट किए गए सामाजिक दूरी मानकों और अन्य प्रोटोकॉल का पालन अवश्य किया जाना चाहिए, जो अभ्यर्थियों के हित में आवश्यक है।

रेलवे ने अब 15 दिसंबर, 2020 से प्रथम चरण के कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन टेस्ट शुरू करने का प्रस्ताव किया है और इस संबंध में आवश्यक उपाय शुरू कर दिए गए हैं। ■

रेल मंत्रालय द्वारा पहली बार वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर सेवानिवृत्ति समारोह का आयोजन

रेल मंत्रालय ने अपनी तरह के पहले आयोजन में 31 जुलाई, 2020 को सेवानिवृत्त हुए भारतीय रेल के 2320 अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए एक आभासी (वर्चुअल) सेवानिवृत्ति समारोह का आयोजन किया। यह एक ऐसा विशिष्ट आयोजन था, जिसमें सभी जोन/डिवीजनों/उत्पादन इकाइयों को एक ही प्लेटफॉर्म पर अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ जोड़ा गया था। भारतीय रेल के इतिहास में पहली बार रेल मंत्री ने 31 जुलाई, 2020 को सेवानिवृत्त हुए सभी 2320 अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ संवाद किया। इस समारोह में रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल, रेल राज्य मंत्री श्री सुरेश सी अँगडी, रेलवे बोर्ड के सचिव श्री सुशांत कुमार मिश्रा और रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

इस अवसर पर श्री गोयल ने कहा, ''यह खुशी और गम का दिन है। यह खुशी का अवसर इसलिए है क्योंकि इन पदाधिकारियों ने विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न पदों पर, विभिन्न दायित्वों के निर्वहन के लिए लंबी अवधि तक अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। रेलवे को बेहतर रेलवे बनाने में आपके योगदान और भविष्य के लिए रेलवे को तैयार करने में आपकी भूमिका को सदैव याद रखा जाएगा। पिछले कुछ वर्षों में रेलवे ने अपनी कार्यशैली में उल्लेखनीय सुधार दर्शाया है। मैं कोविड के खिलाफ लड़ाई के दौरान सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने के लिए रेल कर्मचारियों की सराहना करता हूँ।''

श्री गोयल ने कहा कि यह सेवानिवृत्ति वास्तव में किसी की भी जीवन यात्रा में एक मध्यवर्ती या बीच का स्टेशन। इस यात्रा के बाद का आधा हिस्सा दिलचस्प हो सकता है, बशर्ते कि कोई देश के लिए कुछ बेहतर करने का फैसला करता हो और व्यापक परिवर्तन लाने में अग्रणी बन जाता हो। यदि हम अपने जीवन में कुछ समय बचाएं और अपने जीवन में प्राप्त



सेवानिवृत्त हो रहे रेलकर्मियों से संवाद करते हुए रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल एवं रेल राज्य मंत्री श्री सुरेश अँगडी

अपने अनुभवों का उपयोग राष्ट्र की सेवा में करें, तो हमारे देश का भविष्य उज्ज्वल हो सकता है। हम अगली पीढ़ी को बेहतर तरीके से प्रोत्साहित कर सकते हैं और उन्हें विरासत में एक बेहतर देश दे सकते हैं।

श्री सुरेश अँगडी ने सेवानिवृत्त रेलकर्मियों को संबोधित करते हुए कहा, ''रेलवे के साथ-साथ देश भी उन सेवाओं को कभी नहीं भूल सकता जो रेल कर्मचारियों ने अथक रूप से प्रदान की हैं। युवा कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए आपकी सलाह/सुझाव का सदैव स्वागत है। एक रेलकर्मी सदैव एक रेलकर्मी होता है।''

इन अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने रेल मंत्री व रेल राज्य मंत्री के साथ बातचीत की और उनके सेवानिवृत्ति समारोह को एक यादगार सेवानिवृत्ति समारोह बनाने के लिए उनका धन्यवाद किया। उन्होंने यह भी कहा कि वे सदैव 'रेल परिवार' का हिस्सा बने रहेंगे। ■

भारतीय रेल



पत्रिका की

सदस्यता अब ऑनलाइन भी उपलब्ध

www.irctctourism.com/IRBRMag

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें :

011-47845381

सोमवार से शुक्रवार (सुबह 10 से 1 एवं दोपहर 2 से 5 बजे तक)

हुबली का नया रेल संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित

रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, श्री पीयूष गोयल और कोयला, खान और संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने 9 अगस्त, 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुबली में एक रेलवे संग्रहालय को देश को समर्पित किया। इस आयोजन की अध्यक्षता रेल राज्य मंत्री श्री सुरेश अँगडी ने की थी।

उत्तर कर्नाटक में अपनी तरह का पहला तथा मैसूर के ऐतिहासिक मैसूर रेल संग्रहालय के बाद यह रेल संग्रहालय दक्षिण पश्चिम रेलवे में दूसरा है। यह हुबली रेलवे स्टेशन के दूसरे प्रवेश द्वार के पास स्थित है। देश-विदेश के सैलानी इस संग्रहालय को देख सकते हैं।

इस अवसर पर श्री गोयल ने कहा कि रेलवे का हम सभी के साथ एक भावनात्मक जुड़ाव रहा है। रेलवे ने हमारे जीवन में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है और विभिन्न चरणों में हमारे जीवन की निजी यात्रा की गवाह रही है। भाप युग से लेकर आधुनिक बुलेट ट्रेन के इस युग तक रेलवे के विकास की कहानी वास्तव में उल्लेखनीय है। संग्रहालय उस असाधारण परिवर्तन को व्यक्त करता स्मारक है।

इस मौके पर श्री जोशी ने कहा, हुबली ऐतिहासिक रूप से महत्त्वपूर्ण रेल जंक्शन है। यह संग्रहालय यहां का एक और प्रमुख पर्यटन स्थल बन जाएगा।



Twitter : @PIB_India

समारोह को संबोधित करते हुए श्री सुरेश अँगडी ने कहा कि हुबली के लोगों के लिए आज एक बड़ा अवसर है। संग्रहालय का उद्देश्य रेलवे की विभिन्न शाखाओं की गौरवशाली विरासत को संरक्षित और चित्रित करना है। यह रेलवे के सभी क्षेत्रों में उन्नत प्रणालियों के क्रमिक विकास को भी दिखाता है।



संग्रहालय की मुख्य विशेषताएं

- रोलिंग स्टॉक की गैलेक्सी
- मालप्रभा और घाटप्रभा कॉटेज
- थिएटर कोच
- सुरुचि कैफेटेरिया
- टॉय ट्रेन
- मेमोरेबिलिया शॉप
- टिकट प्रिंटिंग मशीन
- मॉडल ट्रेन रन
- बच्चों की गतिविधि का कक्ष

हुबली संग्रहालय में शिल्पकृतियां मोटे तौर पर तीन खंडों - मालप्रभा और घाटप्रभा नाम के दो कॉटेज और बाहरी हिस्से में बंटी हैं

बाहरी परिदृश्य

प्रवेश द्वार पर एक भव्य मेहराब गुजरे युग का स्वागत करता दिखता है। दक्षिण-पश्चिम रेलवे के अग्रदूतों के प्रतीक के रूप में सुशोभित, जिसने इस क्षेत्र की सेवा की - जो दक्षिणी महरत्ता रेलवे, मैसूर और दक्षिणी महरत्ता रेलवे आदि हैं, स्वागत मेहराब रेलवे की जानकारी देने के लिए आगंतुकों का स्वागत करते हैं।

दो संकीर्ण गेज लोकोमोटिव (ट्रेन इंजन) संग्रहालय में प्रमुख आकर्षण हैं। ट्रैक पर चलने वाली चीजें और ट्रैक से संबंधित सभी चीजों, जैसे रोलिंग स्टॉक (इंजन), कोच, वैगन, टैंकर, स्थायी मार्ग सामग्री, जैसे रेल, स्लीपर्स, लेवल क्रॉसिंग गेट, सिग्नल आदि को संग्रहालय में आकर्षक हरियाली के बीच दीर्घाओं में दिखाया गया है।

एक संकीर्ण गेज कोच, जो देश के विभिन्न हिस्सों से यात्रियों के आकार की मूर्तियों के साथ 'विविधता में एकता' को दर्शाता है, आगंतुकों के लिए अतिरिक्त आकर्षण है।

सन् 1907 में निर्मित दो सुंदर कॉटेज को क्षेत्र की दो नदियों, मालप्रभा और घाटप्रभा के नाम पर संग्रहालय के दो हिस्सों में तब्दील किया गया है।



घाटप्रभा कॉटेज

यह कॉटेज पुराने समय का सर्वोत्कृष्ट आकर्षण है। इनडोर कलाकृतियों का हाउस कलेक्शन इसकी शोभा बढ़ाता है। घाटप्रभा कॉटेज में रनिंग ट्रेन के साथ एक मॉडल रूम, सिग्नल उपकरण आदि हैं। लोकोमोटिव्स, वैगनों, कोचों का इतिहास प्राचीन पुस्तकों और पौधों के साथ प्रस्तुत किया गया है। मेडिकल और सुरक्षा मोर्चों पर रेलवे के काम-काज की झलक भी दिखाई गई है। तथ्यों के साथ बच्चों की गतिविधि का रंगीन कक्ष भी घाटप्रभा का हिस्सा है। एक मेमोरेबिलिया काउंटर, जहां से स्मृति चिन्ह खरीदे जा सकते हैं और इतिहास का कोना है, जहां रेलवे कंपनियों का इतिहास कॉटेज में समाहित है।











मालप्रभा कॉटेज

प्रवेश द्वार पर खूबसूरत चारकोल स्केच की एक शृंखला आर्ट गैलरी का निर्माण करती है। टिकट काउंटर के साथ बुकिंग ऑफिस, मुद्रित टिकट, लौह की कैश चेस्ट आदि कुछ दशक पहले के दौर की याद दिलाते हैं। स्टेशन मास्टर का रूम पैनल के साथ सिम्युलेटेड है। सभी उपकरण, रजिस्टर, फर्नीचर यहां तक कि स्टेशन मास्टर और पॉइंट्स मैन की आदमकद मूर्तियाँ भी लगी हैं। बगल के कमरे को एंटीक फर्नीचर के साथ प्रतीक्षालय की थीम पर तैयार किया गया है। एक पार्सल ऑफिस का सेट-अप भी 150 साल पुरानी पार्सल तौल मशीन के साथ बनाया गया है। संग्रहालय में स्थायी रास्ता, रेल, स्लीपर, ट्रैक फिटिंग, टेलिकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल आइटम्स को समय के साथ तकनीक के विकास के क्रम में दिखाया गया है।











थियेटर्स और रेस्तरां कोच के साथ प्लेटफॉर्म - अलंकृत स्तंभों के साथ शानदार प्लेटफॉर्म रेस्तरां कार और थिएटर कार तक पहुंच प्रदान करता है। कोच थिएटर में निश्चित समय पर मनोरंजक और शिक्षाप्रद लघु फिल्में और वीडियो दिखाए जाने की योजना है।

टॉय ट्रेन में सवारी - स्टीम इंजन वाली रंगीन गाड़ियां बच्चों और बड़ों को समान रूप से लुभाती हैं। टॉय ट्रेन को हुबली वर्कशॉप में तैयार किया गया है। साउंड और स्टीम इफेक्ट से लैस इस टॉय ट्रेन से एक छोटी-सी यात्रा आगंतुकों को पुराने युग में ले जाएगी और बच्चों के लिए रोमांचक अनुभव होगा।

सुरुचि कैफेटेरिया - आगंतुकों को स्वाद देने के लिए सुरुचि कैफेटेरिया संग्रहालय में प्राचीन स्तंभों के साथ खूबसूरत तरीके से डिजाइन किया गया है। यह विभिन्न व्यंजनों का मेनू प्रदान करता है।

इस संग्रहालय की अनूठी विशेषता यह है कि सामग्री और मैन पॉवर जुटाकर उपलब्ध संसाधनों के साथ ही सब कुछ किया जा रहा है।





सावधानियाँ

कोविड महामारी के मद्देनजर बरती जाने वाली सावधानियों के मद्देनजर संग्रहालय में आगंतुकों के लिए प्रवेश एक समय में केवल 30 सदस्यों तक सीमित है। आगंतुकों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपने हाथों को बार-बार सैनिटाइजर डिस्पेंसर से सैनिटाइज करते रहें। फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा और संग्रहालय आते समय सामाजिक दूरी बनाए रखनी होगी। थियेटर कोच पूरी तरह से बंद रहेगा जब तक कि लॉकडाउन न खुल जाए और सामान्य स्थिति न हो। ■

संग्रहालय देखने का समय

सामान्य दिन (मंगलवार से शुक्रवार)	दोपहर 12:00 से शाम 7:00 बजे तक
सप्ताहांत और सार्वजनिक अवकाश	दोपहर 12:00 बजे से रात 8:00 बजे तक
हर सोमवार अवकाश है	

प्रवेश टिकट शुल्क

वयस्क (12 साल से अधिक)	20 रुपये
बच्चे (5-12 साल)	10 रुपये
5 साल से कम	नि:शुल्क

थिएटर कोच

शो टाइमिंग्स	(12:00 बजे दोपहर से हर घंटे 1:00 बजे, 2:00 बजे, 3:00 बजे, 4:00 बजे, 5:00 बजे)
शो टाइम	15 मिनट
10 सदस्यों के समूह में प्रत्येक टिकट 10 रुपये	निशुल्क

टॉय ट्रेन टिकट (एक ट्रिप)

टाइमिंग्स	(12:00 बजे दोपहर से हर घंटे 1:00 बजे, 2:00 बजे, 3:00 बजे, 4:00 बजे, 5:00 बजे)
प्रत्येक टिकट 10 रुपये	
तीन बार आना-जाना एक ट्रिप होता है।	

रेल मंत्री का उद्योगपतियों को भारतीय रेल की परिवर्तन की यात्रा में साथ आने का आमंत्रण

भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने 8 सितंबर, 2020 को वर्चुअल मंच पर रेल कनेक्ट का दूसरा संस्करण आयोजित किया। इस सम्मेलन में भारतीय रेल की भावी योजनाओं, स्वदेशी विनिर्माण और भारत में रेलवे उद्योग के लिए व्यापार करने में आसानी पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसमें सार्वजनिक निजी साझेदारी, प्रौद्योगिकी, शहरी गतिशीलता, स्टेशन का विकास, लोकोमोटिव आधुनिकीकरण, रेल माल भाड़ा, संचार प्रौद्योगिकी और रेलवे प्रणाली की सुरक्षा, स्वास्थ्य, वहनीयता मानकों आदि को कवर करते हुए रेल परिवहन में निजी उद्योग के लिए उभरते अवसरों को लेकर विचार-विमर्श किया गया। इस आयोजन में रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष श्री विनोद कुमार यादव, सीआईआई के महानिदेशक श्री चंद्रजीत बैनर्जी और उद्योगपतियों ने शिरकत की।

इस कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा, "भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारतीय रेल का उल्लेख देश के विकास के इंजन के रूप में उचित ही किया जाता है। उनकी दृष्टि भारतीय रेल को एक ऐसी मजबूत इकाई बनाने की है, जो रेलवे से जुड़ी रूमानियत को बरकरार रखते हुए आधुनिक तकनीक और अच्छी सेवा वाला अनुभव ग्राहकों को प्रदान करे। रेलवे का एक कायापलट हुआ है।

कोविड चरण के दौरान भारतीय रेल ने अवसर का उपयोग बाधाओं को दूर करने, रख-रखाव करने, श्रमिक गाड़ियों को चलाने, माल ढुलाई की हिस्सेदारी वापस लाने, प्रक्रियाओं को मजबूत करने, नीतिगत बदलाव करने, निजी क्षेत्र, प्रौद्योगिकी प्रदाताओं के साथ जुड़ने और बुनियादी ढांचे में सुधार करने में किया है।"

रेल मंत्री ने कहा कि भारतीय रेल नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने उद्योग जगत् के शीर्ष नेतृत्व से भारतीय रेल का साझेदार बनने और सहयोग करने का आग्रह किया ताकि लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में लागत प्रभावी समाधान प्रदान किए जा सकें और लॉजिस्टिक लागतों को कम किया जा सके। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि आत्मनिर्भर रेलवे दरअसल रेलवे और उद्योग, दोनों की भागीदारी पर निर्भर करती है।

रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष श्री यादव ने अपने संबोधन में आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और हरित रेलवे की दिशा में भारतीय रेल द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के बारे में बात की। उन्होंने भारतीय रेल के परिवर्तन की योजना की रूपरेखा प्रस्तुत की और कहा कि भारतीय रेल भारतीय उद्योगों के साथ सहयोग और साझेदारी के लिए तैयार है।

इस सम्मेलन के दौरान विभिन्न उद्योगपतियों ने लॉकडाउन की अवधि के दौरान रेलवे द्वारा निभाई गई महत्त्वपूर्ण भूमिका और रेलवे में साफ दिख रहे परिवर्तनों की सराहना की। ■

दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में रेल के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाती भारतीय रेल

रेलवे के बुनियादी ढांचे को बेहतर करने और शहरों में भीड़भाड़ को कम करने हेतु उत्तर रेलवे ने मौजूदा रोहतक-गोहाना रेलवे लाइन को 4.8 किमी लंबे एलिवेटेड ट्रैक में बदल दिया है। उस लाइन पर काम लगभग पूरा हो चुका है और अगले तीन महीनों में उसे चालू कर दिया जाएगा।

रोहतक-गोहाना रेलवे लाइन शहर के बिल्कुल मध्य से गुजरती है। शहर की सीमा के भीतर इस लाइन पर चार स्तरीय क्रॉसिंग भी है। इससे शहर में यातायात के लिए काफी भीड़-भाड़ हो जाती है क्योंकि लेवल क्रॉसिंग गेट अक्सर बंद रहते हैं। इससे रेल यातायात की गति भी प्रभावित होती थी। सुरक्षा संबंधी खतरे एवं गाड़ियों की गति के प्रभावित होने के अलावा इससे सड़क पर आने-जाने वालों को भी



काफी असुविधा हो रही थी। अब ट्रैक को ऊंचा कर दिया गया है, जिससे लेवल क्रॉसिंग खत्म हो गई है। यह रोहतक के लोगों के लिए एक बड़ी राहत होगी। इस लाइन के चालू होने से रेलवे को भी इस मार्ग पर ट्रेनों का निर्बाध परिचालन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। साथ ही, इस सेक्शन में ट्रेनों की गति भी बढ़ाई जाएगी। भारतीय रेल और हरियाणा सरकार ने साथ मिलकर इस परियोजना पर काम किया है। इस पर कुल मिलाकर 315 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं, जिसमें राज्य का योगदान 225 करोड़ रुपये है। इसके साथ ही रोहतक के लोगों की एक लंबी मांग को रेलवे द्वारा पूरा कर दिया गया है। ■

लेफ्टिनेंट गवर्नर, जम्मू एवं कश्मीर ने उधमपुर-श्रीनगर-बारामुला रेल परियोजना की समीक्षा की

दिनांक 22 अगस्त, 2020 को श्री मनोज सिन्हा, लेफ्टिनेंट गवर्नर, जम्मू एवं कश्मीर ने अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड, श्री विनोद कुमार यादव तथा अन्य रेल अधिकारियों के साथ एक बैठक की।

इस बैठक में उधमपुर-श्रीनगर-बारामुला रेल लिंक राष्ट्रीय परियोजना को समय से पूरा करने के लिए पुनरावलोकन किया गया। इस परियोजना को रेल मंत्रालय एवं जम्मू एवं कश्मीर सरकार के आपसी समन्वयन से समय से पूरा किया जाएगा।

कोरोना के दौरान उत्पन्न हुई बाधाओं और चुनौतियों के बावजूद फिरोजपुर मंडल जम्मू एवं कश्मीर में उधमपुर-श्रीनगर-बारामुला रेल लिंक राष्ट्रीय परियोजना सहित अन्य सभी रेल परियोजनाओं को समय से पूरा करने पर जोर दे रहा है। अनेक चुनौतियों के बावजूद चिनाब पुल का कार्य वर्ष 2021 में पूरा कर लिए जाने की संभावना है। उधमपुर-श्रीनगर-बारामुला रेल



लिंक परियोजना का समस्त कार्य दिसंबर 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा। इस परियोजना के अंतर्गत कटड़ा और बनिहाल के बीच बनाई जा रही रेल लाइन का कार्य सबसे कठिन है, क्योंकि यह रेल लाइन हिमालय के दुर्गम क्षेत्रों से होकर गुजरती है। ■

रेल मंत्री द्वारा राजस्व बढ़ाने तथा कर्मचारी सुरक्षा में वृद्धि के उपाय सुझाने का आह्वान

रेल मंत्रालय द्वारा पहली बार ऑनलाइन श्रमिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें देशभर से रेलवे श्रमिक संघों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस संगोष्ठी में रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, श्री पीयूष गोयल, रेल राज्य मंत्री, श्री सुरेश अँगडी, अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड, श्री विनोद कुमार यादव और रेलवे बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

संगोष्ठी के दौरान दोनों महासंघों के पदाधिकारियों - एआईआरएफ व एनएफआईआर, श्री रखल दास गुप्ता, श्री गुमान सिंह, श्री शिव गोपाल मिश्र, डॉ. एम राघवय्या और महासंघ के अन्य पदाधिकारियों द्वारा अपने-अपने विचार प्रस्तुत किए गए।

संगोष्ठी को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा, "उच्चतम स्तर से लेकर निम्नतम स्तर के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने लॉकडाउन अवधि के दौरान अपने कर्तव्यों का ईमानदारीपूर्वक निर्वहन किया है। वर्तमान में, महामारी के कारण भारतीय रेल विकट समय से गुजर रही है।" उन्होंने रेलवे महासंघों से यह भी कहा कि वे अपने साथ अनूठे विचार लेकर आएं कि रेलवे के राजस्व में कैसे बढ़ोत्तरी की जा सकती है, लागत में कैसे कमी लाई जा सकती है, माल ढुलाई में कैसे वृद्धि की जा सकती है और कैसे रेलवे को तेजी से आगे बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने सभी लोगों से मौजूदा कर्मचारियों की सुरक्षा और कल्याण के संदर्भ में भी सोचने के लिए कहा। उन्होंने इस चरण के दौरान रेलवे अधिकारियों, यूनियनों और कर्मचारियों द्वारा सामूहिक प्रयास की आवश्यकता पर बल दिया।

एक अनूठे कदम के रूप में मंत्री ने रेल कर्मचारियों से लाभदायिकता बढ़ाने और परिवर्तनों के लिए विचारों की क्राउड सोर्सिंग प्रदान करने की मांग की। रेलवे कर्मचारियों का दिल संगठन के लिए धड़कता है। उनके पास ऐसे विचार होंगे जो



रेलवे की लाभदायिकता को बढ़ावा दे सकते हैं। मंत्री ने महाप्रबंधकों और मंडल रेल प्रबंधकों को निर्देश दिया कि वे कर्मचारियों द्वारा सक्रिय रूप से इन विचारों को एकत्रित करें और इसे मंत्रालय तक पहुंचाएं।

रेल राज्य मंत्री, सुरेश अँगडी ने संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि महामारी के दौरान सभी रेलकर्मियों ने अथक परिश्रम किया है। उन्होंने भारतीय रेल के कर्मचारियों को योद्धा की तरह काम करने के लिए बधाई दी।

रेलवे यूनियनों के पदाधिकारियों ने कहा कि रेलवे के विकास वाले अभियान में रेलवे कर्मचारी मंत्रालय के साथ खड़े थे। कार्यकुशलता और वित्तीय स्वास्थ्य में सुधार न केवल कर्मचारियों के हित में है बल्कि राष्ट्र हित में भी है। उन्होंने कहा कि रेलवे कर्मचारी इसके लिए किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी उठाने में सक्षम हैं। ■

कर्नाटक के मुख्यमंत्री और रेल राज्यमंत्री ने नेलमंगला से बाले तक पहली रो-रो सेवा को हरी झंडी दिखाई



कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री बी. एस. येदियुरप्पा और रेल राज्यमंत्री श्री सुरेश अँगडी ने दक्षिण पश्चिम रेलवे के नेलमंगला (बेंगलुरु के पास) से बाले (सोलापुर के पास) तक पहली बार रोल ऑन रोल ऑफ (आरओआरओ यानी रो-रो) सेवा को हरी झंडी दिखाई।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री बी. एस. येदियुरप्पा ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदीजी मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी पर जोर दे रहे हैं। क्षेत्र में एपीएमसी बाजारों की वजह से रो-रो सेवा के लिए अपार संभावनाएं हैं।

इस अवसर पर श्री अँगडी ने कहा कि मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का सपना है। बेंगलुरु और सोलापुर के बीच हजारों ट्रक आते-जाते रहते हैं। रो-रो सेवा के साथ यात्रा का समय केवल 17 घंटे होगा। उन्होंने कहा कि रो-रो सेवा से इस क्षेत्र का तेजी से विकास होगा।

रोल ऑन रोल ऑफ

रोल ऑन रोल ऑफ (रो-रो) विभिन्न वस्तुओं से भरे सड़क वाहनों को खुले समतल रेलवे वैगनों पर ले जाने की एक अवधारणा है।

रो-रो सेवाएं इस मायने में सड़क और रेल परिवहन की सर्वोत्तम विशेषताओं का संयोजन हैं कि वे बड़े और प्रत्यक्ष रेल लिंक द्वारा न्यूनतम हैंडलिंग के साथ घर-घर सेवाएं प्रदान करती हैं। बढ़ते ट्रैफिक की वजह से सड़कों पर भीड़ बढ़ती जा रही है और यात्री वाहनों को आने-जाने में देरी हो रही है। इसके अलावा, अंतरराज्यीय चेक पोस्ट पर विभिन्न दस्तावेजों के निरीक्षण आदि के कारण यात्रा का समय बढ़ जाता है।

दूसरी ओर, रेलवे मध्यम से लेकर बड़ी मात्रा में माल ढुलाई के लिए बाधा रहित और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन सेवा प्रदान करती है। परिवहन के सभी साधनों की तुलना में रेल परिवहन में सबसे कम ईंधन खर्च लगता है और यह सड़क की तुलना में अधिक सुरक्षित भी है।

रो-रो के लाभ

भारतीय रेल में रो-रो ट्रेन सेवाओं को पहली बार वर्ष 1999 में कोंकण रेलवे में शुरू किया गया था और तब से यह सफलतापूर्वक चल रही हैं।

रोल-ऑन-रोल-ऑफ यानी रो-रो सेवा निम्नलिखित फायदे के साथ एक मल्टीमॉडल डिलीवरी मॉडल है -

- माल और आवश्यक वस्तुएं लाने- ले जाने की तेज गतिविधि। शहरों के बीच सड़कों पर जाम की वजह से ट्रकों के गंतव्य तक पहुंचने में लगने वाले समय को कम करता है।
- कीमती ईंधन बचाता है।
- कार्बन उत्सर्जन को कम करता है।
- ट्रक के चालक दल के लिए राहत क्योंकि यह लंबी दूरी की ड्राइविंग से बचाता है।
- चेक पोस्ट/टॉल गेट आदि का कोई झंझट नहीं।
- मौजूदा ट्रैक पर रोडवेज और रेलवे-इंटर-मोडल परिवहन के बीच निर्बाध अंतर-संचालन।
- आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना।
- लोडिंग/अनलोडिंग के लिए 3 घंटे का नि:शुल्क समय है।



- 'लोकल फॉर वोकल' यानी स्थानीय के लिए मुखर अभियान को रो-रो सेवा से बल मिलेगा।
- ट्रकों के माध्यम से छोटे / विकेंद्रीकृत लोडिंग को प्रोत्साहित करके स्थानीय एमएसएमई इकाइयों को बढ़ावा मिलेगा।
- रो-रो टीओपी (टमाटर, प्याज, आलू) की कीमतें स्थिर रखने में सरकार की 'ऑपरेशन ग्रीन' जैसी पहल को मदद करेगा
- कृषि उत्पादन क्षेत्रों और कृषि उपभोग केंद्रों को जोड़ने में मदद प्रदान करेगा।
- यह सुनिश्चित करता है कि किसानों को उनकी उपज के लिए सही बाजार और सही मूल्य मिले।
- वस्तुओं की कमी वाले और अधिकता वाले बाजारों को आपस में जोड़ता है और दोनों में संतुलन बनाए रखता है।

लॉकडाउन के दौरान रो-रो फेरी मॉडल कई ट्रांसपोर्टर्स के काम आया।

मेसर्स जितेंद्र रियल्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने सोलापुर और बेंगलुरु के बीच रो-रो ट्रेन सेवाओं की व्यावसायिक व्यवहार्यता का पता लगाया। दक्षिण मध्य और दक्षिण पश्चिम रेलवे द्वारा अनुशंसित और मध्य रेल द्वारा सौंपी गई व्यवहार्यता रिपोर्ट के आधार पर, रेलवे बोर्ड ने अप्रैल, 2020 में 2 वाणिज्यिक शहरों नेलमंगला (बेंगलुरु के पास) और बाले (सोलापुर के पास) के बीच रो-रो सेवा को मंजूरी दे दी है।

कृषि उपजों से संपन्न बेंगलुरु और सोलापुर तेजी से उभरते व्यापारिक शहर हैं। इन दोनों शहरों के बीच सड़क पर बड़ी संख्या में वस्तुओं से लदे वाहन आते-जाते रहते हैं।

गहन अध्ययन के बाद इन दो शहरों के बीच रो-रो रेल सेवाओं के लिए मार्ग तय किए गए हैं जो 4 राज्यों - कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र से होकर गुजरते हैं।

बेंगलुरु-सोलापुर खंड पर रो-रो रेल सेवाएं भारतीय रेल में केवल निजी तौर पर संचालित रो-रो ट्रेन सेवाएं होंगी जो न केवल सोलापुर और बेंगलुरु के दो प्रमुख बाजारों को मदद पहुंचाएंगी बल्कि इस मार्ग पर यात्रा करने वाली जनता को एक बड़ी राहत देते हुए व्यस्त राजमार्ग पर भीड़-भाड़ को भी कम करेंगी।

बेंगलुरु से आने वाली प्रमुख वस्तुओं में मसाले, मेवे, (ड्राई फ्रूट्स),कच्चे नारियल, कॉफी, नट्स इत्यादि हैं, जबकि सोलापुर से प्याज, दालें, फल इत्यादि जैसे कृषि उत्पादों के लोड किए जाने की संभावना है। फरवरी, 2020 के बाद यह देखा गया है कि कृषि उत्पादों के परिवहन को बहुत महत्त्व दिया गया है। ■

रेल राज्यमंत्री ने उत्तर रेलवे के मालभाड़ा लदान की समीक्षा की

दिनांक 9 सितम्बर, 2020 को, रेल राज्यमंत्री, श्री सुरेश अँगडी ने उत्तर एवं उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक श्री राजीव चौधरी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उत्तर रेलवे के मालभाड़ा लदान की समीक्षा की।

महाप्रबंधक श्री चौधरी ने मंत्री को अवगत कराया कि माल ढुलाई में सुधार के लिए मौजूदा और संभावित ग्राहकों के साथ निरंतर संवाद के माध्यम से नए ट्रैफिक स्ट्रीम प्राप्त करने में उत्तर रेलवे द्वारा गठित बिजनेस डेवलपमेंट यूनिटों के सक्रिय दृष्टिकोण की जानकारी दी। लंबे समय के बाद, उत्तर रेलवे द्वारा लगातार संवाद की स्थिति बनाते हुए चीनी का लदान किया गया है। श्री चौधरी ने बताया कि उत्तर रेलवे ने अगस्त, 2020 के दौरान खाद्यान्न लदान में लगातार 5 नए रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। उत्तर रेलवे ने 29 अगस्त, 2020 को 59 रैकों का लदान करके सर्वश्रेष्ठ एकल दिवसीय लदान हासिल किया है। इससे पहले 24 जुलाई, 2020 को 55, 22 अप्रैल, 2020 को 54, 17 अप्रैल, 2020 को 53 और 9 अप्रैल, 2020 को क्रमशः 51 रैकों का लदान कर रिकॉर्ड बनाए थे। उन्होंने आगे बताया कि उत्तर रेलवे ने अगस्त 2020 के दौरान 6 मीट्रिक टन का सर्वश्रेष्ठ मूल लदान दर्ज किया। यह पिछले वर्ष के लदान से 43.12% और अप्रैल से अगस्त की अवधि के दौरान किए गए सर्वश्रेष्ठ मूल लदान 25.43 मीट्रिक टन से 29.41% अधिक है। उन्होंने यह भी कहा कि उत्तर रेलवे द्वारा 5 हजार टन क्षमता वाली 400वीं लाँग लीड-लाँग हॉल अन्नपूर्णा रेलगाड़ी भी चलाई गई।

महाप्रबंधक ने बताया कि उत्तर रेलवे ने दिनांक 17 अगस्त, 2020 को एक ही दिन में 31.88 करोड़ रुपये की सर्वश्रेष्ठ मूल आय दर्ज की। यह सभी क्षेत्रीय रेलों में सर्वाधिक है। उत्तर रेलवे ने अपने नेटवर्क पर अधिक मालभाड़ा यातायात का लदान किया है। हमने मालभाड़ा यातायात के उच्च परिमाण का लदान करके आय में हिस्सेदारी और ले जाये गए एनटीकेएम में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। उत्तर रेलवे पर अप्रैल, 2020 से वहन किए गए एनटीकेएम की संख्या में लगभग 105.14% की वृद्धि दर्ज की गयी है। वर्तमान में, भारतीय रेल पर वहन किए गए कुल एनटीकेएम में उत्तर रेलवे की हिस्सेदारी 9.32% है। उन्होंने कहा कि मुख्यालय एवं मंडल स्तरों पर बिजनेस डेवलपमेंट यूनिटों के गठन के अब सकारात्मक परिणाम आने लगे हैं।

श्री अंगडी ने माल ढुलाई, मालगाड़ियों की औसत गति बढ़ाने और नए तरह के माल यातायात को लाने की दिशा में किए गए प्रयासों के लिए उत्तर रेलवे के अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि पीपीपी मोड के तहत माल शेड का विकास रोजगार सृजन को भी बढ़ावा देगा और निर्देश दिया कि हमें अपने प्रस्तावों को अधिक ग्राहक उन्मुख बनाने का प्रयास करना चाहिए। श्री अंगडी ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा आत्मनिर्भर भारत के आह्वान को सफल बनाने हेतु रेलवे अथक प्रयास कर रही है। ■

मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश द्वारा रोबोटिक ट्रॉली का उद्घाटन



मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ ने 26 जुलाई, 2020 को ललित नारायण मिश्र रेलवे चिकित्सालय, गोरखपुर का निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने चिकित्सालय में कोरोना मरीजों के इलाज में बहुपयोगी कॉन्टेक्ट लेस, रिमोट संचालित रोबोटिक ट्रॉली का उद्घाटन किया। ज्ञातव्य है कि यांत्रिक कारखाने, गोरखपुर द्वारा कोरोना मरीजों के इलाज में बहुपयोगी यह रोबोटिक ट्रॉली (केयर बॉट) आंतरिक संसाधनों द्वारा विकसित की गई है। इसका उपयोग कोरोना मरीजों को दूर से दवा एवं भोजन आदि देने के लिए किया जाएगा, जिससे कोरोना मरीजों एवं चिकित्सा कर्मियों के बीच निकट से कोई आदान-प्रदान नहीं होगा तथा सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहेगी। इसके उपयोग से पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट (पी.पी.ई.) के खपत में भी कमी आएगी। यह ट्रॉली कोरोना मरीजों को एक बार में ही दवा एवं खाने का सामान तेजी से तथा स्वच्छता के साथ कुशलतापूर्वक देने में सक्षम है। इस ट्रॉली में लगे उपकरण (थर्मल स्कैनर) से मरीजों का बुखार भी दूर से ही नापा जा सकता है। इस ट्रॉली में 360 डिग्री एच.डी. विजन ऐप आधारित क्लाउड कैमरा लगा हुआ है। कैमरे के माध्यम से डॉक्टर मरीजों से वीडियो कॉलिंग के माध्यम से वर्चुअल बातचीत कर सकते हैं। 25 मीटर रेंज वाली यह रोबोटिक ट्रॉली एक बार पूरी तरह चार्ज होने पर 120 मिनट तक लगातार कार्य कर सकती है। यह 50 किग्रा वजन उठाने में सक्षम है। इस अवसर पर पूर्वोत्तर रेलवे के अपर महाप्रबन्धक श्री अमित कुमार अग्रवाल, प्रमुख मुख्य चिकित्सा निदेशक डॉ. एन.के. यादव एवं वरिष्ठ रेल अधिकारी एवं चिकित्सक उपस्थित थे। ■

दिसंबर 2022 तक सभी डिब्बों में आरएफआईडी टैग लगाने की योजना

भारतीय रेल ने दिसंबर 2022 तक अपने सभी डिब्बों में रेडियो-फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग (आरएफआईडी) लगाने की योजना बनाई है। इस टैग के जरिए रेल डिब्बे जहां कहीं भी हों, उनका पता लगाया जा सकता है।

अब तक 23,000 रेल डिब्बों में आरएफआईडी टैग लगाए जा चुके हैं। यह काम अभी भी जारी है। वर्तमान में भारतीय रेल अपने सभी रेल डिब्बों की जानकारी लिखित रूप में रखती है जिसमें त्रुटियों की काफी गुंजाइश बनी रहती है। ऐसे में रेलवे के लिए आरएफआईडी टैग से अपने सभी डिब्बों और इंजनों की सही स्थिति जानना आसान हो जाएगा।

डिब्बे जहां बनकर तैयार होते हैं वहीं उन पर आरएफआईडी टैग लगा दिए जाएंगे जबकि इन टैग को पढ़ने वाले उपकरण रेलवे स्टेशनों और रेल पटरियों के पास प्रमुख स्थानों पर लगाए जाएंगे, जो डिब्बों पर लगे टैग को दो मीटर की दूरी से ही पढ़ लेंगे और डिब्बे की पहचान कर उससे संबंधित आंकड़ों को केन्द्रीय कंप्यूटरीकृत प्रणाली तक पहुंचा देंगे। इससे प्रत्येक डिब्बे की पहचान की जा सकेगी।

आरएफआईडी टैग प्रणाली शुरू हो जाने से माल डिब्बों, यात्री डिब्बों और इंजनों की कमी की समस्या को तेजी के साथ अधिक पारदर्शी तरीके से सुलझाने में मदद मिल सकेगी। ■



'गरीब कल्याण रोजगार अभियान' के तहत प्रवासी मजदूरों को रोजगार प्रदान करती भारतीय रेल

भारतीय रेल ने 'गरीब कल्याण रोजगार अभियान' के तहत 4 सितंबर, 2020 तक प्रवासी श्रमिकों के लिए बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में कुल 8,09,046 कार्यदिवस सृजित किए हैं।

रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल इस परियोजना के तहत इन राज्यों में प्रवासी मजदूरों के लिए काम के अवसरों में हुई प्रगति की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। इन राज्यों में लगभग 164 रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का निष्पादन किया जा रहा है।

इस अभियान में 4 सितंबर, 2020 तक करीब 12,276 श्रमिकों को जोड़ा जा चुका है और इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए ठेकेदारों को 1,631.80 करोड़ रुपये का भुगतान जारी किया गया है।

रेलवे ने प्रत्येक जिले के साथ ही राज्यों में भी नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं ताकि राज्य सरकारों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित किया जा सके।

परियोजना के तहत रेलवे की ओर से कई तरह के कार्यों का निष्पादन किया जा रहा है, जिसमें (i) लेवल क्रॉसिंग तक के लिए सड़कों का निर्माण और रखरखाव (ii) रेल पटरियों के किनारे बने नालों, खाइयों और सिल्टेज जलमार्गों की साफ सफाई और उन्हें बेहतर बनाया जाना (iii) रेलवे स्टेशनों तक पहुंचने के लिए सड़कों का निर्माण और उनका रखरखाव (iv) रेल पटरियों के किनारे के जमीनी हिस्सों की मरम्मत, कटिंग और उन्हें चौड़ा किया जाना (v) रेलवे की भूमि के आखिरी छोर में वृक्षारोपण करना और (vi) रेल पटरियों के किनारे के मौजूदा जमीनी हिस्सों की मरम्मत, कटिंग और पुलों से संबंधित संरक्षण कार्य शामिल हैं।





उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कोविड के विनाशकारी प्रभाव को झेलने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए 'गरीब कल्याण रोजगार अभियान' शुरू किए जाने की घोषणा 20 जून, 2020 को की थी। इस अभियान के तहत ऐसे प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर बनाए गए हैं जो कोविड के कारण पैदा हुई विषम परिस्थितियों की वजह से अपने गांव और राज्यों को लौट गए थे। प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि 'गरीब कल्याण रोजगार अभियान' के तहत टिकाऊ ग्रामीण बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए 50,000 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाएगी।

कुल 125 दिनों का यह अभियान 'मिशन मोड' में चलाया जा रहा है। इसके तहत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और ओडिशा के ऐसे 116 जिलों में 25 विभिन्न प्रकार के कार्य और निर्माण गतिविधियां शामिल की गई हैं जहां बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने घरों को लौटे हैं। इन जिलों में चलाए जा रहे सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिए 50 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

यह अभियान 12 विभिन्न मंत्रालयों / विभागों का एक समन्वित प्रयास है जिसमें ग्रामीण विकास, पंचायती राज, सड़क परिवहन और राजमार्ग, खनन, पेयजल और स्वच्छता, पर्यावरण, रेलवे, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, सीमा सड़क संगठन, दूरसंचार और कृषि मंत्रालय सहयोग कर रहे हैं। इस अभियान के तहत 25 तरह के सार्वजनिक निर्माण कार्यों और आजीविका के अवसरों से जुड़े कार्यों को तेजी से पूरा करने का काम किया जा रहा है। ■

भारतीय रेल को 2030 तक 'हरित रेलवे' बनाने का लक्ष्य



विद्युतीकरण का एक दृश्य

रेल मंत्रालय ने 2030 तक भारतीय रेल को पूरी तरह हरित ऊर्जा से संचालित करने का लक्ष्य निर्धारित करने के साथ, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन से निपटने की दिशा में कई बड़ी पहलें की हैं। रेलवे विद्युतीकरण, लोकोमोटिव और ट्रेनों की ऊर्जा दक्षता में सुधार के साथ स्थाई उपकरणों और प्रतिष्ठानों/स्टेशनों के लिए हरित प्रमाणन हासिल करने, डिब्बों में जैव शौचालय बनाए जाने तथा अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए नवीकरणीय स्रोतों पर निर्भरता तथा शून्य कार्बन उत्सर्जन को प्राप्त करना इस रणनीति का हिस्सा है।

भारतीय रेल ने 40,000 से अधिक (आरकेएम) (व्यस्त मार्गों में से 63%) का विद्युतीकरण पूरा कर लिया है, जिसमें 2014-20 के दौरान 18,605 किमी मार्ग का विद्युतीकरण कार्य किया गया है। इससे पहले 2009-14 की अवधि के दौरान केवल 3,835 किमी मार्ग का विद्युतीकरण पूरा हुआ था। भारतीय रेल ने वर्ष 2020-21 के लिए 7,000 किमी मार्ग के विद्युतीकरण का लक्ष्य तय किया है। व्यस्त नेटवर्क के सभी मार्गों के दिसंबर 2023 तक विद्युतीकरण करने की योजना बनाई गई है। भारतीय रेल आखिरी मील संपर्क और परस्पर न जुड़ पाए मार्गों के विद्युतीकरण पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इसे ध्यान में रखते हुए कोविड अवधि के दौरान 365 किमी प्रमुख मार्गों का काम पूरा किया गया।

कोविड की अवधि में मुंबई-हावड़ा के कटनी-सतना खंड (99 आरकेएम) को इलाहाबाद के माध्यम से हावड़ा के लिए वैकल्पिक मार्ग प्रदान किया गया है। इसी तरह इंदौर-गुना-बीना मार्ग पर पचोर-मक्सी (88 आरकेएम) खंड पर मक्सी-भोपाल-बीना के लिए एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान किया गया है। हावड़ा/सियालदह-एसवीडी कटरा पर पटना मार्ग के माध्यम से भागलपुर-शिवनारायणपुर (45 आरकेएम) अनुभाग चालू किया गया है। करियाकल बंदरगाह को तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कोयले, उर्वरक और इस्पात संयंत्रों से जोड़ने वाले मार्ग पर, तिरुवरूर-कराइकल (46 आरकेएम) खंड को इरोड, कोयम्बटूर और पालघाट के लिए बंदरगाह से जोड़ने की संपर्क लाइन बनाई गई है।



भारतीय रेल ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भी कई पहल की है। यह रूफ टॉप सोलर पैनल (डेवलपर मॉडल) के माध्यम से 500 मेगावॉट (एमडब्ल्यू) ऊर्जा क्षमता का दोहन करने के लिए काम कर रहा है। अब तक, 900 स्टेशनों सहित विभिन्न इमारतों की छतों पर 100 मेगावॉट क्षमता वाले सौर संयंत्र लगाए गए हैं। 400 मेगावॉट की संयुक्त क्षमता वाले सौर संयंत्र निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं। इनमें से 245 मेगावॉट क्षमता वाले सौर संयंत्रों के लिए निविदाएं जारी कर दी गई हैं। दिसंबर 2022 तक इन संयंत्रों को पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है।

इसके अलावा, भारतीय रेल अपनी जमीन पर भी सौर संयंत्र लगाने की कोशिश में है। भारतीय रेल के पास 20 गीगावॉट क्षमता वाले सौर संयंत्र स्थापित करने के लिए 51,000 हेक्टेयर भूमि है। इन संयंत्रों से उत्पन्न होने वाली बिजली की केंद्र/राज्यों के ग्रिडों या सीधे 25 केवी एसी कर्षण प्रणाली को आपूर्ति की जाएगी। रेलवे एनर्जी मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड भारतीय रेल की एक संयुक्त उपक्रम कंपनी है जिसमें रेलवे की (49%) और राइट्स लिमिटेड की (51%) हिस्सेदारी है। इस कंपनी को रेलवे की जमीन पर लगाए जाने वाले सौर संयंत्रों का काम देखने की जिम्मेदारी दी गई है।

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) के सहयोग से बीना (मध्य प्रदेश) में 1.7 मेगावॉट की ऐसी एक परियोजना पहले ही स्थापित की जा चुकी है और वर्तमान में व्यापक परीक्षण की प्रक्रिया में है। यह दुनिया में अपनी तरह की पहली सौर परियोजना है।

शुरुआती स्तर पर भूमि आधारित सौर परियोजनाओं के लिए, भारतीय रेल ने तीन चरणों में 3 गीगावॉट क्षमता वाली सौर परियोजना शुरू की है। पहले चरण में ओपन एक्सेस राज्यों के लिए रेलवे भूखंडों में 1.6 गीगावॉट क्षमता के लिए 29 अप्रैल 2020 को डेवलपर मॉडल के तहत् निविदा जारी की गई है। द्वितीय चरण में, रेलवे प्लॉटों में 400 मेगावॉट क्षमता को आरईएमसीएल के स्वामित्व मॉडल के तहत् बिना खुली पहुंच वाले राज्यों के लिए विकसित किया जाएगा। इसके लिए 16 जून 2020 को निविदा जारी की गई है। तीसरे चरण में रेलवे की भूमि पर डेवलपर मॉडल के तहत् पटरियों के साथ-साथ खुली पहुंच वाले राज्यों के लिए ट्रैक स्थापित किए जाएंगे, जिसके लिए 1 जुलाई, 2020 को निविदा जारी की गई है।

पवन ऊर्जा क्षेत्र में, 103 मेगावॉट पवन आधारित बिजली संयंत्रों को पहले ही चालू कर दिया गया है। इनमें 26 मेगावॉट क्षमता वाली परियोजना राजस्थान के जैसलमेर में, 21 मेगावॉट क्षमता वाली परियोजना तमिलनाडु में और 56.4 मेगावॉट क्षमता वाली परियोजना महाराष्ट्र के सांगली में है। भारतीय रेल ने तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान और कर्नाटक में अगले 2 वर्षों में 200 मेगावॉट क्षमता वाले पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की भी योजना बनाई है।

जलवायु परिवर्तन में अपनी भूमिका का एहसास करते हुए भारतीय रेल ने इमारतों और स्टेशनों में एलइडी बल्बों के जरिए 100 फीसदी प्रकाश करने जैसी हरित पहल शुरू की है। भारतीय रेल ने सीआईआईआई से अपनी 7 प्रोडक्शन यूनिट्स, 39 वर्कशॉप्स, 6 डीजल शेड और 1 स्टोर्स डिपो के लिए हरित प्रमाण पत्र भी हासिल कर लिया है। 14 रेलवे स्टेशनों और 21 अन्य भवनों/परिसरों को भी हरित ऊर्जा वाले भवनों के रूप में प्रमाणित किया गया है। इसके अलावा 215 स्टेशनों को पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस)/आईएसओ 14001 के साथ प्रमाणित किया गया है।



हेड ऑन जेनरेशन

कुल 505 जोड़ी ट्रेनों में 'हेड ऑन जेनरेशन' तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इससे प्रति वर्ष लगभग 70 मिलियन लीटर डीजल/ 450 करोड़ रुपये की बचत की संभावना है। रेलवे ने इसके अलावा अपनी सभी 8 उत्पादन इकाइयों और 12 कार्यशालाओं में ऊर्जा दक्षता हासिल करने के लिए सीआईआई के साथ करार किया है, जिसके परिणामस्वरूप ऊर्जा दक्षता में 15 प्रतिशत सुधार हुआ है। ■



पवन ऊर्जा



हरित पहल के तहत् भारतीय रेल ने अपनी रेलगाड़ियों के कुल 69,000 डिब्बों में 2,44,000 से अधिक जैव-शौचालय लगाए हैं

कोविड के बावजूद रेलवे ने मिशन मोड पर ज्यादा माल ढुलाई की

कोविड से उपजी चुनौतियों के बावजूद भारतीय रेल ने मिशन के तौर पर काम करते हुए सितंबर 2020 महीने में 6 सितंबर तक पिछले वर्ष की समान अवधि में हुई माल ढुलाई और कमाई के आंकड़े को पार कर लिया है।

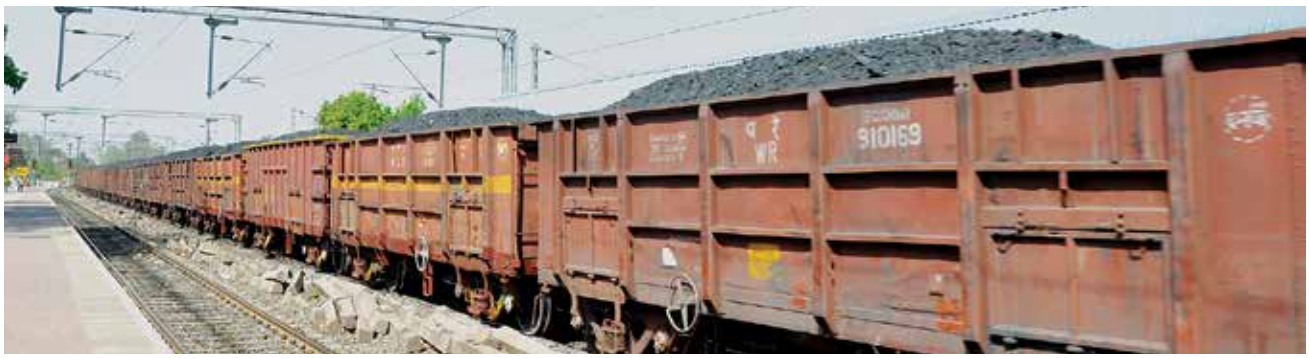
सितंबर 2020 के महीने में 6 सितंबर तक भारतीय रेल द्वारा माल ढुलाई 19.19 मिलियन टन हुई, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में हुई माल ढुलाई (17.38 मिलियन टन) की तुलना में 10.41 प्रतिशत (1.81 मिलियन टन) अधिक है। इस अवधि में भारतीय रेल ने माल ढुलाई से 1836.15 करोड़ रुपये कमाए जो पिछले वर्ष की समान अवधि की कमाई (1706.47 करोड़ रुपये) की तुलना में 129.68 करोड़ अधिक है। सितंबर 2020 के महीने में 6 सितंबर तक भारतीय रेल में 19.19 मिलियन टन की माल ढुलाई हुई जिसमें 8.11 मिलियन टन कोयला, 2.59 मिलियन टन लौह अयस्क, 1.2 मिलियन टन खाद्यान्न, 1.03 मिलियन टन उर्वरक और 1.05 मिलियन टन (क्लिंकर को छोड़कर) सीमेंट शामिल है। उल्लेखनीय है कि रेलवे द्वारा माल ढुलाई को बहुत ही आकर्षक बनाने के लिए भारतीय रेल में कई रियायतें/छूट दी जा रही हैं। यह ध्यान देने की बात है कि माल ढुलाई में सुधार को संस्थागत रूप दिया जाएगा और इसे आगामी शून्य आधारित समय सारिणी में शामिल किया जाएगा।

रेलवे से माल परिवहन के कुछ लाभ इस प्रकार हैं

- सब्सिडी मिलने के कारण माल परिवहन सस्ता होना
- तेजी और कुशलता के साथ माल की आपूर्ति
- बिना किसी नुकसान के सामान का गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाया जाना सुनिश्चित करना
- पर्यावरण अनुकूल परिवहन के तरीके जिससे कार्बन उत्सर्जन घटेगा
- किसानों को अतिरिक्त लाभ पहुंचाने तथा जल्दी नष्ट होने वाली उपभोग की वस्तुओं को ताजा रखने के लिए किसान रेलगाड़ी जैसी विशेष रेलगाड़ी चलाना
- ये पहलें उद्योग संघों के सहयोग से की जा सकती हैं
- दीपावली के दौरान समय पर सामानों की आपूर्ति से थोक व्यापारी कैसे लाभान्वित हों इस पर ध्यान केन्द्रित करना
- भारतीय रेल सीधे संपर्क किए जाने वाले फोन नंबरों और वेबसाइट के पते को प्रचारित करेगी, जिससे व्यापारी अपने माल भेजने के लिए रेलवे से आसानी से संपर्क कर सकें
- भारतीय रेल की ओर से ऐसी घटनाओं को साझा किया जा सकता है, जिससे आम आदमी को यह पता लग सके कि वह किस तरह से दैनिक उपयोग की वस्तुओं को आसानी से खरीद पाने के लिए भारतीय रेल की कुशल सेवाओं से लाभान्वित हो सकता है

उठाए गए कदम

- मंडल, जोन और रेलवे बोर्ड के स्तर पर व्यवसायिक इकाइयों की स्थापना –
- मालगाड़ियों की गति दोगुनी करके 23 किमी प्रति घंटे से 46 किमी प्रति घंटे करना
- 20 जोड़ी पार्सल रेलगाड़ियों का 30 मार्च, 2020 से तय समय पर परिचालन शुरू
- बांग्लादेश को निर्यात के लिए पार्सल और कंटेनरों का 10 जुलाई, 2020 से उद्घाटन
- बांग्लादेश के लिए ऑटोमोबाइल्स की निर्यात सेवाओं का 12 अगस्त, 2020 से उद्घाटन
- कई स्टेशनों पर ठहराव व कई वस्तुओं के परिवहन के साथ किसान रेलगाड़ी देवलाली (नासिक) से दानापुर (पटना) के लिए शुरू की गई – 7 से 14 अगस्त, 2020 तक दो फेरे लगा चुकी है
- मालगाड़ी एक्सप्रेस ट्रेन – व्यापार माला एक्सप्रेस रेलगाड़ियों का परिचालन
- रेल परिवहन को अधिक आकर्षक बनाने के लिए शुल्क सहित और शुल्क रहित पहल
- मिशन मोड के तहत माल शेड में सुधार – 405 की पहचान
- डाक विभाग के साथ मिलकर ग्राहकों के लिए सामान पहुंचाने की डोर-टू-डोर सेवा की शुरुआत



भारतीय रेल 2030 तक 33 बिलियन यूनिट से अधिक की ऊर्जा खपत को पूरा करेगी

वर्तमान वार्षिक आवश्यकता लगभग 21 बिलियन यूनिट

- भारतीय रेल की सौर ऊर्जा डेवलपर्स के साथ बैठक
- भारतीय रेल अपनी अतिक्रमण नहीं की गई खाली भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए डेवलपर्स को पूरा सहयोग देगी
- प्रमुख सौर ऊर्जा डेवलपर्स बैठक में शामिल, वर्ष 2030 से पहले 'शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक' बनने की भारतीय रेल की यात्रा में साझेदार बनने की अपनी उम्मीदों को साझा किया
- रेलवे का वर्ष 2023 तक 100 प्रतिशत विद्युतीकरण का लक्ष्य
- भारतीय रेल की वर्ष 2030 तक अपनी खाली भूमि पर 20 गीगावॉट क्षमता का सौर संयंत्र लगाने की योजना

अपनी ऊर्जा की सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए शत-प्रतिशत (100%) आत्मनिर्भर बनने के लक्ष्य को हासिल करने और साथ ही राष्ट्रीय सौर ऊर्जा लक्ष्यों में योगदान देने के लिए भारतीय रेल ने रेलवे और वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में प्रमुख हितधारकों के साथ व्यापक बैठक आयोजित की।

भारतीय रेल अपनी कर्षण यानि खींचने की शक्ति की आवश्यकता को पूरा करने और परिवहन का एक पूर्ण 'ग्रीन मोड' बनने के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग के लिए प्रतिबद्ध है।

इस बैठक में चर्चा के प्राथमिक क्षेत्र इस प्रकार थे

1. रेलवे ट्रैक के बगल में सौर परियोजनाएं स्थापित करने के लिए नवीन समाधान।
2. भारतीय रेल द्वारा वर्ष 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने के निर्धारित समय तक 20 गीगावॉट अक्षय ऊर्जा लक्ष्य हासिल करने के लिए संभावित बिजली खरीद क्रम।
3. भारतीय रेल द्वारा बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा परियोजनाएं लगाने में चुनौतियां।

डेवलपर्स ने देश में नवीकरणीय ऊर्जा के विकास में अग्रणी भारतीय रेल के प्रयासों को स्वीकार किया और वर्ष 2030 तक भारतीय रेल को हरित होने और शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त करने के रास्ते पर मजबूती से सहयोग देने की इच्छा व्यक्त की। यह रेलवे स्टेशनों में सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करने और रेलवे की खाली पड़ी भूमि का नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) परियोजनाओं के लिए उपयोग करने के प्रधानमंत्री के हालिया निर्देशों की तर्ज पर है।

यह सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की एक पहल राष्ट्रीय सौर मिशन की दिशा में भी योगदान देगी।





भारतीय रेल के 960 से अधिक स्टेशनों का सौरकरण

अपनी सारी बिजली उपभोग आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 100 प्रतिशत आत्मनिर्भर बनने तथा राष्ट्रीय सौर बिजली लक्ष्यों में योगदान देने के लिए भारतीय रेल ने अभी तक 960 से अधिक स्टेशनों का सौरकरण कर दिया है। 550 स्टेशनों, जो निष्पादन के अधीन हैं, के लिए 198 मेगावॉट सोलर रूफटॉप क्षमता के लिए आर्डर दिए गए हैं।

जिनका सौरकरण हो चुका है, उनमें से कुछ स्टेशन हैं- वाराणसी, नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, जयपुर, सिकंदराबाद, कोलकाता, गुवाहाटी, हैदराबाद, हावड़ा आदि।

भारतीय रेल के पास लगभग 51,000 हेक्टेयर रिक्त भूमि उपलब्ध है और अब वह डेवलपर्स को रेलवे की अनधिग्रहित रिक्त भूमि पर सौर बिजली संयंत्र संस्थापित करने के लिए सभी सहायता देने को तैयार है। उल्लेखनीय है कि रेलवे वर्ष 2023 तक 100 प्रतिशत विद्युतीकरण अर्जित करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

उल्लेखनीय है कि भारतीय रेल अपनी ट्रैक्शन विद्युत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करने एवं पूरी तरह 'परिवहन का हरित मोड' बनने के लिए प्रतिबद्ध है। यह रेलवे स्टेशनों का सौरकरण करने एवं नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) परियोजनाओं के लिए रिक्त रेल भूमि का उपयोग करने के प्रधानमंत्री के निर्देश की तर्ज पर है।

इस संबंध में, आरंभ में भारतीय रेल की एक पीएसयू रेलवे एनर्जी मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (आईईएमसीएल) द्वारा पहले ही रेलवे ट्रैक के साथ साथ रिक्त रेल भूमि पार्सलों एवं भूमिक पार्सलों पर 3 जीडब्ल्यू सौर परियोजनाओं के लिए बोली आमंत्रित की जा चुकी है। कम शुल्क पर रेलवे को बिजली की आपूर्ति करने के अतिरिक्त ये सौर परियोजनाएं ट्रैक के साथ साथ चारदीवारी के निर्माण के द्वारा रेलवे की भूमि की सुरक्षा भी करेंगी। ■



मध्यप्रदेश की बीना में 25 केवी ट्रैक्शन सिस्टम से सीधी कनेक्टिविटी के साथ 1.7 मेगावॉट क्षमता की पायलट परियोजना सफलतापूर्वक काम करने लगी है। इसके अलावा, गैर-अनुवीक्षण अनुप्रयोगों के लिए रायबरेली में आधुनिक कोच फैक्टरी (एमसीएफ) में 3 मेगावॉट क्षमता का सौर संयंत्र भी चालू किया गया है। इसके अलावा, राज्य ट्रांसमिशन उपयोगिता (एसटीयू) और केंद्रीय ट्रांसमिशन उपयोगिता (सीटीयू) के साथ कनेक्टिविटी के लिए क्रमशः 2 और परियोजनाएं - 2 मेगावॉट की दीवाना में और 50 मेगावॉट क्षमता की भिलाई में प्रगति पर हैं।

सौर ऊर्जा के उपयोग से रेलवे को 'शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन रेलवे' में बदलने के मिशन को हासिल करने में तेजी आएगी। इसे प्राप्त करने के लिए, भारतीय रेल ने 2030 तक अपनी खाली भूमि का उपयोग करके 20 गीगावॉट क्षमता के सौर संयंत्र स्थापित करने के लिए एक बहुत बड़ी योजना विकसित की है। रेलवे की वर्ष 2023 तक 100 प्रतिशत विद्युतीकरण प्राप्त करने की महत्त्वाकांक्षी योजना के साथ, भारतीय रेल की ऊर्जा की खपत 2030 तक 33 बिलयन यूनिट से अधिक हो जाएगी जबकि वर्तमान वार्षिक आवश्यकता लगभग 21 बिलियन यूनिट है।

भारतीय रेल ने डीकार्बोनाइजेशन के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है जिसे लगाई जा रही सौर परियोजनाओं द्वारा पूरा किया जाएगा। इससे यह ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने वाला पहला परिवहन संगठन बन जाएगा। इस संबंध में रेल पटरी के बगल में रेलवे की खाली भूमि के टुकड़े और रेलवे की सम्पत्ति पर 3 गीगावॉट की सौर परियोजनाओं के लिए भारतीय रेल का सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, रेलवे ऊर्जा प्रबंधन कंपनी लिमिटेड (आरईएमसीएल) पहले ही बोलियां लगा चुका है। इन सौर परियोजनाओं से, रेलवे को कम शुल्क पर बिजली की आपूर्ति होने के अलावा, पटरी के साथ-साथ चारदीवारी के निर्माण से रेलवे की भूमि की रक्षा भी की जा सकेगी।

श्री गोयल ने बताया कि भारतीय रेल, रेलवे की अतिक्रमण नहीं की गई खाली भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए डेवलपर्स को हर प्रकार का सहयोग देने को तैयार है। पटरी के साथ चारदीवारी का निर्माण और रखरखाव डेवलपर्स द्वारा किया जाएगा। आधुनिक स्वदेशी प्रौद्योगिकी को अपना कर ऊर्जा की दृष्टि से आत्मनिर्भर रेलवे भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों और राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अंशदान (आईएनडीसी) को पूरा करने में योगदान देगी, जैसी कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्रतिबद्धता है। ■

आत्मनिर्भर भारत मिशन के लिए तैयार है भारतीय रेल

सरकारी ई-बाजार जीईएम से अपनी वस्तुओं और सेवाओं की खरीद करेगी भारतीय रेल

हर साल 70,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की वस्तु एवं सेवाओं की खरीद करती है भारतीय रेल

- श्री पीयूष गोयल ने रेलवे की खरीद प्रक्रिया में 'मेक इन इंडिया' उत्पादों को प्रोत्साहन देने के लिए उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा की, भारतीय रेल में सामग्री प्रबंधन की विस्तृत प्रदर्शन समीक्षा की गई
- भारतीय रेल की ई-खरीद प्रणाली आईआरईपीएस का जीईएम के साथ होगा एकीकरण
- अधिकारियों को उद्योग के साथ संवाद करने, आत्म निर्भर भारत की दिशा में प्रगति के लिए अपनी क्षमताओं और संभावनाओं के विस्तार और विनिर्माण सहित भारतीय आर्थिक संसाधनों की भागीदारी में बढ़ोत्तरी सुनिश्चित करने के निर्देश
- खरीद में स्थानीय सामग्री के नियम की आवश्यकता, जिससे स्थानीय वेंडर्स आपूर्तिकर्ताओं से ज्यादा निविदाएं हासिल हो सकें

रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने भारतीय रेल के साथ ही भारत सरकार की खरीद प्रक्रिया में 'मेक इन इंडिया' उत्पादों को प्रोत्साहन देने के लिए उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा की।

बैठक के दौरान श्री पीयूष गोयल ने भारतीय रेल से भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी खरीद का वातावरण विकसित करके उद्योग में भरोसा पैदा करने से लिए जरूरी कदम उठाने का अनुरोध किया।

खरीद प्रक्रिया में 'मेक इन इंडिया' उत्पादों को प्रोत्साहन देने से जुड़े कदमों की समीक्षा करते हुए खरीद की प्रक्रिया में स्थानीय वेंडर्स की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया गया। यह भी फैसला लिया गया कि खरीद में स्थानीय सामग्री के नियम ऐसे होने चाहिएं कि हमें स्थानीय वेंडर्स/ आपूर्तिकर्ताओं से ज्यादा निविदाएं हासिल हो सकें। इससे भी 'आत्मनिर्भर भारत' मिशन को बढ़ावा मिलेगा। इस दिशा में भारतीय रेल के प्रयासों को सुनिश्चित करने के लिए डीपीआईआईटी के सक्रिय सहयोग की मांग की गई, जिससे आवश्यकता पड़ने पर उपयुक्त नीतिगत बदलाव किए जा सकें।

यह महसूस किया गया कि ऐसे वेंडर्स को प्रोत्साहित किए जाने की जरूरत है, जो अधिकांशत: स्थानीय स्तर पर विनिर्मित सामग्री की आपूर्ति कर सकें। एक एफएक्यू भाग और एक हेल्पलाइन बनाने का भी सुझाव दिया गया, जिससे वेंडर्स को खरीद प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर स्पष्टता रहे।

इस अवसर पर सदस्य (सामग्री प्रबंधन), रेलवे द्वारा 'मेक इन इंडिया'' को प्रोत्साहन और जीईएम के माध्यम से खरीद के लिए उठाए जा रहे कदमों पर एक विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया गया।

समीक्षा बैठक में रेल राज्य मंत्री श्री सुरेश अंगडी, रेलवे बोर्ड के सदस्य, सीईओ/जीईएम और डीपीआईआईटी, वाणिज्य मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

भारतीय सेवा प्रदाताओं और कलपुर्जा विनिर्माताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए रणनीतियां बनाने की आवश्यकता महसूस की गई। सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) दुनिया भर में सरकारी खरीद से जुड़ा बेहद नवीन विचार है। श्री गोयल ने बाजार को उद्योग के लिए विशेष रूप से दूरदराज के इलाकों और एमएसएमई के लिए खोलकर जीईएम प्लेटफॉर्म से रेलवे की लगभग 70 हजार करोड़ रुपये की वस्तु एवं सेवाओं को खरीदने पर जोर दिया।

भारत सरकार की सबसे बड़ी खरीद एजेंसियों में से एक भारतीय रेल जीईएम की पूरी क्षमताओं के उपयोग के लिए, अपनी खरीद प्रणालियों को जीईएम के साथ एकीकृत कर रही है। विभाग ने भारतीय रेल की ई-खरीद प्रणाली को जीईएम के साथ एकीकृत करने के लिए समय-सीमा साझा की। रेलवे ने किसी भी प्रकार के मैनुअल इंटरफेस (संपर्क) की जरूरत को खत्म करने के लिए 2 प्रणालियों के निरंतर एकीकरण की आवश्यकता पर जोर दिया। रेलवे की खरीद को पूरी तरह से जीईएम पर ले जाने के लिए दोनों प्रणालियों, आईआरईपीएस और जीईएम के बीच तालमेल कायम किया जाना चाहिए।

एकीकरण के बाद भारत सरकार का सभी एजेंसियों के लिए एकल बिंदु सार्वजनिक खरीद पोर्टल की दिशा में आगे बढ़ने का इरादा है।

बैठक के दौरान भारत में भ्रष्टाचार मुक्त सार्वजनिक खरीद का वातावरण तैयार करने के तरीकों पर चर्चा की गई, जिसमें रेल मंत्रालय, डीपीआईआईटी और जीईएम को अत्यधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभानी है। विचार-विमर्श के दौरान भारतीय रेल के विकास के सफर में ज्यादा-से-ज्यादा स्वदेसी वेंडर्स की भागीदारी के लिए उद्योग को जोड़ने की आवश्यकता पर जोर दिया गया।

प्रस्तुतीकरण के दौरान यह फैसला लिया गया कि रेलवे अपनी सभी गतिविधियों के लिए उपयोग के अनुकूल सिंगल स्टेप वेब आधारित इंटरफेस विकसित करने की दिशा में काम करेगी। वेबसाइट पारदर्शी होनी चाहिए, साथ ही हर इच्छुक वेंडर को भारतीय रेल के काम के तरीके से अवगत कराना चाहिए। वेबसाइट में भारतीय रेल के भ्रष्टाचार मुक्त होने और पारदर्शी माहौल होने का भरोसा दिलाने वाली सभी उपयुक्त जानकारियां होनी चाहिए। ■

रेलकर्मियों के लिए ई-पास की सुविधा शुरू

अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड श्री विनोद कुमार यादव ने रेलकर्मियों के लिए ऑनलाइन ई-पास बनाने और टिकट बुकिंग के लिए सीआरआईएस द्वारा मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस) परियोजना के तहत विकसित किए गए ई-पास मॉड्यूल का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ किया। इस अवसर पर रेलवे बोर्ड के सभी सदस्य, आईआरसीटीसी के अध्यक्ष सह-प्रबंध निदेशक, सीआरआईएस के प्रबंध निदेशक, सभी महाप्रबंधक, पीसीपीओएस, पीसीसीएमएस, पीएफए और डीआरएम उपस्थित थे।

महानिदेशक, मानव संसाधन ने इस मौके पर ई-पास मॉड्यूल और इसके चरणबद्ध कार्यान्वयन की रणनीति के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी दी।

कर्मचारियों के लिए पास जारी करने की प्रक्रिया अभी तक मैनुअल ही की जाती रही है। इसके अलावा रेलवे कर्मचारी के लिए पास पर ऑनलाइन टिकट बुक करने की कोई सुविधा भी नहीं थी।

ईआर पास मॉड्यूल को एचआरएमएस परियोजना के तहत सीआरआईएस द्वारा विकसित किया गया है। इसे चरणबद्ध तरीके से भारतीय रेल से जोड़ा जाएगा। इस सुविधा के साथ रेलवे कर्मचारी को न तो पास के लिए आवेदन करने के लिए कार्यालय आना पड़ेगा और न ही पास जारी होने का इंतजार करना पड़ेगा। कर्मचारी कहीं से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और ई-पास ऑनलाइन प्राप्त कर सकेंगे। ई-पास के लिए आवेदन और इसे प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया मोबाइल पर उपलब्ध रहेगी। इसके माध्यम से पहले की तरह पीआरएस/यूटीएस काउंटर से टिकट बुकिंग की सुविधा के अलावा पास पर टिकट बुक करने की सुविधा आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगी।

यह सुविधा रेलवे कर्मचारियों को उन्हें रेल पास का आसानी से उपयोग करने में मदद करेगी और साथ ही साथ सभी अधिकारियों को पास जारी करने का काम भी सुगम बनाएगी।

एचआरएमएस परियोजना भारतीय रेलवे की पूर्ण मानव संसाधन प्रक्रिया के डिजिटलीकरण की एक व्यापक योजना है। एचआरएमएस में कुल 21 मॉड्यूल की योजना बनाई गई है। लगभग 97 प्रतिशत रेलवे कर्मचारियों की बेसिक डेटा एंट्री एचआरएमएस के कर्मचारी मास्टर और ई-सर्विस रिकॉर्ड मॉड्यूल में पूरी हो चुकी है, जिसे पिछले साल लॉन्च किया गया था।

सीआरआईएस बहुत जल्द ही एचआरएमएस का ऑफिस ऑर्डर मॉड्यूल और सेटलमेंट मॉड्यूल भी लॉन्च करने जा रहा है। ■

आप सब का

भारतीय रेल

के साथ अटूट रिश्ता है

भारतीय रेल के साथ आप अपने संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, गीत, आदि लेख हिन्दी में हमें भेजें। पसंद आने पर रचनाओं को हम रेल मंत्रालय की आधिकारिक मासिक पत्रिका

'भारतीय रेल'

में प्रकाशित करेंगे।

ई-मेल: editorbhartiyarailrb@gmail.com

पसंद किये गये लेख की जानकारी ई-मेल से दी जाएगी। प्रकाशित होने पर मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानदेय भी दिया जाएगा।

शर्तें लागू

'फिट इंडिया मूवमेंट' के तहत भारतीय रेल में 'फिट इंडिया फ्रीडम रन' का भव्य आयोजन

भारतीय रेल ने भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा शुरू की गई नई पहल 'फिट इंडिया फ्रीडम रन' का पूरी तरह से सहयोग कर रही है। यह आयोजन 15 अगस्त से 2 अक्टूबर, 2020 तक किया जा रहा है। इस पहल को 'फिट इंडिया मूवमेंट' के तत्वावधान में किया जा रहा है। समग्र भारतीय रेल में 'फिट इंडिया फ्रीडम रन' का सफल आयोजन किया जा रहा है।

'फिट इंडिया रन' की कल्पना सामाजिक दूरी (सोशल डिस्टेंसिंग) के नियम का पालन करते हुए खुद को फिट रखने की अपरिहार्य आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए की गई है। इस रन में एक व्यक्ति अपने अनुकूल समय पर अपनी पसंद के किसी मार्ग पर दौड़ / चल सकता है। ऐसे रन / वॉक के दौरान कोई विश्राम (ब्रेक) भी ले सकता है। असल में, इसमें हर कोई अपनी दौड़ पूरी करता है और अपने हिसाब से अपनी दौड़ की गति तय करता है।

युवा मामलों और खेल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री श्री किरण रिजिजू ने 'फिट इंडिया फ्रीडम रन' का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष श्री विनोद कुमार यादव भी मौजूद थे। इस पहल को सफल बनाने के लिए सभी क्षेत्रीय रेलवे / इकाइयों को 'फिट इंडिया फ्रीडम रन' को लेकर जागरूकता फैलाने और इस अभियान में बड़ी संख्या में रेलवे अधिकारियों, उनके परिजनों एवं रिश्तेदारों को शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करते हुए 'फिट इंडिया फ्रीडम रन' में बड़ी भागीदारी सुनिश्चित करने की सलाह दी गई। भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों में दिए गए सरल कदम उठाते हुए खुद को फिट रखने की भी सलाह दी गई है। ये दिशा-निर्देश मंत्रालय की वेबसाइट www.fitindia.gov.in पर उपलब्ध हैं।

- 'फिट इंडिया फ्रीडम रन' को सफल बनाने के लिए रेलवे के सभी महाप्रबंधकों को रेलवे परिवार के बीच अधिकतम जागरूकता फैलाने और अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।
- भारतीय रेल के पास 29 खेलों के लगभग 10,000 खिलाड़ी और 300 कोच हैं; वर्ष 2019-20 में कुल 32 राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में से 6 पुरस्कार भारतीय रेल के खिलाड़ियों ने जीते थे

भारतीय रेल में अपनी शुरुआत से ही भारत में खेलों को बढ़ावा देने की महान परंपरा रही है। यह भारत में खेलों का सबसे बड़ा प्रमोटर है जो हर साल 300-400 खिलाड़ियों को रोजगार प्रदान करता है और उन्हें खेल में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए सभी सुविधाएं और अनुकूल माहौल देता है ताकि वे देश के लिए मेडल ला सकें। भारतीय रेल के पास 29 खेलों में लगभग 10,000 खिलाड़ी और 300 कोच हैं। वर्ष 2019-20 में कुल 32 राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में से 6 पुरस्कार भारतीय रेल के खिलाड़ियों ने जीते थे।

देश में अत्याधुनिक खेल अवसंरचना के निर्माण और खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सभी मूल्यांकनों में खेल विकास के लिए 0.5 प्रतिशत डीएंडजी शुल्क का प्रावधान शामिल किया गया है। यह भारतीय रेल द्वारा खेल को बढ़ावा देने और 'फिट इंडिया' पहल के एक भाग के रूप में एक अनूठी पहल है। 'फिट इंडिया फ्रीडम रन' को सफल बनाने के लिए सभी महाप्रबंधकों को रेलवे परिवार के बीच अधिक-से-अधिक जागरूकता फैलाने और अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था। ■



मध्य रेल द्वारा 'फिट इंडिया फ्रीडम रन' का आयोजन किया गया, जिसमें रेलकर्मियों एवं उनके परिवारजनों ने बड़ी संख्या में भाग लिया

सीएसएमटी रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास

सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति (पीपीपीएसी) के सिद्धांत अनुमोदन के बाद पीपीपी मोड पर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (मुंबई) रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए, पीपीपी आधार पर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (मुंबई) के पुनर्विकास के लिए अर्हता (आरएफक्यू) के लिए अहर्ता आवेदन आईआरएसडीसी द्वारा आमंत्रित किया गया है। आरएफक्यू दस्तावेज http://irsdc.enivida.com पर उपलब्ध है। आवेदन की देय तिथि 22.10.2020 है।

पात्रता मानदंड को पूरा करने वाले आवेदकों की अगले चरण में भाग लेने के लिए एक संक्षिप्त सूची बनाई जाएगी। बोली की संपूर्ण प्रक्रिया दो चरण की है, जिसमें आरएफक्यू और रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (आरएफपी) शामिल हैं। आरएफपी चरण में चयनित बोलीदाता 60 वर्ष के पट्टे के आधार पर वाणिज्यिक विकास के लिए रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास और आसपास की रेलवे भूमि का वाणिज्यिक विकास तथा 60 वर्षों के लिए रियायती आधार पर स्टेशन के परिचालन और रखरखाव के साथ चयनित भूखंडों पर 99 वर्ष तक आवासीय विकास के लिए संचालन और रखरखाव करेगा। रियायतकर्ता को उपयोगकर्ता शुल्क भी राजस्व का एक और निरंतर स्रोत होगा जो स्टेशन की वाणिज्यिक परिचालन तिथि (सीओडी) के ठीक बाद उपलब्ध होगा। यह योजना फ्रांस के मैसर्स एआरईपी द्वारा बनाई गई है और समय-समय पर विभिन्न हितधारकों के साथ चर्चा की गई है। स्टेशन की पुनर्विकास लागत (अनिवार्य लागत), जिसमें वित्त पोषण और आकस्मिकता आदि की लागत शामिल है, 1,642 करोड़ रुपये है। पुनर्विकास के लिए निवेश का अवसर डीबीएफओटी (डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट और ट्रांसफर)के आधार पर है।

परियोजना की प्रमुख मुख्य विशेषताएं

- पीपीपी परियोजनाओं के लिए सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार पीपीपीएसी की सैद्धांतिक स्वीकृति में वित्त मंत्रालय, कानून मंत्रालय, नीति आयोग, रेल मंत्रालय आदि के प्रतिनिधि शामिल हैं;
- पात्रता मानदंड आरएफक्यू चरण में वित्तीय क्षमता के संदर्भ में है और पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के करीब नेट वर्थ / एसीआई 821 करोड़ रुपये होना चाहिए;
- निर्माण और ओएंडएम अनुभव क्षमता परियोजना मिलने के बाद, लेकिन नियत तारीख से पहले पूरी होनी चाहिए;
- **रेलवे स्टेशनों की विस्तारित ओएंडएम अवधि :** बेहतर यात्री सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करने के लिए, रेलवे स्टेशन 60 वर्षों के लिए छूटग्राही के साथ लाइसेंस पर होंगे;
- **अतिरिक्त राजस्व स्रोत :** रेलवे स्टेशन उपयोगकर्ताओं से पूर्व निर्धारित उपयोगकर्ता शुल्क ले सकेगा, (जैसाकि रेल मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया है) जैसाकि हवाई अड्डों आदि में प्रचलन में है;
- **अचल संपत्ति के लिए दीर्घकालिक पट्टा अधिकार :** आवासीय या मिश्रित उपयोग के लिए 99 वर्ष तक का और गैर-आवासीय प्रारूपों के लिए 60 वर्ष। वाणिज्यिक विकास के लिए निर्मित क्षेत्र (अस्थायी) के 2.54 लाख वर्गमीटर तक के क्षेत्र की अनुमति है। आरएफपी चरण में बनाए गए सटीक क्षेत्र की जानकारी दी जाएगी;
- भूमि उपयोग में परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं है;
- पर्यावरण और वन मंत्रालय से कोई पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता नहीं है;
- आईआरएसडीसी रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 11 के तहत प्रदत्त शक्ति के संदर्भ में स्थानीय अधिकारियों के परामर्श से मास्टर प्लान और भवन निर्माण योजनाओं की मंजूरी के लिए एकल खिड़की होगी;
- वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ)या विदेशी निवेश कोष (एफआईएफ)भी भाग लेने के पात्र हैं; तथा
- अर्हता मानदंड को पूरा करने वाले सभी आवेदक आरएफपी अवस्था पर मूल्य बोली प्रस्तुत करने के पात्र होंगे, अर्थात्, आरएफपी चरण के लिए आवेदकों की संक्षिप्त सूची तैयार करने की कोई ऊपरी सीमा नहीं है।

विस्तृत जानकारी और हाल के अपडेट के लिए ट्विटर (irsdcinfo), फेसबुक (facebook.com/IRSDC) और लिंकडिन (linkedin.com/company/ इंडियन-रेलवे-स्टेशन्स-डेवलपमेंट-कार्पोरेशन-लिमिटेड) या वेबसाइट irsdc.in की मदद ली जा सकती है। ■



रेल कोच फैक्ट्री, कपूरथला ने 'पोस्ट कोविड कोच' डिजाइन किया

भारतीय रेल ने कोविड-19 वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कई कदम उठाने के साथ-साथ अनेक उल्लेखनीय उपाय किए हैं। इसी क्रम में रेल कोच फैक्ट्री, कपूरथला ने 'पोस्ट कोविड कोच' विकसित किया है। कोविड मुक्त यात्री सफर के लिए इस कोच में हैंड्सफ्री सुविधाओं, कॉपर कोटिंग युक्त रेलिंग व चिटकनी और प्लाज्मा एयर प्यूरीफायर के अलावा टाइटेनियम डाई-ऑक्साइड कोटिंग भी की गई है।

हैंड्सफ्री सुविधाएं: 'पोस्ट कोविड कोच' में अनेक हैंड्सफ्री सुविधाएं हैं जैसे कि पैर से संचालित पानी का नल एवं साबुन निकालने की मशीन, पैर से संचालित शौचालय द्वार (बाहर), पैर से संचालित फ्लश वॉल्व, पैर से संचालित शौचालय के दरवाजे की चिटकनी, टॉयलेट के बाहर स्थित वॉश बेसिन में पैर से संचालित पानी का नल एवं साबुन निकालने की मशीन और डिब्बे के दरवाजे पर बांह से संचालित हैंडल। मतलब यह कि इनमें से किसी को भी हाथ से छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी।





कॉपर कोटिंग युक्त रेलिंग व चिटकनी : 'पोस्ट कोविड कोच' में कॉपर कोटिंग युक्त रेलिंग व चिटकनियां लगाई गई हैं क्योंकि कॉपर के संपर्क में आने वाला वायरस कुछ ही घंटों में निष्क्रिय हो जाता है। कॉपर में सूक्ष्मजीव-रोधी गुण होते हैं। जब कॉपर की सतह पर वायरस आता है तो आयन रोगाणु को जोर का झटका देता है और वायरस के अंदर स्थित डीएनए एवं आरएनए को नष्ट कर देता है।

प्लाज्मा एयर प्यूरीफायर : 'पोस्ट कोविड कोच' में एसी नली या पाइप में प्लाज्मा एयर उपकरण लगा होता है। यह प्लाज्मा एयर उपकरण आयन युक्त वायु का उपयोग करके एसी कोच के अंदर की हवा और सतहों को जीवाणुरहित कर देगा और इस तरह से कोच या डिब्बे को कोविड-19 एवं सूक्ष्म कण-रोधी बना देगा। यही नहीं, इस सुविधा से आयन सांद्रता 100 आयन/घन सेंटीमीटर से बढ़कर 6,000 से अधिक आयन/घन सेमी हो जाएगी।



टाइटेनियम डाई-ऑक्साइड कोटिंग : 'पोस्ट कोविड कोच' में टाइटेनियम डाई-ऑक्साइड कोटिंग की सुविधा है। नैनो संरचना वाली टाइटेनियम डाई-ऑक्साइड कोटिंग दरअसल फोटोएक्टिव (प्रकाश द्वारा सहज प्रभावित) सामग्री के रूप में कार्य करती है। यह एक पर्यावरण अनुकूल जल-आधारित कोटिंग है जो वायरस, बैक्टीरिया, फफूंदी एवं फंगस को नष्ट कर इन्हें पनपने नहीं देती और सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि यह अंदर की हवा को बेहतर बना देती है। यह जहरीली नहीं है, जोकि संयुक्त राज्य अमेरिका के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) की खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा अनुमोदित एवं सीई प्रमाणित है। टाइटेनियम डाई-ऑक्साइड को एक सुरक्षित पदार्थ माना जाता है और यह मनुष्य के लिए हानिरहित है। यह टाइटेनियम डाई-ऑक्साइड कोटिंग वॉश बेसिन, शौचालय, सीटों एवं बर्थ, स्नैक टेबल, ग्लास विंडो, फ्लोर सहित हर उस सतह पर की गई है जहां लोगों का हाथ लग जाता है। यह कोटिंग 12 माह तक प्रभावकारी या कारगर रहती है।



मध्य रेल पर आपटा स्टेशन, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस स्टेशन के बाद फिल्म शूटिंग के लिए पसंदीदा लोकेशन





मध्य रेल पर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस स्टेशन के बाद आपटा रेलवे स्टेशन फिल्म निर्माताओं के लिए सबसे लोकप्रिय फिल्म शूटिंग लोकेशन बना हुआ है। वित्तीय वर्ष 2019-2020 में आपटा रेलवे स्टेशन पर चार फिल्मों की शूटिंग की गई, जिसमें रात अकेली है, मुंबई सागा और शुभ मंगल ज्यादा सावधान शामिल हैं, जबकि 8 फिल्मों की शूटिंग छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस में की गई, जिनमें सबसे लोकप्रिय फिल्में पंगा, चोक्ड और सूरज से मंगल भारी थीं।

आपटा स्टेशन पर कई महत्त्वपूर्ण फिल्मों की शूटिंग की गई है, जिनमें दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है, रंग दे बसंती, बागी, खाकी, शादी नंबर 1, चाइना टाउन और कई अन्य बॉक्स-ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई हैं।

मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री शिवाजी सुतार ने बताया कि आपटा एक तरफ पहाड़ी के साथ अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है, दूसरी तरफ एक सड़क के पास एक नदी और आसान सड़क पहुंच है, जो पनवेल-रोहा मार्ग पर घुमावदार ट्रैक और प्लेटफॉर्मों के साथ स्थित है। उपकरणों को रखने और अभिनेताओं की वैनिटी वैन को पार्क करने के लिए पर्याप्त स्थान है तथा कम भीड़ वाला ऐसा स्टेशन फिल्म की शूटिंग के लिए एक सही लोकेशन है। आपटा रेलवे स्टेशन पर कुछ ट्रेनों के लिए ठहराव दिया गया है। यह क्रॉसिंग स्टेशन है क्योंकि इसमें एक अतिरिक्त ट्रैक भी है जो फिल्म शूटिंग के लिए बुक की गई विशेष ट्रेनों की आवाजाही के लिए दोगुना लाभ पहुंचाता है। आपटा स्टेशन फिल्म सिटी, मुंबई से लगभग 75 किमी की दूरी पर है जहाँ पहुँचने में सिर्फ 2 घंटे लगते हैं। इन कारणों से आपटा रेलवे स्टेशन वेब सीरीज, डॉक्युमेंट्रीज, और टीवी सीरियल्स की फिल्म शूटिंग के लिए पसंदीदा लोकेशन बन गया है।

मध्य रेल को फिल्म निर्माताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले कई खूबसूरत फिल्म शूटिंग लोकेशन उपहार में मिले हैं। सबसे पसंदीदा फिल्म शूटिंग लोकेशन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से लेकर आपटा, पनवेल, चौक, लोनावला, खंडाला, वठार, सतारा जैसे लोकप्रिय स्टेशन और तुर्भे और वाडी बंदर जैसे प्रसिद्ध यार्ड हैं। ■

मध्य रेल के जनसंपर्क विभाग द्वारा फिल्म की शूटिंग की अनुमति दी जाती है। हाल ही में फिल्म की शूटिंग की अनुमति में तेजी लाने के लिए सिंगल विंडो प्रणाली शुरू की गई है। इस प्रक्रिया के सरलीकरण से फिल्म कंपनियों को आवेदन प्रस्तुत करने के बाद अनुमति प्राप्त करने में आसानी हुई है। आवश्यकताओं का उल्लेख करते हुए स्क्रिप्ट और एप्लिकेशन के साथ आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं।

मध्य रेल में वर्ष 2019-20 के दौरान 21 फिल्मों की शूटिंग हुई, जिससे 1.33 करोड़ की आमदनी हुई। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस स्टेशन में फिल्म 'पंगा' सहित 21 फिल्मों की शूटिंग हुई, जिससे 44.52 लाख रुपये की तथा आपटा में 4 फिल्मों की शूटिंग से 22.61 लाख रुपये की आय हुई। पनवेल स्टेशन पर रजनीकांत अभिनीत फिल्म 'दरबार' की शूटिंग से सबसे अधिक 22.10 लाख रुपये की आय हुई। पुणे मंडल में सुंदर स्थान वठार में सलमान की 'दबंग-3' सहित 3 फिल्मों की शूटिंग हुई जिनसे 37.22 लाख रुपये की कमाई हुई। केवल 'दबंग-3' से 15.70 लाख रुपये की आय हुई।, पुणे से मुंबई के बीच फिल्म 'लाल सिंह चड्ढा' का एक शॉट और अन्य फिल्म शूटिंग स्थानों जैसे कि तुर्भे और वाडी बंदर यार्ड, पुणे स्टेशन से भी अच्छी आय उत्पन्न हुई है।

राष्ट्रपति ने विशिष्ट सेवा हेतु आरपीएफ कर्मी को पुलिस पदक से सम्मानित किया

स्वतंत्रता दिवस, 2020 के अवसर पर राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविन्द ने निम्नलिखित आरपीएफ/आरपीएसएफ कर्मियों को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति के पुलिस पदक और सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया :

विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक

श्री डी.बी. कसार, प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त, दक्षिण-पूर्व रेलवे

सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक

- श्री संतोष एन. चंद्रन, डीआईजी, आरएंडटी, रेलवे बोर्ड
- श्री राजेंद्र रूपनवार, वरिष्ठ डीएससी, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे
- सुश्री सारिका मोहन, वरिष्ठ डीएससी, उत्तर रेलवे
- श्री शैक करीमुल्लाह, सहायक सुरक्षा आयुक्त, दक्षिण मध्य रेलवे
- श्री हिमांशु शेखर झा, सहायक सुरक्षा आयुक्त, रेलवे बोर्ड
- श्री गुरजसबीर सिंह, सहायक सुरक्षा आयुक्त, उत्तर रेलवे
- श्री नेपाल सिंह गुर्जर, उप-निरीक्षक, 2 बीएन आरपीएसएफ
- श्री एबी रशीद लोन, इंस्पेक्टर, 6 बीएन आरपीएसएफ
- श्री एम. मोहम्मद रफी, हेड कांस्टेबल, दक्षिण पश्चिम रेलवे
- श्री शैलेश कुमार, निरीक्षक/उत्तर रेलवे
- श्री सुधेंदु बिस्वास, सहायक उप निरीक्षक, पूर्वी रेलवे
- श्री कवल सिंह, उप निरीक्षक, 2 बीएन आरपीएसएफ
- श्री के. वेंकटेश्वरलु, निरीक्षक, दक्षिण मध्य रेलवे
- श्री अशरफ सिद्दीकी, निरीक्षक, पूर्वोत्तर रेलवे
- श्री सुरेन्द्र कुमार, सहायक उप-निरीक्षक, उत्तर रेलवे ■

राष्ट्रपति द्वारा आरपीएफ के तीन जवान 'जीवन रक्षा पदक' से सम्मानित



सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक
(मरणोपरांत)
स्वर्गीय श्री जगबीर सिंह,
कांस्टेबल, उत्तर रेलवे

स्वर्गीय श्री जगबीर सिंह ने आदर्शनगर-आजादपुर रेलवे सेक्शन दिल्ली के नजदीक अपनी ड्यूटी के दौरान रेलवे परिसर में 4 बच्चों की जान बचाते हुए अपनी जान दे दी। अदम्य वीरता का परिचय देते हुए उन्होंने खुद की परवाह किए बिना इन बच्चों की जान बचाई।



उत्तम जीवन रक्षा पदक
श्री शिवचरण सिंह,
कांस्टेबल, पश्चिम रेलवे

श्री शिवचरण सिंह ने 10 अगस्त, 2019 को ट्रेन संख्या 12959 में ट्रेन की पहरेदारी करते हुए देखा कि जब ट्रेन श्यामखयाली रेलवे स्टेशन के पास पटरियों पर जलभराव के कारण रुकी तो भारी बाढ़ में फंसने के कारण कुछ लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे। श्री शिवचरण सिंह अपनी जान की परवाह किए बिना उनकी मदद के लिए पहुंचे और 09 व्यक्तियों का बहुमूल्य जीवन बचाया।



उत्तम जीवन रक्षा पदक
श्री मुकेश कुमार मीणा,
हेड कांस्टेबल, उत्तर पश्चिम रेलवे

हेड कांस्टेबल/आरपीएफ/जोधपुर डिवीजन के श्री मुकेश कुमार मीणा ने 16 सितम्बर, 2018 को ट्रेन संख्या 22478 में पहरेदारी के दौरान 02 बच्चों के साथ एक महिला यात्री की जान बचाने में अनुकरणीय साहस प्रदर्शित किया। श्री मुकेश मीणा ने दौड़ती ट्रेन से छलांग लगाई और महिला यात्री को उनके दोनों बच्चों के साथ प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच के अंतर से बाहर निकाला।

आरपीएफ महानिदेशक बने यूआईसी उपाध्यक्ष



96वीं यूआईसी महासभा ने जुलाई 2020 से लेकर जुलाई 2022 तक के लिए सुरक्षा मंच के उपाध्यक्ष के रूप में आरपीएफ महानिदेशक श्री अरुण कुमार को मनोनीत किया गया है। उसके बाद, श्री अरुण कुमार जुलाई 2022 से लेकर जुलाई 2024 तक सुरक्षा मंच के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करेंगे। इसकी जानकारी यूआईसी के महानिदेशक, श्री फ्रैंकोइस डेवने ने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष, श्री विनोद कुमार यादव को दी।

यूआईसी (यूनियन इंटरनेशनेल देस शिमन्स) एक फ्रेंच शब्द है, जिसका अर्थ अंग्रेजी में 'इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे' है। इसका मुख्यालय पेरिस में है।

यूआईसी सुरक्षा मंच को, व्यक्तियों, संपत्ति और प्रतिष्ठानों की सुरक्षा से संबंधित मामलों में रेलवे की ओर से विश्लेषण करने और नीतिगत दृष्टिकोण विकसित करने और निर्माण करने का अधिकार प्राप्त है। यह सुरक्षा मंच यूआईसी सदस्यों की सुरक्षा एजेंसियों के बीच सूचनाओं और विचारों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देता है और सदस्यों या बाहरी गतिविधियों की आवश्यकता के अनुसार रेलवे सुरक्षा के क्षेत्र में साझा हितों वाली परियोजनाओं और गतिविधियों को प्रस्तावित करता है। यूआईसी सुरक्षा मंच द्वारा वर्तमान महामारी के दौरान कोविड-19 के लिए गठित टास्क फोर्स, विचारों का आदान-प्रदान करने, सावधानियों को अपनाने, पूर्वावस्था की प्राप्ति के प्रयासों और अनुभवों को साझा करने की दिशा में बहुत ही उपयोगी साबित हुआ है।

आरपीएफ, भारतीय रेल की ओर से, हमेशा ही यूआईसी सुरक्षा मंच का एक सक्रिय सदस्य रहा है और लंबे समय से विचार-विमर्श, मंत्रणा, विचारों का आदान-प्रदान और सर्वोत्तम प्रथाओं के लिए योगदान देता रहा है। इसने 2006 और 2015 में, नई दिल्ली में यूआईसी सुरक्षा सम्मेलनों का आयोजन भी किया है। आरपीएफ अपने आप को कार्य समूहों, मंचों और बैठकों में शामिल करता रहा है और यूआईसी सुरक्षा मंच के कामकाज में इसके योगदान को ध्यान में रखते हुए यूआईसी के नेतृत्व द्वारा इसकी लंबे समय से सराहना की जा रही है। ■

83 महिला आरपीएफ सब-इंस्पेक्टर कैडेट्स का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण



विभिन्न जोनल रेलवे से संबंधित 83 महिला सब-इंस्पेक्टर कैडेट्स (बैच नंबर 9ए) की पासिंग आउट परेड 10 अगस्त, 2020 को रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के प्रशिक्षण केंद्र, मौला-अली में आयोजित की गई।

सुश्री चंचल शेखावत को 'बेस्ट कैडेट' एवं 'इंडोर में सर्वश्रेष्ठ' और सुश्री स्मृति बिश्वास को 'बेस्ट इन आउटडोर' चुना गया। परेड की कमान सुश्री चंचल शेखावत ने संभाली।

इस अवसर पर श्री गजानन माल्या, महाप्रबंधक, दक्षिण मध्य रेलवे ने महिला सब-इंस्पेक्टरों को रेलवे की संपत्ति और रेल यात्रियों की सुरक्षा के लिए पूरे समर्पण भाव के साथ काम करने और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि समाज के कमजोर तबकों, महिलाओं एवं बच्चों का ध्यान रखने पर विशेष फोकस करना चाहिए क्योंकि महिलाओं एवं बच्चों की तस्करी बढ़ती जा रही है। उन्होंने युवा कैडेट्स के उज्ज्वल भविष्य की कामना की और उल्लेखनीय कार्य- प्रदर्शन के लिए महिला एसआई कैडेट्स को बधाई भी दी तथा इसके साथ ही यह मंगल कामना की कि वे अत्यंत प्रोफेशनल ढंग से एवं करुणा भाव के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करेंगी। इन सब-इंस्पेक्टर कैडेट्स को रेलवे में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए इंडोर और आउटडोर विषयों में 9 महीनों तक कठोर प्रशिक्षण दिया गया है और अंतिम परीक्षा पास करने के बाद आज उन्होंने इस अत्यंत आकर्षक परेड में भाग लिया और शपथ लेने के बाद वे रेलवे सुरक्षा बल की सदस्य बन गई हैं। यह परेड कोविड-19 से संबंधित सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के साथ-साथ सामाजिक दूरी बनाए रखने के नियम का पालन करते हुए आयोजित की गई। ■

भारतीय रेल ने सुरक्षा के लिए ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किया

ड्रोन निगरानी तकनीक सीमित जनशक्ति वाले व्यापक क्षेत्रों में सुरक्षा निगरानी के मामले में एक महत्त्वपूर्ण और लागत प्रभावी उपकरण के रूप में उभरी है। भारतीय रेल में मध्य रेल के मुंबई मंडल ने हाल ही में रेलवे परिसर, रेलवे ट्रैक सेक्शन, यार्ड, वर्कशॉप आदि जैसे रेलवे क्षेत्रों में बेहतर सुरक्षा और निगरानी के लिए 2 निंजा यूएवी खरीदे हैं।

आरपीएफ, मुंबई के 4 कर्मचारियों की एक टीम को ड्रोन उड़ान, निगरानी और रखरखाव के लिए प्रशिक्षित किया गया है। ये ड्रोन रियल टाइम ट्रैकिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग में सक्षम हैं और इन्हें ऑटोमैटिक फेल सेफ मोड पर संचालित किया जा सकता है।

आरपीएफ ने रेलवे सुरक्षा के उद्देश्य से ड्रोन के व्यापक उपयोग की योजना बनाई है। 31.87 लाख रुपये की लागत से अब तक आरपीएफ द्वारा दक्षिण पूर्व रेलवे, मध्य रेल, आधुनिक कोचिंग फैक्टरी, रायबरेली और दक्षिण पश्चिम रेलवे के लिए 9 ड्रोन खरीदे गए हैं।

भविष्य में 97.52 लाख रुपये की लागत से सत्रह 17 और ड्रोन की खरीद प्रस्तावित है। 19 आरपीएफ कर्मियों को अब तक ड्रोन के संचालन और रखरखाव का प्रशिक्षण दिया गया है, जिसमें से 4 ने ड्रोन उड़ाने के लिए लाइसेंस प्राप्त किया है। 6 और आरपीएफ कर्मियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है।

ड्रोन की तैनाती का उद्देश्य तैनात सुरक्षा कर्मियों की प्रभावशीलता में वृद्धि और उन्हें सहायता प्रदान करना है। यह

- ड्रोन की तैनाती का उद्देश्य तैनात सुरक्षा कर्मियों की प्रभावशीलता में वृद्धि करना और उन्हें सहायता प्रदान करना है
- मध्य रेल के मुंबई मंडल ने हाल ही में रेलवे क्षेत्रों में बेहतर सुरक्षा और निगरानी के लिए 2 निंजा यूएवी खरीदे
- आरपीएफ द्वारा अब तक 9 ड्रोन खरीदे जा चुके हैं

रेलवे की संपत्ति और यार्ड, कार्यशालाओं, कार शेड आदि में सुरक्षा की देखरेख करने में मदद कर सकता है। इसका उपयोग रेलवे परिसर में आपराधिक और असामाजिक गतिविधियों, जैसे जुआ खेलने, कचरा फेंकने और फेरी लगाने वालों आदि पर निगरानी रखने के लिए भी किया जा सकता है। इन्हें डेटा संग्रह के लिए भी तैनात किया जा सकता है। एकत्रित किए गए डेटा का विश्लेषण गाड़ियों के सुरक्षित संचालन के लिए भी बेहद उपयोगी साबित हो सकता है।

ड्रोन को आपदा स्थलों पर विभिन्न एजेंसियों के प्रयासों में समन्वय के लिए राहत और बचाव कार्यों, रिकवरी और पुनर्निर्माण जैसी सेवाओं के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। रेलवे संपत्ति पर अतिक्रमण का आकलन करने के लिए रेलवे संपत्ति की मैपिंग करते समय भी यह बहुत उपयोगी हैं। व्यापक स्तर पर भीड़ प्रबंधन प्रयासों के दौरान, यह लोगों के एकत्रित होने के संभावित समय और संख्या जैसी महत्त्वपूर्ण जानकारी दे सकता है, जिसके आधार पर भीड़ को नियंत्रित करने के प्रयासों की योजना बनाई और निष्पादित की जा सकती है। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान प्रवासियों की आवाजाही को रोकने और निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था।

एक ड्रोन कैमरा इतने बड़े क्षेत्र को कवर कर सकता है जिसके लिए 8-10 आरपीएफ कर्मियों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार, यह सीमित जनशक्ति के उपयोग में पर्याप्त सुधार ला सकता है। ड्रोन निगरानी को रेलवे की संपत्ति, क्षेत्र की संवेदनशीलता, अपराधियों की गतिविधि आदि के आधार पर तैयार किया गया है। इससे पूरे क्षेत्र की निगरानी के माध्यम से अपराधी की सीधी गिरफ्तारी के लिए निकट की आरपीएफ पोस्ट को सूचित किया जाता है। ऐसे ही एक अपराधी को वाडीबंदर यार्ड क्षेत्र में वास्तविक समय के आधार पर पकड़ा गया था जबकि वह यार्ड में खड़े रेलवे कोच के अंदर चोरी करने की कोशिश कर रहा था। ■



मध्य रेल में ड्रोन द्वारा निगरानी की तस्वीर

डीसी को नई एसी बिजली लाइन में बदलने की रोचक जानकारी

श्री विमलेश चन्द्र



एसी सप्लाई प्रणाली युक्त उपनगरीय रैक

भारतीय रेल विविधताओं से भरी हुई है। जिस तरह से इसमें अनेकों तरह के गेज प्रणाली और अनेकों तरह कि रेल गाडियाँ संचालित हैं, उसी तरह भारतीय रेल में विद्युतीकरण के भी कई प्रकार रहे हैं। भारतीय रेल में विद्युतीकरण के कई प्रकार के साथ साथ एक रोचक बात यह है कि मुंबई में जहां से पहली बिजली वाली रेलगाड़ी चली थी, वहाँ पुरानी संरचना पर नए प्रकार के विद्युतीकरण का कार्य बहुत ही चुनौती भरा और रोचक रहा है।

1500 वोल्ट डी.सी. संकर्षण प्रणाली

जैसा कि हम जानते हैं कि भारत एवं एशिया की प्रथम बिजली रेलगाड़ी 03 फरवरी 1925 को तत्कालीन जी.आई.पी. रेलवे द्वारा मुम्बई वी.टी. और कुर्ला हार्बर के बीच चलाई गई थी। यह 1,500 वोल्ट डी.सी. संकर्षण प्रणाली वाली बिजली लाइन थी। इसका उद्घाटन मुम्बई के तत्कालीन गवर्नर सर लेसली आर्म विल्सन ने किया था। इसी तरह भारत की दूसरी बिजली रेलगाड़ी, उपनगरीय रेलगाड़ी के रूप में तत्कालीन बी.बी. एंड सी.आई.आर. द्वारा 05 जनवरी, 1928 को कोलाबा और बोरीविली के बीच चलाई गई थी। यह भी 1,500 वोल्ट डी.सी. संकर्षण प्रणाली वाली बिजली लाइन थी। इसके बोरीविली-विरार खंड को वर्ष 1936 में पूरा किया गया था। मध्य रेल में कल्याण से दो दिशा में रेल लाइन जाती हैं। पहला कल्याण-इगतपुरी रेलवे लाइन और दूसरा कल्याण-पुणे रेलवे लाइन। कल्याण-इगतपुरी खंड को वर्ष 1929 में 1,500 वोल्ट डीसी प्रणाली से शुरू किया गया था जबकि इगतपुरी से आगे भुसावल तक 25 केवी ए.सी. संकर्षण प्रणाली को 1967-69 के बीच बनाया गया था। इसी प्रकार कल्याण-पुणे रेलवे लाइन को वर्ष 1930 में 1,500 वोल्ट डीसी प्रणाली से शुरू किया गया था।

1,500 वोल्ट डी.सी. संकर्षण प्रणाली मीटर गेज

इसी तरह भारत में प्रथम और एक मात्र मीटर गेज वाली बिजली रेलगाड़ी दक्षिण रेलवे में मद्रास (चेन्नै) बीच और ताम्बरम् के बीच 2 अप्रैल 1931 को चलाई गई थी। यह भी 1,500 वोल्ट डी.सी. संकर्षण प्रणाली वाली लाइन थी। इसका उद्घाटन सर जॉर्ज एफ. स्टेनली ने किया था। जिसे 11 मई को जन सामान्य के लिए खोला गया था। इसे जनवरी 1967 में 25 केवी एसी में बदल दिया गया था तथा वर्ष 2004 में गेज परिवर्तन के कारण 30 जून, 2004 को इसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया।

3,000 वोल्ट डी.सी. संकर्षण प्रणाली

भारतीय रेल में 3,000 वोल्ट डीसी वाली संकर्षण प्रणाली भी प्रचलित थी। 3,000 वोल्ट डीसी संकर्षण प्रणाली वाली प्रथम उपनगरीय रेल सेवा हावड़ा और शिओरापल्ली के बीच 14 दिसम्बर, 1957 को शुरू की गई थी। जबकि इस प्रकार का लंबा और मेन रूट खंड सर्वप्रथम वर्ष 1958 में पूर्व रेलवे के



डीसी एसी पर चलने वाला बिजली इंजन



उपनगरीय गाड़ी का पुराना डी.सी. रेक

हावड़ा-बर्दवान खंड में शुरू किया गया था। पूर्व और दक्षिण पूर्व रेलवे में स्थापित 3,000 वोल्ट डी. सी. संकर्षण प्रणाली को वर्ष 1966 से 1968 के बीच 25 केवी ए.सी. संकर्षण प्रणाली में बदल दिया गया था।

750 वोल्ट डी.सी. संकर्षण प्रणाली

इसी प्रकार भारतीय रेल में सर्वप्रथम 750 वोल्ट डीसी संकर्षण प्रणाली 24 अक्टूबर, 1984 को मेट्रो रेलवे, कोलकाता में शुरू की गई थी। यह थर्ड रेल प्रणाली वाली बिजली संकर्षण प्रणाली है। इसे थर्ड रेल प्रणाली इसलिए कहते हैं क्योंकि रेल लाइन के पास से ही एक और लाइन जाती है, जिसमें बिजली रहती है, जो इस गाड़ी को बिजली प्रदान करती है। भारत में शुरू हुई यह इस प्रकार बिद्युतीकरण की पहली प्रणाली है।

25 केवी ए.सी. संकर्षण प्रणाली

वर्ष 1957 में निर्णय लिया गया कि देश में अब केवल 25 केवी ए.सी. सिंगल फेज प्रणाली रेलवे संकर्षण के लिए उपयोग की जाएगी। इसे अपनाने के बाद 15 दिसम्बर, 1959 को भारतीय रेल में सबसे पहले दक्षिण पूर्व रेलवे में 25 केवी ए.सी. प्रणाली राजखरसोवा-डोंगोंपोसी खंड में शुरू की गई थी, जबकि 25 केवी डीसी संकर्षण प्रणाली वाली प्रथम उपनगरीय रेल सेवा कोलकाता में सितंबर 1962 को शुरू हुई थी। 25 केवी ए.सी. संकर्षण प्रणाली की महत्त्वपूर्ण घटना में चारों महानगरों के बीच ट्रंक रूट का बिद्युतीकरण शामिल है। 7 जनवरी, 1977 को पूर्व और उत्तर रेलवे के ट्रंक रूट मतलब दिल्ली-हावड़ा रूट को 25 केवी ए.सी. संकर्षण प्रणाली में बिद्युतीकरण करके चालू किया गया, जबकि 31 मार्च, 1987 को उत्तर, मध्य तथा पश्चिम रेलवे के ट्रंक रूट मतलब दिल्ली-मुंबई (प.रे.) रूट को 25 केवी ए.सी. संकर्षण प्रणाली में बिद्युतीकरण करके चालू किया गया। इसी प्रकार 31 मार्च, 1991 को पूर्व, दक्षिण-पूर्व तथा मध्य रेल के हावड़ा-मुंबई ट्रंक रूट को 25 केवी ए.सी. संकर्षण प्रणाली में बिद्युतीकरण करके चालू किया गया, जबकि 31 मार्च, 1991 को उत्तर मध्य, दक्षिण मध्य तथा दक्षिण रेलवे के दिल्ली-चेन्नई ट्रंक रूट को 25 केवी ए.सी. संकर्षण प्रणाली में बिद्युतीकरण करके चालू किया गया था। भारतीय रेल में फरवरी 1994 में मध्य और दक्षिण पूर्व रेलवे के बीना-कटनी तथा कटनी-अनूपपुर-विश्रामपुर-चिरमिरी खंड में भारतीय रेल में सर्वप्रथम 2x25 केवी ए.सी. संकर्षण प्रणाली शुरू करके एक नया इतिहास रचा गया था।

1,500 वोल्ट डी.सी. और 25 केवी ए.सी. संकर्षण वाली दोहरी प्रणाली

यह एक ऐसी प्रणाली शुरू की गई थी, जिसमें संकर्षण प्रणाली को बदलने की बजाय रेलगाड़ी के इंजन को 1,500 वोल्ट डी.सी. पर और 25 केवी ए.सी. पर चलाने के लिए उपयुक्त बनाया गया। मतलब, ऐसा बिजली इंजन और ऐसा उपनगरीय रेलगाड़ी का रैक बनाया गया जो इस दोनों प्रकार के बिजली सप्लाई पर चलने के लिए बिना किसी रुकावट के चलने के लिए उपयुक्त थे। मेन लाइन पर चलने वाली रेलगाड़ियों के लिए ए.सी./डी.सी. इंजन को चिरेका और भेल ने बनाया था। चिरेका ने 30 जनवरी, 1975 को पहली बार 1,500 वोल्ट डी.सी. और 25 केवी ए.सी. संकर्षण पर कार्य करने वाले बिजली इंजन का निर्माण करके पश्चिम रेलवे को सौंपा था, जिसका नाम बल्लभ था। इसी के साथ दोनों रेलवे में मतलब पश्चिम रेलवे और मध्य रेल में इस प्रकार के इंजन मिलने शुरू हो गए। इस तरह के इंजन के कारण बिजली संकर्षण चेजिंग पॉइंट पर इंजन बदलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। इस तरह यह मेन लाइन पर चलने वाले इंजन संकर्षण बदलाव तक चलते रहे और अब ये इंजन स्वभाविक रूप से केवल 25 केवी ए.सी. सप्लाई से चल रहे हैं।

भारतीय रेल की सर्वप्रथम ए.सी./डी.सी. उपनगरीय रेल सेवा पश्चिम रेलवे द्वारा 12 जून, 2001 को चर्चगेट-विरार के बीच चलाई गई थी। अब 1,500 वोल्ट डी.सी. प्रणाली बंद हो गई है तो स्वाभाविक रूप से ऐसे इंजन और रैक बनने भी बंद हो गए हैं।

1,500 वोल्ट डी.सी. संकर्षण प्रणाली को 25 केवी ए.सी. संकर्षण प्रणाली में बदलना

भारतीय रेल में 1500 वोल्ट डीसी प्रणाली 4 खंडों में कार्यरत थी। पहला, मध्य रेल के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से कल्याण तक उपनगरीय खंड और इससे जुड़े खंड। दूसरा, मध्य रेल के कल्याण-इगतपुरी खंड में और तीसरा कल्याण-पुणे। चौथा खंड पश्चिम रेलवे में चर्चगेट-विरार खंड था। इन सभी में इगतपुरी, पुणे और विरार में डी.सी. प्रणाली को ए.सी. प्रणाली से विशेष प्रणाली से जोड़ा गया था अर्थात् यहाँ पर 1,500 वोल्ट डी. सी. संकर्षण प्रणाली का और 25 केवी ए.सी. संकर्षण प्रणाली का इंटरचेंज पॉइंट स्थापित था।



सीमेंस का एसी सप्लाई प्रणाली वाला उपनगरीय रैक

मुंबई में पश्चिम रेलवे तथा मध्य रेल में चल रही 1,500 वोल्ट डीसी प्रणाली को 25 केवी एसी में बदलने का निर्णय वर्ष 1996-97 में लिया गया था, जिसमें पश्चिम रेलवे में चर्चगेट से विरार तक के रेल खंड को 1,500 वोल्ट डी. सी. संकर्षण प्रणाली से 25 केवी ए.सी. संकर्षण प्रणाली में बदलने का कार्य 3 फेज में किया गया। पहले फेज में जून 2003 में बोरीवली-विरार खंड को बदला गया। फिर दूसरे फेज में अंधेरी-बोरीबिली और तीसरे फेज में चर्चगेट-अंधेरी खंड को बदला गया था। इस तरह से पूरा खंड 04 फरवरी, 2012 को 25 केवी ए.सी. संकर्षण प्रणाली से चालू कर दिया गया था।

इस तरह पहला खंड वसई-जसई था और अंतिम खंड हार्बर लाइन था। इस तरह से यह बिजली लाइन 441 रुट किमी और 1,681 ट्रैक किमी लंबी थी। 3 फरवरी, 1925 को मुंबई वीटी से कुर्ला तक जो प्रथम बिजली रेलगाड़ी चली थी। उसके प्रथम संचालन के 91 वर्ष बाद डीसी सप्लाई से चलने वाली मेन लाइन की अंतिम लोकल ट्रेन 07 जून, 2015 को चली थी जबकि ब्रांच लाइन में अंतिम डीसी लोकल ट्रेन लगभग एक वर्ष बाद 9 अप्रैल, 2016 को चली थी। और इसी के साथ ही एक युग का अंत हो गया था।

बहुत चुनौतीपूर्ण रहा डीसी को एसी में बदलने का कार्य

पुराने बिजली लाइन (डीसी) को नए बिजली लाइन (एसी) में बदलने का कार्य बहुत आश्चर्य चकित करने वाला था। जो लोग रेलवे संकर्षण प्रणाली के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं उन्हें पता है कि 1,500 वोल्ट डी. सी. संकर्षण प्रणाली और 25 केवी ए.सी. संकर्षण प्रणाली में बहुत अंतर होता है। केवल सप्लाई की नहीं बल्कि बिजली के वायर, पोल या पिलर, ग्रिड या पॉवर सप्लाई स्टेशन, इंसुलेटर, पिलर हाइट, स्पान इत्यादि में भी, लेकिन जब इगतपुरी, कसारा, कल्याण, पुणे और मुंबई के उपनगरीय स्टेशन मुंबई सेंट्रल, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, चर्चगेट, दादर, बोरीविली इत्यादि स्टेशनों पर इसको कन्वर्ट करने का कार्यक्रम बना होगा तो सचमुच में उस समय के बिजली इंजीनियरों को बहुत सोच-विचार करना पड़ा होगा। कारण वही कि इन दोनों के सिस्टम में बहुत अंतर होता है। इनमें एक और बड़ा कारण था। पहले से जो फुट ओवर ब्रिज बने थे या फिर और जो भी फिटिंग्स कम ऊँचाई पर थीं, वे भी 25 केवी ए.सी. संकर्षण प्रणाली के लिए रुकावट बन रही थीं, क्योंकि 25 केवी ए.सी. संकर्षण प्रणाली के पिलर की ऊँचाई ज्यादा रहती है, जो इन नई संरचनाओं की सीध में आती थीं। आखिर गाड़ियों के संचालन में बिना कोई रुकावट किए इसे बदलने के लिए कैसे लक्ष्य दिया गया होगा? लेकिन भारतीय रेल के इंजीनियर क्या नहीं कर सकते हैं? आखिर में बिना किसी रुकावट के वे सफलता पूर्वक अपना कार्य पूरा कैसे कर लिए होंगे? ये बहुत



डीसी से एसी में बदली हुई बिजली लाइन



नागपुर डायमंड क्रॉसिंग के ऊपर जटिल बिजली की लाइनें

इसी तरह मध्य रेल में चल रही 1500 वोल्ट डीसी प्रणाली को 25 केवी एसी में बदलने का कार्य कई चरणों में पूरा हुआ, जिसका विवरण इस प्रकार है।

1) वसई-दिवा-पनवेल-जसई 29 जनवरी, 2003,
2) पनवेल-कर्जत 12 मार्च, 2004,
3) इगतपुरी-कसारा 19 फरवरी, 2006,
4) कसारा-टिटवाला 12 नवम्बर, 2006,
5) टिटवाला-कल्याण और कल्याण यार्ड 03 मई, 2009,
6) कल्याण-दिवा (पांचवीं और छठी लाइन) 03 मई, 2009,
7) पुणे-लोनावाला 10 दिसंबर, 2009
7) लोनावाला-कर्जत-खपोली 02 मई, 2010,
8) कर्जत-बांगनी 02 मई, 2010,
9) बिजली इंजन शेड कल्याण 07 जून, 2010,
10) कल्याण-बागनी 24 अक्टूबर, 2010
11) कल्याण डाउन यार्ड 15 अप्रैल, 2011
12) कल्याण-ठाणे, ठाणे-लोकमान्य तिलक टर्मिनल 12 जनवरी, 2014,
13) ठाणे-कुर्ला-छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल 8 जून, 2015,
14) ठाणे-तुर्भे-वाशी-नेरुल मार्च 2016,
15) तिलकनगर-पनवेल मार्च 2016,
16) तिलकनगर-छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल मार्च 2016,
12) हार्बर लाइन 10 अप्रैल 2016 को एसी संकर्षण से चालू हुई थी।

सारी बातें सोचने वाली हैं। नए संरचना में मतलब 25 केवी ए.सी. संकर्षण प्रणाली में इन्होंने फुट ओवर ब्रिज और अन्य संरचना के नीचे से कांटेक्ट वायर लाई गई और जहाँ ओपन एरिया मिला वहां वायर ऊपर ली गई। मतलब, एकदम नजदीक में ऊँचाई पर भी और तुरंत कम ऊँचाई भी वायर लगाकर इंजीनियरों ने इस प्रकार का पहला काम किया। इस प्रकार की सेटिंग मुम्बई में भी हैं। इससे कोई ज्यादा तोड़फोड़ भी नहीं करनी पड़ी और ज्यादा पिलर या स्पान भी नहीं लगाना पड़ा। मतलब, कुछ नई और कुछ पुरानी संरचना को उपयोग करके एक बेहतर संरचना प्रदान करते हुए यहाँ बिजली सप्लाई सिस्टम को बदल कर एक रिकार्ड कायम किया गया। इसी प्रकार 25 केवी ए.सी. संकर्षण प्रणाली में पतली वायर लगती है तो भी कई स्थान पर मतलब पुणे या इगतपुरी इत्यादि में 25 केवी ए.सी. संकर्षण प्रणाली में काफी मोटी और काली वायर लगाई गई। यहाँ केवल 60% संरचना को खराब कंडीशन के बेस पर बदला गया। बाकी 40% पुरानी संरचना वही के वही उपयोग में ली गई हैं। मतलब, मजबूत और लम्बी आयु वाली संरचना को बेहतर तरीके से उपयोग किया गया। सबसे अलग और आश्चर्य वाली बात यह कि इसका कांटेक्ट वायर काफी पुराना और प्योर कापर है। इसलिए यह मोटा और काला है। यदि आप भी कभी पुणे या इगतपुरी या अन्य स्टेशन पर रुकें तो रेल लाइन के ऊपर बनी बिजली लाइन और इनकी सभी संरचना पर जरूर नजर दौड़ाईएगा। अन्य जगहों की तुलना में यहाँ की बिजली लाइन जरूर कुछ अलग मिलेगी। सबसे रोचक बात यह कि इसे बदलने का कार्य सप्ताह के अंत में रात्रि में किया जाता था, जिससे किसी गाड़ी के संचालन पर अवरोध उत्पन्न नहीं होता था। यदि पुरानी प्रणाली को पूरी तरह से निकाल कर नये सिरे से नई प्रणाली लगाते तो स्वाभाविक रूप से इसे बदलने में कई दशक लग जाते। ■

सहायक मंडल यांत्रिक इंजीनियर

भारतीय रेल और 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार आश्वासन योजना' का सम्मिलन

श्री प्रथम अग्रवाल

भारतीय रेल और 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार आश्वासन योजना' के सम्मिलन के संबंध में नीति निर्देश रेल मंत्रालय द्वारा पिछले पाँच वर्षों में, 2013 से 2018 के दौरान जारी किए गए हैं। दक्षिण मध्य रेलवे के ओंगोल उप मण्डल ने इस योजना के कार्यान्वयन के लिए अभूतपूर्व पहल की। लगातार प्रयासों के माध्यम से 24 नवम्बर, 2018 को एक नई नीति तैयार की गई, जिसमें 9 प्रकार के कार्यों की पहचान की गई, जो रेलवे के अधिकार क्षेत्र में किए जा सकते हैं। ये कार्य इस प्रकार हैं :-

1. पुल, पाइप पुलिया, बॉक्स पुलिया, आरयूबी के पानी निकास में जमा मिट्टी निकालना।
2. रेलवे के तटबंध को मजबूत बनाना और चौड़ा करना।
3. रेलवे सीमा के साथ नाली की खुदाई।
4. खुले कुओं में जमा मिट्टी की सफाई।
5. चालू नलकूपों/सूखे हुए नलकूपों के ढांचों को ठीक करना।
6. ब्लॉक वृक्षारोपण।
7. रेल कॉलोनियों में विलेज पार्क (उद्यान)।
8. रैखिक वृक्षारोपण।
9. सड़कों को लेवल क्रॉसिंग से बिटुमेन सतह तक जोड़ना। (90:10)

वर्तमान में 4 प्रकार के निर्माण कार्य (S.No. 1 से 4) प्रगति पर हैं। इन कार्यों के लिए अभी तक 40.73 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है और आज तक 2.38 करोड़ रुपये के कार्य प्रगति पर हैं। 92.11 लाख रुपये का काम पूरा हो चुका है। उसी की कुछ तस्वीरें संलग्न हैं -

आंध्र प्रदेश की मुख्य वेबसाइट - http://www.nrega.ap.gov.in/Nregs/(आंध्र प्रदेश राज्य के लिए NREGA की आधिकारिक वेबसाइट जो, TCS द्वारा प्रबंधित की जा रही है) में रेलवे परियोजना का एक विशेष शीर्षक बनाया गया है।

इस सम्मिलन योजना के तहत स्वीकृत, चल रहे और पूरे हो चुके कार्यों की सूची नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से देखी जा सकती है। इस बात का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि MGNREGS के तहत निगरानी प्रणाली ऑनलाइन है जो निगरानी को पारदर्शी और आसान बनाती है।

http://www.nrega.ap.gov.in/Nregs/FrontServlet? request-Type = AssetregRH&actionVal= WorkCatergory&id=Railway%2Project$&type=&Atype=-1

इस योजना की क्षमता काफी अधिक है तथा इसी वित्त वर्ष में 600 करोड़ रुपये की स्वीकृति की आशा है। ऊपर सूचीबद्ध सभी कार्य रख-रखाव प्रकृति के हैं। जैसे ही ये कार्य स्वीकृत होते हैं, रेलवे के धन को पूंजीगत संपत्ति निर्माण के लिए उपयोग में लाया जा सकता है।

इसके अलावा, वृक्षारोपण और ऊपर सूचीबद्ध अन्य निर्माण कार्यों पर राज्य सरकार द्वारा रेलवे की तुलना में बेहतर तरीके से कार्रवाई की जाती है क्योंकि यह उनकी मुख्य गतिविधियों में आता है, जैसे MGNREGS के तहत वृक्षारोपण नीति में वृक्षों का





3 साल की रख-रखाव अवधि और 80% वृक्षों के जीवित रहने जैसी शर्तों का प्रावधान है। वृक्षों में नियमित रूप से पानी डालने और मवेशियों से इन्हें बचाने के लिए चौकीदार की तैनाती की जाती है। उपर्युक्त नीति-निर्देशों का पूरी गंभीरता के साथ पालन किया जाता है। संबधित राज्य और वन विभाग के परामर्श से पौधों की ऐसी प्रजातियों को चुना गया है, जिन्हें परिपक्वता के बाद काटा जा सकता है और रेलवे को गैर-किराया राजस्व प्राप्त हो सकता है। इसके लिए स्थानीय लुगदी और कागज उद्योग के साथ चर्चा की गई हैं और उनके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने की कार्रवाई चल रही है।

इसी तरह, रेलवे सीमा के साथ नाली बनाने से पशुओं के रेलगाड़ी के नीचे आने की घटनाओं को कम करने में सहायता मिलेगी। ये नालियाँ वर्षा जल संचयन गड्ढों के रूप में भी काम करेंगी। रेलवे की सीमा के निकट खेतों को इसका लाभ होगा जिसपर किसानों ने खुशी जताई है। उनका विश्वास जीतने के बाद, ADEN@OGL सब डिवीजन में 7 लेवल क्रॉसिंग्स को बंद करने की प्रक्रिया को बल मिला है।



ओंगोल सब डिवीजन में कुछ निर्माण कार्यों के लिए आंशिक रूप से MGNREGS और आंशिक रूप से केंद्र प्रायोजित योजना के माध्यम से निधि की व्यवस्था की कोशिश की गई, जो सफल हुई, जैसे सिंगरायाकोंडा स्टेशन तक सीमेंट कंक्रीट मार्ग का निर्माण कराया गया जिसमें मजदूरों की लागत का MGNREGS के तहत और सामग्री लागत का रुर्बन (एक केंद्रीय प्रायोजित योजना) के तहत प्रबंध किया गया। इसी प्रकार, ओंगोल सब डिवीजन में आने वाले 2 स्टेशनों पर सार्वजनिक शौचालय और एप्रोच रोड स्ट्रीट लाइटिंग का निर्माण भी कराया गया।

आंध्र प्रदेश में रेलवे के अलावा 23 और विभाग हैं जो MGNREGS की निधि का उपयोग कर कार्य करते हैं। आंध्र प्रदेश राज्य के लिए MGNREGS के तहत पिछले साल का बजट रु. 10,000 करोड़ के करीब था। हमारा लक्ष्य इस निधि में से एक बड़ा हिस्सा रेलवे के लिए प्राप्त करना है और इसके लिए हमने कार्य-स्थलीय सुविधाओं को मजबूत करने के लिए निम्न कार्य हाथ में लिए हैं -

1. ओंगोल सब डिवीजन क्षेत्र में आने वाले सभी समपार फाटकों (38) और स्टेशनों (9) पर शौचालयों की व्यवस्था करना।
2. ओंगोल सब डिवीजन क्षेत्र में आने वाले सभी समपार फाटकों (38) और स्टेशनों (9) पर पानी की सुविधा उपलब्ध कराना।
3. ओंगोल सब डिवीजन क्षेत्र में आने वाले सभी समपार फाटकों (38) और स्टेशनों (9) पर ओआरएस (ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन) सहित प्रथमोपचार सुरक्षा किट बॉक्स उपलब्ध कराना।

इस कार्य का आकलन इस तथ्य से किया जा सकता है कि उपरोक्त सभी सुविधाएं शुरू में हर 10 किमी पर मौजूद थीं, जिन्हें मैं हर 1.5 किमी पर लाने में कामयाब रहा। इससे इस तरह की बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धि और आसान हो गई है। सभी कामगारों के साथ-साथ जिला प्रशासन द्वारा हमारे काम की व्यापक सराहना की गई है और ओंगोल सब डिवीजन क्षेत्र में एक स्वस्थ वातावरण तैयार हुआ है, जिसमें कार्यों की गुणवत्ता में सुधार और कार्य निष्पादन में गति लाना संभव हुआ है।

ऊपर दी गई तस्वीरें जियो टैग की गई हैं जो ओंगोल सब डिवीजन के कार्यों की दैनिक प्रगति को प्रदर्शित करती हैं। ■

अधिशासी अभियंता, मध्य रेल, अहमद नगर

विशेष पार्सल रेलगाड़ी को बांग्लादेश भेजा

भारतीय रेल ने पहली बार बांग्लादेश के बेनापोल के लिए आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के रेड्डीपलेम से सूखी मिर्च की एक विशेष मालगाड़ी से ढुलाई की।

आंध्र प्रदेश के गुंटूर और इसके आस-पास के इलाके की मिर्च की गुणवत्ता को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है। इससे पहले, सूखी मिर्च सड़क मार्ग से बांग्लादेश ले जाई जाती थी। लॉकडाउन अवधि के दौरान वे सड़क मार्ग से इस आवश्यक वस्तु को नहीं ले जा सके। तब रेलवे अधिकारियों ने उन्हें रेल से माल ले जाने की सुविधाओं के बारे में विस्तार से समझाया। लेकिन मालगाड़ी से सामान भेजने के लिए प्रत्येक खेप में कम-से-कम 1,500 टन से अधिक माल का इंतजाम करना होता। इस समस्या को कम करने के लिए दक्षिण मध्य रेलवे के गुंटूर मंडल ने पहल की। तदनुसार, 16 पार्सल वैन से युक्त एक विशेष पार्सल एक्सप्रेस मालगाड़ी बांग्लादेश के बेनापोल गई। प्रत्येक पार्सल वैन में सूखी मिर्च का वजन लगभग 19.9 टन था। इस प्रकार विशेष पार्सल एक्सप्रेस मालगाड़ी द्वारा कुल 384 टन वजन का सामान ले जाया गया। विशेष पार्सल एक्सप्रेस द्वारा माल ले जाने की लागत प्रति टन 4,608 रुपये आई जो सड़क परिवहन के 7,000 रुपये प्रति टन की तुलना में बहुत सस्ती और किफायती है। ■



पूर्वोत्तर रेलवे के इज्जतनगर मण्डल द्वारा बांग्लादेश के लिए मिनी-ट्रकों की लोडिंग

पूर्वोतर रेलवे के इज्जतनगर मंडल ने 27 जुलाई, 2020 को 51 टाटा एस मिनी ट्रकों को रेल परिवहन के माध्यम से बांग्लादेश भेजकर परिवहन क्षेत्र में एक नया आयाम स्थापित किया है। यह महत्त्वपूर्ण उपलब्धि परिणाम है, नवगठित बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट (बी.डी.यू.) टीम के द्वारा किए गए प्रयासों का। अभी तक बांग्लादेश में टाटा एस कार्गो भेजने का कार्य टाटा मोटर्स द्वारा सड़क मार्ग से किया जाता था। रेलवे जहां एक ओर संरक्षित एवं तीव्र परिवहन सुविधा उपलब्ध करा रही है, वहीं दूसरी ओर निर्यात को भी बढ़ावा दे रही है।



बी.डी.यू. टीम के आक्रामक विपणन (अग्रेसिव मार्केटिंग) प्रयासों तथा पूर्वोत्तर रेलवे मुख्यालय एवं रेलवे बोर्ड के समेकित समन्वय के फलस्वरूप इज्जतनगर मंडल को सड़क परिवहन से यह माल परिवहन रेल प्रणाली पर लाने में सफलता मिली है। इज्जतनगर मंडल के हल्दी रोड स्टेशन से बांग्लादेश के बेनापोल स्टेशन के लिए 51 टाटा एस मिनी ट्रकों के पहले कंसाइनमेंट को भेजा गया है।

इस व्यापार से न केवल बांग्लादेश के साथ भारत के आर्थिक संबंध मजबूत होंगे, अपितु भारतीय अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा। भारतीय रेल न केवल टाटा मोटर्स को सुरक्षित तथा तीव्र गति की परिवहन प्रणाली उपलब्ध करा रही है बल्कि इसके साथ वह भारत सरकार के हरित अर्थव्यवस्था (ग्रीन इकोनामी) अभियान में भी सहयोग कर रही है, क्योंकि सड़क परिवहन की तुलना में रेल परिवहन में बहुत कम कार्बन उत्सर्जन होता है।

ज्ञातव्य है कि भारतीय रेल द्वारा वर्ष 2024 तक माल लदान को दोगुना करने के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु समेकित प्रयासों के अन्तर्गत पारंपरिक माल लदान के साथ ही अन्य माल के लदान को रेल परिवहन की ओर आकर्षित करने के लिए आक्रामक विपणन नीति (अग्रेसिव मार्केटिंग) अपनाई गई है। विभिन्न व्यापार समूहों एवं उद्योगों से सम्बद्ध व्यापारियों के साथ नियमित समन्वय बनाये रखने तथा उन्हें रेल प्रशासन द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में अवगत कराने के लिए क्षेत्रीय रेल के मुख्यालयों एवं मण्डलों में उच्चस्तरीय बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट का गठन किया गया है। रेलवे बोर्ड में कार्यकारी निदेशक स्तर की गठित उच्चस्तरीय बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट, क्षेत्रीय रेलों का मार्गदर्शन करने के साथ ही भेजे गए प्रस्तावों पर एक सप्ताह के भीतर उचित निर्णय ले रही है। इस विपणन नीति के लागू होने के फलस्वरूप जहाँ भारतीय रेल पर माल लदान में वृद्धि हो रही है, वहीं उद्योग जगत् को भी पर्याप्त लाभ हो रहा है। रेल परिवहन प्रणाली की अपनी विश्वसनीयता है। सुगम, सुलभ एवं तीव्र माल परिवहन सुनिश्चित करने हेतु मालगाड़ियों की गति में वृद्धि तथा मालभाड़ा में दी जा रही रियायतें व्यापारियों के लिए उपयोगी साबित हो रही हैं। व्यापारियों की दिक्कतों का तत्काल निवारण हो जाने से वे स्वाभाविक रूप से रेल के माध्यम से माल भेजने एवं मंगाने में अपना हित सुरक्षित पा रहे हैं। ■

मध्य रेल ने मुंबई उपनगरीय प्रणाली के चौथे कॉरिडोर खारकोपर-उरण मेजर इंफ्रा प्रोजेक्ट को गति दी



मध्य रेल ने इस लॉकडाउन और अनलॉक अवधि के बीच कई इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को पूरा करने हेतु गति दी है। इनमें से एक प्रमुख इंफ्रा प्रोजेक्ट है, 27 किलोमीटर का 'बेलापुर-सीवुड-उरण' प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट की शेष लाइन, जो कि 14.60 किमी की खारकोपर-उरण लाइन है, को गति प्रदान की गई है। इस पूरी लाइन के पूरा होने से मुंबई-उरण के बीच की समय/दूरी लगभग 40% से 50% तक कम हो जाएगी।

मध्य रेल के निर्माण विभाग द्वारा परियोजना को गति देने से रेलवे को मुंबई से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक के इस महत्त्वपूर्ण रेल मार्ग को पूरा करने में मदद मिल रही है।

खारकोपर-उरण खंड में मशीनों की सहायता, जैसे पाइल बोरिंग मशीन, कंक्रीट प्लाजर बूम, ट्रांजिट मिक्सर, ट्रिपर्स, जेसीबी, हाइड्रस, पॉक्लेन्स, हाइड्रोलिक जैक आदि से विभिन्न निर्माण संबंधी गतिविधियां तेज की गईं हैं। रांजनपाड़ा स्टेशन पर कवर ओवर प्लेटफॉर्म का कार्य, न्हावा-शेवा, द्रोणागिरि और उरण स्टेशनों में नींव और सब-स्ट्रक्चर का कार्य, उरण में सब-वे, और चैनेज 10,975 पुलों की नींव का कार्य और 7,982 पुलों पर यू-गर्डर की स्ट्रेसिंग और लोअरिंग आदि कार्य शामिल हैं।

खारकोपर-उरण परियोजना में प्रमुखता से 5 स्टेशन, 2 प्रमुख पुल, 41 छोटे पुल, 2 रोड अंडर ब्रिज और 4 रोड ओवर ब्रिज होंगे। यह निर्माण कार्य उपलब्ध श्रमिकों द्वारा उनकी पूरी सुरक्षा और हेल्थ प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सावधानीपूर्वक सुनिश्चित किया जा रहा है।

लॉकडाउन / अनलॉक अवधि और मानसून की बारिश के कारण बाधित कार्य उपलब्ध अंतराल पर निष्पादित कर, निर्माण गतिविधियों को और तेजी से किया जा रहा है। 4.479 हेक्टेयर भूमि (अधिकतम फारेस्ट लैंड) चैनेज 8 किमी से चैनेज 11 किमी के बीच की भूमि को सिडको द्वारा रेलवे को हैंडओवर किया जाना अभी बाकी है।

बेलापुर - सीवुड्स - उरण रेलवे लाइन, जो मध्य रेल मुंबई उपनगरीय नेटवर्क का चौथा कॉरिडोर है, के पूरा होने से मुंबई से जेएनपीटी और उरण तक यात्रियों की यात्रा में आसानी व उनके समय में बचत होगी। इसके साथ ही, यात्रियों को नवी मुंबई में नए हवाई अड्डे तक पहुँचने में भी सुविधा होगी। ■

किफायती और पर्यावरण हितैषी सोलर और विंड रिनुएबल एनर्जी की ओर मध्य रेल के बढ़ते हुए कदम

मध्य रेल पर्यावरण अनुकूल नवीकरणीय ऊर्जा, जैसे कि सौर और पवन ऊर्जा के लिए ओपन एक्सेस और नेट मीटरिंग के माध्यम से बड़े पैमाने पर आगे बढ़ रही है ताकि वर्ष 2030 तक रेल मंत्रालय की नीति का पूरी तरह से पालन करके ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए, कार्बन फुटप्रिंट को कम करके और जलवायु परिवर्तन कर ऊर्जा की लागत को कम किया जा सके। मध्य रेल रूफटॉप कॉन्फिगरेशन के साथ-साथ भूमि आधारित सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, दोनों के लिए आगे बढ़ रही है।



रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र

मध्य रेल ने अपने 5 मंडलों और 4 कारखानों में फैली 14.379 MWp (मेगावॉट पीक) क्षमता को एकत्रित करने वाली रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्रों की योजना बनाई है। उसमें से, 4.92 MWp स्थापित किया गया है और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई, पुणे आदि और विभिन्न ईएमयू कार शेड, कार्यशालाओं और प्रशासनिक / सेवा भवनों सहित विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफॉर्मों पर कवर ओवर शेड पर कमीशन किया गया है। इससे प्रति वर्ष 6.4 मिलियन यूनिट ऊर्जा का उत्पादन होता है। परिणामस्वरूप 4.1 करोड़ रुपये प्रति वर्ष की बचत हो रही है। बाकी सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापना के विभिन्न चरणों में हैं, जो चालू होने पर 12.43 एमयू का उत्पादन करेंगे जोकि प्रति वर्ष 7.37 करोड़ रुपये की बचत में तब्दील हो जाएगा।

भूमि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र

ट्रैकसाइड भूमि और अन्य विभिन्न खाली परिसरों का उपयोग करने के लिए मध्य रेल ने खाली ट्रैकसाइड स्ट्रेच के साथ-साथ भूमि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए अनुपयोगी भूमि की पहचान की है, जो ट्रैक्शन उद्देश्य के लिए 109 MWp की क्षमता को एकत्रित करता है। इन सौर ऊर्जा संयंत्रों से प्रति वर्ष 143 मिलियन यूनिट ऊर्जा उत्पन्न होगी। इससे ऊर्जा बिल में प्रति वर्ष 43 करोड़ रुपये की बचत होगी। इसी प्रकार, गैर-कर्षण प्रयोजनों के लिए विभिन्न परिसरों में रिक्त भूमि पार्सल की पहचान की गई है, जिस पर कुल 71 मेगावॉट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्रों की योजना बनाई गई है, जो प्रति वर्ष 93 मिलियन यूनिट ऊर्जा का उत्पादन करेंगे और प्रति वर्ष 64 करोड़ रुपये की बचत होगी। इस प्रकार प्रति वर्ष ऊर्जा बिलों में कुल बचत 107 करोड़ की होगी।

पवन ऊर्जा

पवन ऊर्जा डेवलपर्स के साथ पॉवर खरीद समझौते (पीपीए) के माध्यम से अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, पवन ऊर्जा को भी मैसर्स रेलवे एनर्जी मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के तत्वावधान में लगाया गया है। कर्षण प्रयोजनों के लिए सांगली में 50.4 मेगावॉट की पवन चक्कियों को स्थापित किया गया है, जबकि पवन चक्कियों को एकत्र करने वाले 6 Mw पवन चक्कियों को गैर-कर्षण प्रयोजनों के लिए स्थापित किया गया है।

उत्पन्न ऊर्जा को ओपन एक्सेस नियमों के तहत् मध्य रेल के ड्रॉवल पॉइंट्स में वितरित किया जाता है। इसमें पॉवर ग्रिड के किसी भी बिंदु पर पॉवर को इंजेक्ट किया जाता है और पॉवर ट्रांसमिशन यूटिलिटीज को व्हीलिंग चार्ज का भुगतान करके ड्रॉ के किसी अन्य बिंदु पर खींचा जाता है। अब तक, 67.76 मिलियन यूनिट ऊर्जा प्राप्त हुई है, जिससे 39 करोड़ रुपये की बचत हुई है। 2020-21 में कमीशन के उपरांत गैर-कर्षण के लिए, 6 मेगावॉट की क्षमता के लिए पवन ऊर्जा डेवलपर्स के साथ हस्ताक्षरित पीपीए से लगभग 4.2 करोड़ रुपये की वार्षिक, की बचत होगी।

मध्य रेल द्वारा एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट की उपलब्धि

मध्य रेल ने ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी (बीईई) 'नेशनल एनर्जी फॉर एनहांसमेंट एनर्जी एफिशिएंसी' के तहत 2019 में PAT-II साइकिल (प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार) के दौरान ट्रेन संचालन में ऊर्जा दक्षता द्वारा 2019 में एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स प्राप्त किए हैं। मध्य रेल ने अन्य क्षेत्रीय रेलों की प्रतिस्पर्धा में द्वितीय सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है।

पीएटी योजना देश में विशिष्ट ऊर्जा प्रोत्साहन उद्योगों के बीच ऊर्जा की खपत को कम करने और बढ़ी हुई ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए बीईई द्वारा एक कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस योजना के तहत् विशिष्ट ऊर्जा खपत में कटौती, बचत लक्ष्यों को 3 साल के चक्र के लिए नामित उपभोक्ताओं को सौंपा गया है। एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट को 2 ऊर्जा एक्सचेंजों पर कारोबार किया जा सकता है जोकि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज और पॉवर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड हैं या PAT के तहत् अन्य इकाइयों द्वारा खरीदे जाते हैं जो उनकी अनुपालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। ■

मध्य रेल की परेल कार्यशाला में विकसित की गई मेडी-बॉट जीवक

मध्य रेल के महाप्रबंधक श्री संजीव मित्तल ने दिनांक 25 अगस्त, 2020 को छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, मुंबई में मेडी-बॉट जीवक का ई-उद्घाटन किया। इस अवसर पर सभी प्रधान विभागाध्यक्ष और पांचों मंडलों के मंडल रेल प्रबंधक डिजिटल माध्यम से उपस्थित थे।

मध्य रेल की परेल कार्यशाला ने शुरू से ही कोविड 19 के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व किया है। इस कार्यशाला ने कोविड योद्धाओं की सहायता के लिए मास्क, पीपीई किट, कवरऑल, सेनेटाइजर, ऑक्सीजन ट्रॉली का निर्माण कर प्रदान किया है तथा रेलवे कोच को कोविड आइसोलेशन कोच में भी बदलने का कार्य भी किया है। श्री संजीव मित्तल, महाप्रबंधक, मध्य रेल के नेतृत्व में कोविड योद्धाओं को बेहतर सुविधाएँ और प्रेरणा प्रदान करने के अपने प्रयास में इस कारखाने ने वर्तमान कोविड-19 महामारी में उपयोग के लिए मेडिकल रोबोट को डिजाइन और संकल्पित किया है।

श्री ए.के. गुप्ता, प्रधान मुख्य यांत्रिक इंजीनियर एवं श्री बी.एम. अग्रवाल मुख्य कारखाना इंजीनियर के मार्गदर्शन में श्री विवेक आचार्य, मुख्य कारखाना प्रबंधक, परेल कार्यशाला की टीम ने इसको डिजाइन किया है। यह कोविड-19 रोगियों की देखभाल के लिए बनाया गया है और कोविड-19 रोगियों के लिए स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के संपर्क को कम करेगा। जीवक, रिमोट-नियंत्रित मरीजों के बेड पर जाने के लिए एक चिह्नित लाइन का अनुसरण कर सकता है। यह मरीजों की देखभाल और रक्तचाप की निगरानी, ऑक्सीजन संतृप्ति स्तर, शरीर के तापमान आदि से संबंधित विभिन्न गतिविधियों को करने के लिए वर्चुअल हेल्थकेयर कार्यकर्ता के रूप में काम करता है।

जीवक में रोगी का दोतरफा संचार और वीडियो कवरेज होता है। डॉक्टर रोगी से बात कर सकते हैं और रोगी को स्क्रीन पर देखकर एक आभासी जाँच कर सकते हैं। रोगी की आभासी जांच से डॉक्टर और पैरामेडिक स्टाफ के संपर्क में काफी कमी आएगी। मरीज को नियमित दवा देने के लिए जीवक में एक दवा का डिब्बा भी है। एक बार जब पूरी जाँच हो जाती है और रोगी को दवा दी जाती है, तो जीवक को कीटाणु शोधन के लिए उसके डेक पर वापस बुलाया जाएगा और फिर अगले रोगी के लिए यह अपने आप तैयार हो जाएगा।



ड्रोनस्टार्क और बीजीएन मेडेक्स (इंडिया) लिमिटेड प्राइवेट के सहयोग से परेल कार्यशाला ने इस जीवक की अवधारणा और डिजाइन किया है। परेल कार्यशाला ने मेडी-बोट जीवक भारत रत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मेमोरियल रेलवे अस्पताल भायखला को सुपुर्द कर दिया है, जिसका लाभ इस अस्पताल के डाक्टर एवं मरीजों को भली-भांति मिल रहा है। ■

छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस में फुट ऑपरेटेड हैंडवॉश मशीन



मध्य रेल, मुंबई मंडल और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने व्यक्तिगत स्वच्छता को सक्षम करने के लिए एक संयुक्त पहल के तहत दिनांक 25 अगस्त, 2020 को छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई में फुट ऑपरेटेड हैंडवॉश वेंडिंग मशीन (FHVM) स्थापित की है। यह मशीन कोविड-19 महामारी के दौरान यात्रियों के लिए संपर्क रहित लिक्विड हैंडवॉश और पानी को अलग-अलग डिस्पैंस करती है।

सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए, एक मशीन में 4 स्टेशन होते हैं, जिसमें 4 व्यक्ति एक साथ एक समय में अपने हाथ धो सकते हैं। इस मशीन को छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई के प्लेटफॉर्म नंबर-14 पर लगाया गया है। ■

दिल्ली क्षेत्र के लिए 'मच्छर मार' विशेष रेलगाड़ी चलाई गई

उत्तर रेलवे ने दिल्ली क्षेत्र में रेल पटरियों के किनारे मच्छरों को पनपने से रोकने के लिए 28 अगस्त से नई दिल्ली से एक बार फिर 'मॉस्किटो टर्मिनेटर ऑन व्हील्स' मच्छर मार विशेष रेलगाड़ी चलाई गयी। उत्तर रेलवे एवं उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबन्धक, श्री राजीव चौधरी ने बताया कि यह रेलगाड़ी प्रत्येक फेरे में लगभग 75 किलोमीटर की दूरी तय करेगी । रेल पटरियों के किनारे बने गड्ढों एवं एकत्रित पानी में मच्छरों को पनपने से रोकने, उन्हें नियंत्रित करने तथा रेल पटरियों के किनारों पर रहने वाले लोगों की स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह मच्छर मार विशेष रेलगाड़ी चलाई गई है।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा उपलब्ध कराए गए एक ट्रक को रेलगाड़ी के खुले डिब्बे (डीबीकेएम) पर लोड किया गया है। ट्रक पर मच्छर मार दवाई छिड़कने का संयंत्र लगा है जो 50 से 60 मीटर की दूरी तक छिड़काव करने में सक्षम है। यह रेलगाड़ी संलग्न कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 2 अक्टूबर, 2020 तक हजरत निजामुद्दीन, लाजपत नगर, सेवा नगर, लोधी कालोनी, दिल्ली सफदरजंग, बराड़ स्कवायर, इंद्रपुरी, मायापुरी, पटेल नगर, दयाबस्ती, दिल्ली किशनगंज, सदर बाजार, दिल्ली शाहदरा और नई दिल्ली तथा अन्य इलाकों से होकर गुजरेगी। मच्छरों को पनपने से रोकने के लिए प्रति सप्ताह मच्छर मार दवाई का



मॉस्किटो टर्मिनेटर ऑन व्हील्स

छिड़काव किया जाएगा। 5 सप्ताहों में कुल 10 राउंड छिड़काव किया जाएगा। कोरोना महामारी की अवधि के दौरान इन छिड़कावों से मच्छरों को पनपने और फैलने पर अंकुश लगेगा। इस कार्य के दौरान कर्मचारियों द्वारा कोरोना महामारी से बचाव संबंधित सभी सावधानियां अर्थात् सामाजिक दूरी इत्यादि का पालन भी किया जाएगा। ■

उत्तर मध्य रेलवे ने लॉकडाउन में बुनियादी ढांचे और रख-रखाव कार्य पूर्ण किए

उत्तर मध्य रेलवे ने कई महत्त्वपूर्ण रख-रखाव और बुनियादी ढांचे के विकास कार्यों को सफलतापूर्वक निष्पादित करने के लिए कोविड-19 की महामारी के कारण यात्री सेवाओं के निलंबन से प्राप्त अवसर का पूरी तरह से लाभ उठाया है।

पार्सल ट्रेनों और मालगाड़ियों के माध्यम से सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्तिश्रृंखला सुनिश्चित करने, श्रमिक और विशेष ट्रेनों के रूप में आवश्यक यात्री परिवहन के अलावा उत्तर मध्य रेलवे ने इन परियोजनाओं को नियमित यात्री सेवाओं के निलंबन के दौरान निष्पादित किया। यातायात ब्लॉक की अधिक आवश्यकता के कारण इनमें से बहुत से कार्यों को सामान्य समय पर करने से ट्रेन संचालन पर अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता।

संरक्षा कार्यों के अंतर्गत एक समपार को बंद किया गया, एक आरओबी और आरयूबी को कमीशन किया गया, आगरा मंडल के ईदगाह-बयाना खंड में समपार संख्या 32, 36, 58 और 59 की जगह सब-वे बनाया गया। सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा हेतु 46 समपारों पर ट्रेन अप्रोच हूटर प्रदान करने के साथ-साथ प्राथमिक बूम टूटने के मामले में 2 लेयरप्रोटेक्शन के रूप में 07 समपारों पर स्लाइडिंगबूम का प्रावधान किया गया।

मथुरा जं. पर प्लेटफॉर्म पर पूर्ण कवर शेड तथा प्लेटफॉर्म नं. 7 का उच्चीकरण, आगरा के बाड स्टेशन पर ऊंचा प्लेटफॉर्म, निवारी स्टेशन पर प्लेटफॉर्म उच्चीकरण और गोवर्धन स्टेशन का आदर्श स्टेशन के रूप में विकास तथा कानपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म-8/9 और ग्वालियर स्टेशन के प्लेटफॉर्म-1 पर एक-एक पैसेंजर लिफ्ट की स्थापना की गई। इस अवधि में ट्रेन परिचालन पर न्यूनतम प्रभाव डालते हुए ललितपुर यार्ड में कर्व संख्या-27 और खजुराहो यार्ड में गैर मानक क्रॉसओवर संख्या-201 ए और 201 बी में सुधार के द्वारा ट्रैक के ले-आउट को ठीक किया गया जो परिचालन में अति लाभदायक होगा।

सिग्नलिंग सिस्टम में सुधार हेतु आगरा मण्डल के अचाई -छाता-कोसी, झांसी मंडल में भीमसेन- रसूलपुर-गोगामऊ और प्रयागराज मंडल में छिपीयाना-मारीपत खंड में डुअलडिटेक्शन प्रणाली और अघोरी खास-चुर्क खंड में नील ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट के स्थान पर डाइडो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट की स्थापना महत्त्वपूर्ण कार्य हैं।

कानपुर-अनवर गंज में ड्राइवर रनिंग रूम, डीजल रनिंग रूम प्रयागराज, न्यूरनिंग रूम चुनार और मानिकपुर में गार्ड रनिंग रूम और कानपुर में गार्ड रनिंग रूम में एसी की व्यवस्था के साथ ही प्रयागराज मंडल के सभी 23 रनिंग रूम अब वातानुकूलित हैं। कोविड-19 के खिलाफ एहतियाती उपाय के रूप झांसी में नियंत्रण कक्ष में पहले से स्थापित केन्द्रीयकृत एसी प्लांट के स्थान पर विंडो / स्प्लिट एसी लगाया गया है। ■

प्रयागराज स्टेशन पर संपर्करहित टिकट जाँच

दिनांक 12 मई, 2020 से 30 एसी स्पेशल और दिनांक 01 जून, 2020 से 200 स्पेशल ट्रेनें शुरू की गई हैं, जिनमें से 26 एसी स्पेशल और प्रयागराज-नई दिल्ली तथा कानपुर-नई दिल्ली की 2 प्रारम्भिक स्पेशल सहित 100 अन्य स्पेशल ट्रेनों का उत्तर मध्य रेलवे के विभिन्न स्टेशनों पर ठहराव दिया गया है। कोविड-19 के मद्देनजर मानक व्यवस्थाओं के अलावा, उचित सामाजिक दूरी और न्यूनतम शारीरिक संपर्क के साथ यात्रियों के कुशल संचालन के लिए दिनांक 01.06.20 से प्रयागराज जंक्शन पर टिकट स्कैनिंग के लिए स्वचालित क्यूआर कोड आधारित एक प्रणाली पहले से ही लागू की जा चुकी है।

एक अनूठे प्रयोग के तहत प्रयागराज जंक्शन पर संपर्क रहित टिकट जाँच तथा एयरपोर्ट की तर्ज पर बोर्डिंग पास जारी करने की व्यवस्था लागू की गई है। स्टेशन के एंट्री गेट पर, टिकट चेकिंग स्टाफ और यात्रियों के बीच कांच के पृथक्करण के साथ 4 क्यूबिकल लगाए गए हैं। सूचना के आदान-प्रदान के लिए दोनों तरफ टीएफटी मॉनिटर लगाए गए हैं। क्यूआर कोड से टिकट चेक करने की व्यवस्था के अतिरिक्त यात्री की ओर वेब कैमरा स्थापित किया गया है, जो टिकट परीक्षक के पास उपलब्ध कंप्यूटर से जुड़ा है। इससे टिकट और पहचान पत्र की बिना शारीरिक संपर्क के जांच होती है। संचार हेतु ग्लास पार्टिशन के दोनों तरफ माइक्रोफोन और स्पीकर लगाए गए हैं।

यात्री की पहचान और टिकट की पुष्टि के बाद विवरण के साथ बोर्डिंग पास यात्री की तरफ प्रदान किए गए प्रिंटर से जारी किया जा रहा है। बोर्डिंग पास स्टेशन तथा ट्रेन में प्रवेश के लिए प्रधिकार पत्र का भी कार्य करता है यद्यपि टिकट और पहचान पत्र यात्री के पास उपलब्ध होने चाहिए। ऑन बोर्ड टिकट चेकिंग स्टाफ के पास उपलब्ध टैबलेट में इस प्रणाली से बोर्ड किए यात्रियों की जानकारी सॉफ्टवेयर के माध्यम से पहले से ही दर्ज रहती है। इस प्रणाली से किसी ट्रेन में खाली सीटों की पहचान भी सुगमता से हो जाती है। स्टेशन में प्रवेश के लिए इसे यात्रियों के लिए एकल जांच केंद्र बनाने के लिए थर्मल स्कैनिंग प्रक्रिया को भी इस प्रणाली में एकीकृत किया जा रहा है।



प्रयागराज स्टेशन पर संपर्क रहित टिकट जाँच प्रणाली

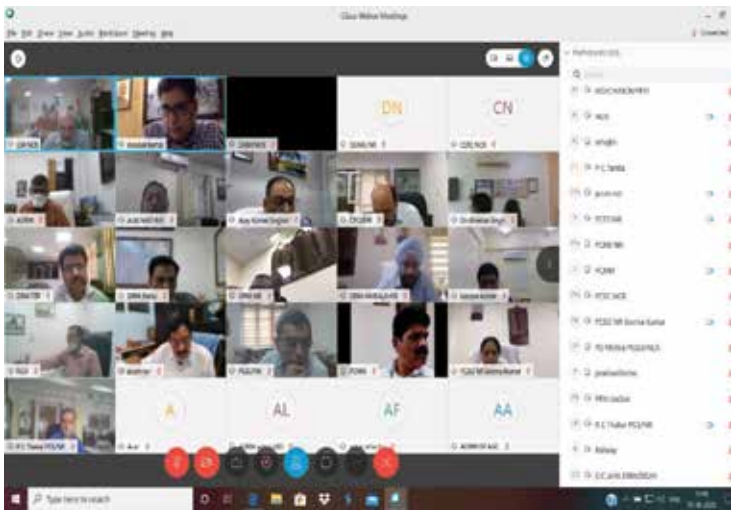
महाप्रबंधक ने इसके सफल कार्यान्वयन के लिए प्रयागराज मण्डल की टीम को बधाई दी है। मण्डल रेल प्रबंधक प्रयागराज श्री अमिताभ, सीनियर डीसीएम श्री अंशु पांडे और विभागीय टीम इस प्रणाली के प्रसार के लिए काम कर रही है। ■

उत्तर मध्य रेलवे के प्रमुख ग्राहकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई बैठक

उत्तर मध्य रेलवे वाणिज्य विभाग द्वारा महाप्रबंधक श्री राजीव चौधरी की अध्यक्षता में दिनांक 26 जून, 2020 को रेलवे के प्रमुख मालभाड़ा ग्राहकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक का आयोजन किया गया।

बैठक का मुख्य उद्देश्य रेल उपभोक्ताओं को लोडिंग/अनलोडिंग हेतु समुचित सुविधाएं प्रदान करने के साथ रेलवे की लोडिंग बढ़ाने हेतु मालभाड़ा ग्राहकों के सुझाव पर विस्तृत चर्चा करना था।

बैठक में रेल उपभोक्ता-आइओसी/बाद, एचपीटीआर/रसूलपुर, डीसीपीजी/पारीछा, एमजेएसी/चुनार, केएलपीएल/कानपुर, कानकोर, अल्ट्राटेक सीमेंट एवं पॉवर हाउस के प्रतिनिधि के साथ-साथ चेम्बर ऑफ कामर्स, कानपुर व प्रयागराज के प्रतिनिधियों ने तथा रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। ■



स्टेशनों पर सतर्कता रखने के अलावा साथी रेलकर्मियों के लिए फेस कवर की सिलाई

उत्तर मध्य रेलवे द्वारा कोविड-19 के खिलाफ चलाए गए अभियान में रेल सुरक्षा बल अग्रणी योगदानकर्ता रहा है। लॉकडाउन की शुरुआत में रेलवे सुरक्षा बल ने सभी खाली कोचिंग रेकों, 400 से अधिक स्टेशनों और अन्य रेलवे संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ रेलवे स्टेशनों के निकट 30,000 से अधिक असहाय और फंसे व्यक्तियों को नि:शुल्क भोजन भी उपलब्ध कराया। इसी क्रम में श्रमिक विशेष गाड़ियों में 16 बच्चों की सुरक्षित डिलीवरी में रेलवे डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की भी सहायता की।

उत्तर मध्य रेलवे परिक्षेत्र में 429 समय-सारणीबद्ध पार्सल ट्रेनों, खाली कोचिंग रेकों सहित 4,500 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की एस्कॉर्टिंग के वृहद् कार्य को संभालने के अतिरिक्त रेल सुरक्षा बल ने 138 प्रारम्भिक, 202 टर्मिनेटिंग और उत्तर मध्य रेलवे परिक्षेत्र में निर्धारित ठहराव वाली 70 श्रमिक विशेष गाड़ियों में स्टेशन पर डी-बोर्डिंग, बोर्डिंग, यात्रियों में सोशल डिस्टेनसिंग आदि कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाई है।

वातानुकूलित स्पेशल गाड़ियों और अन्य विशेष गाड़ियों के परिचालन प्रारम्भ होने के साथ उत्तर मध्य रेलवे में ठहराव वाली 126 स्पेशल गाड़ियों के लिए बल द्वारा ट्रेनों की एस्कॉर्टिंग और स्टेशनों पर होने वाली गतिविधियों का कुशलता से संचालन किया जा रहा है।

रेल सुरक्षा बल कर्मियों ने लॉकडाउन के दौरान सुरक्षा बल के परिवार के सदस्यों के लिए ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिताओं के आयोजन, रेलवे कॉलोनियों में कोरोना सम्बंधी विभिन्न जागरूकता अभियान, जिसमें भिक्षु का भेष बनाना इत्यादि सम्मिलित था तथा गीतों के माध्यम से मनोबल बढ़ाने के कार्यों आदि के सम्पादन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

उत्तर मध्य रेलवे के रेल सुरक्षा बल ने अपने अथक प्रयासों से न केवल अपने निर्धारित कर्तव्यों का निर्वहन किया है, बल्कि मानवीय दृष्टिकोण दिखाते हुए सभी का दिल भी जीता है जोकि रेल सुरक्षा बल के मिशन 'यशो लभस्व' को पूर्णत: सिद्ध करती है। ■

प्रयागराज मंडल ने गाड़ियों की शत-प्रतिशत समयपालनता की उपलब्धि हासिल की

उत्तर मध्य रेलवे ने वर्ष 2019-20 के दौरान समपार फाटकों पर संरक्षा से जुड़े कई महत्त्वपूर्ण कार्य पूरे किए और 'अंतरराष्ट्रीय समपार जागरूकता दिवस' के अवसर पर वर्ष 2020-21 में भी इसी गति से कार्य करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है।

उत्तर मध्य रेलवे के अति व्यस्ततम ट्रंक रूटों पर गाड़ियों के परिवहन से इन रूटों की क्षमता का लगभग 160% उपयोग किया जा रहा है, इसके बावजूद उत्तर मध्य रेलवे उन पर देश की सबसे तेज 160 किमी प्रति घंटे की गति से चलने वाली गाड़ी 'गतिमान एक्सप्रेस', भारतीय रेल की सबसे अधिक औसत गति वाली अर्थात् 104 किमी प्रति घंटे की औसत गति से चलने वाली वंदेभारत एक्सप्रेस गाड़ी सहित 100 से अधिक गाड़ियों का 130 किमी प्रति घंटे की गति से संचालन करती है, जो अपने आप में एक कीर्तिमान है।

प्रयागराज मण्डल ने दिनांक 10 जून, 2020 को सभी 65 ट्रेनों को सही समय पर चलाकर 100% समयबद्धता की एक असाधारण उपलब्धि हासिल की है और पूरे उत्तर मध्य रेलवे द्वारा कुल 93 ट्रेनों में से 92 ट्रेनों को समयपालनता के साथ चलाकर 98.92% समयबद्धता का रिकॉर्ड आंकड़ा प्राप्त किया गया।

उत्तर मध्य रेलवे ने संपत्ति के रखरखाव और गाड़ियों के संचालन में संतुलित और समग्र दृष्टिकोण के फलस्वरूप ही जून, 2020 में 90% से अधिक की उत्कृष्ट समयपालनता को बनाए रखा है, जिसमें आगरा, झांसी और प्रयागराज मण्डलों का महत्त्वपूर्ण योगदान है, जिनकी समयपालनता क्रमश: 96%, 93% और 87% है। महाप्रबंधक ने इस उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सामूहिक पुरस्कार भी स्वीकृत किया है।

प्रत्येक वर्ष 11 जून को 'अंतरराष्ट्रीय समपार जागरूकता दिवस' के रूप में मनाया जाता है। कोविड-19 के दृष्टिगत इस वर्ष सीमित गतिविधियां चलाई गईं।

लेवल क्रासिंग्स पर संरक्षा हेतु ब्रॉडगेज रेल नेटवर्क से मानव रहित लेवल क्रासिंग्स को पूरी तरह से हटाने के बाद, वर्ष 2019-20 में उत्तर मध्य रेलवे ने सड़क यातायात मार्ग के डायवर्जन के साथ-साथ 04 ऊपरी सड़क पुल और 60 आर.यू. बी (एलएचएस) का निर्माण कर 91 मानवयुक्त समपार फाटकों को बंद किया है। पिछले वित्त वर्ष के दौरान, अधिक ट्रैफिक वाले 20 लेवल क्रॉसिंग फाटकों को इंटरलॉक किया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि फाटकों के बंद होने के बाद ही गाड़ियों के सिग्नल आ पाएं, 153 गेटों पर एकनॉलेज्मेंट बटन का भी प्रावधान किया गया है ताकी कार्यरत स्टेशन मास्टर गेट के बंद होने की पुष्टि कर सकें तथा 56 गेटों पर दोहरे स्तर की सुरक्षा के रूप में स्लाइडिंग बूम लगाए गए हैं ताकि प्राथमिक बूम टूटने की स्थिति में इन्हें प्रयोग में लाया जा सके। वर्ष 2020-21 में, 20 ऊपरी सड़क पुल एवं 70 आरयूबी (LHS) के निर्माण, 11 फाटकों की इंटरलाकिंग और बूम टूटने की अधिक घटना वाले 67 क्रिटिकल लेवल क्रॉसिंग्स पर स्लाइडिंग बूम के प्रावधान का एक महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ■

उत्तर मध्य रेलवे ने रिलीज्ड कंक्रीट स्लीपरों से बाउंड्री वॉल का निर्माण प्रारम्भ किया

उत्तर मध्य रेलवे ने अनुपयोगी पीएससी स्लीपरों, जिन्हें रिसाइकल करना काफी खर्चीला एवं पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं है, से रेलवे ट्रैक के किनारे-किनारे बाउंड्री वॉल निर्माण हेतु ड्राइंग जारी की गई है, जिसके अनुसार आगरा-मथुरा खंड में 500 मीटर की बाउंड्री वॉल का निर्माण किया है और 1.5 किमी के एक और पैच पर काम चल रहा है। प्रयागराज मण्डल ने भी सूबेदारगंज स्टेशन पर लगभग 100 मीटर तक बाउंड्री वॉल का निर्माण किया है। इस योजना के बड़े पैमाने पर कार्यान्वयन से सभी मापदंडों पर मूल्यांकन किया जा रहा है। यह महत्त्वपूर्ण है क्योंकि गति बढ़ाने तथा ट्रैक के किनारे सौर संयंत्र स्थापित करने वाली सोलर पार्क एजेंसी द्वारा पीपीपी योजना के तहत भी बाउंड्रीवॉल का निर्माण सोलर परियोजना में प्रस्तावित है जबकि शेष बाउंड्री वॉल का निर्माण रेलवे द्वारा करना होगा। 11 अगस्त, 2020 को संरक्षा, लोडिंग और 160 किमी प्रति घंटे की गति बढ़ाने के कार्यों की समीक्षा के दौरान महाप्रबंधक ने इस पर बल भी दिया था।

समीक्षा में उन्होंने संरक्षा पर कहा कि प्रयागराज और आगरा मण्डलों को तकनीकी और अन्य सहायता प्रदान करने के लिए अपर महाप्रबंधक श्री रंजन यादव की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जाये और 2023-24 तक पूरी की जाने के लिए लक्षित महत्त्वाकांक्षी परियोजना की दैनिक प्रगति की निगरानी की जाए। विभिन्न संरक्षा अभियानों के अंतर्गत ट्रैक के



बगल के विभिन्न इंस्टालेशनों की रनिंग ट्रैक से ऊंचाई तथा दूरी की जांच हेतु एक संरक्षा ड्राइव चलाई गई है।

माल लदान प्रदर्शन की समीक्षा के दौरान महाप्रबंधक ने निर्देश दिया कि स्टेशन से स्टेशन रियायती दरों सहित अतिरिक्त लोड को हासिल करने के सभी प्रस्तावों को सर्वोच्च प्राथमिकता पर मंजूरी दी जानी चाहिए। बीडीयू को निर्देशित किया गया है कि वे वर्ष 2023-24 में 2024 मिलियन टन के लोडिंग लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अब तक किए गए कार्यों और भविष्य के रोड मैप को निर्धारित करें। ■

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे ने गतिरोधकों को हटाकर गति व सुरक्षा में बढ़ोत्तरी का प्रयास किया

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे ट्रेनों की अनुभागीय गति को बढ़ाने के लिए कई उपाय कर रही है। इसके लिए कमजोर अस्थाई एवं स्थाई गतिरोधकों को हटाया जा रहा है। इसके अलावा विभिन्न अनुभागों में लूप लाइनों के जरिए ट्रेनों के आवागमन की गति को बढ़ाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप यात्रा के पाबंद समय में सुधार के साथ ट्रेनों की गति में भी सर्वांगीण वृद्धि हुई है।

पू.सी. रेलवे के तिनसुकिया मंडल के अधीन 277.45 किमी अनुभागों में लूप लाइनों की गति में वृद्धि हुई है। इसमें 190.95 किमी लंबा फारकटिंग-सिमलुगुड़ी-श्रीपुरिया गांव अनुभाग शामिल हैं, जिसके अंतर्गत 19 स्टेशन आते हैं तथा 86.50 किमी लम्बा फारकटिंग-जोरहाट-मरियानी अनुभाग शामिल है, जिसके अंतर्गत 5 स्टेशन आते हैं। इस सुधार के परिणामस्वरूप ट्रेनें अब बढ़ी हुई गति के साथ इन स्टेशनों पर लूप लाइनों के जरिए गुजर सकती हैं और यात्रा के समय में कमी आएगी।

इसी तरह पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के विभिन्न प्रकार के सुधारात्मक कार्यों द्वारा लामडिंग मंडल के अधीन 65.20 किमी लंबे बराईग्राम-पेचारथाल अनुभाग तथा 20.27 किमी लंबे चंद्रनाथपुर-बदरपुर अनुभाग में ट्रेनों की अनुभागीय गति को 100 किमी प्रति घंटे तक बढ़ा दिया गया है। इससे यात्रा के समय में उल्लेखनीय कमी आएगी।

इसके अलावा लामडिंग मंडल के लामडिंग-फारकटिंग अनुभाग में जून के महीने के दौरान 1 स्थायी गति रोधक को हटाया गया है। इससे संबंधित हिस्से में ट्रेनों को वर्धित गति के साथ यात्रा करने में सहायता मिलेगी। ■



जल संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु कई स्थानों पर स्वचालित कोच वॉशिंग प्लांट स्थापित

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे क्षेत्र के कटिहार, न्यू जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी (डेमू), अलीपुरद्वार, नाहरलागुन, डिब्रूगढ़, सिलचर और अगरतला जैसे विभिन्न स्थानों में स्वचालित कोच वॉशिंग प्लांट की स्थापना प्रगति पर है। इससे 75 प्रतिशत से 80 प्रतिशत पानी को अन्य कार्यों में उपयोग के लिए रिसाइकिल भी किया जा सकता है। स्वचालित कोच धुलाई संयंत्र हाई प्रेशर वॉटर जेट, क्षैतिज एवं लम्बवत् रोटेटिंग नॉयलन कंबीनेशन ब्रशों के इस्तेमाल द्वारा कोचों व ट्रेनों के लिए एक बहु चरण बाहरी सफाई प्रणाली है। रखरखाव के लिए पिट लाइन में रेक को रखने पर यह कोच की संपूर्ण बाहरी सफाई करता है।

इस प्रणाली का मुख्य लाभ हैं-

- यह ईको-फ्रेंडली है क्योंकि सफाई के लिए कम पानी, कम बिजली और कम केमिकल(साबुन) की खपत करता है।
- सिस्टम को खोलने के लिए न्यूनतम विद्युत ऊर्जा, जनशक्ति और रखरखाव की आवश्यकता होती है।
- एक ट्रेन की बाहरी सफाई गतिविधि में जनशक्ति की आवश्यकता कम होती है।
- 24 डिब्बोंवाली ट्रेन रेक की उत्कृष्ट गुणवत्ता वाली बाहरी सफाई 10-15 मिनट की समय अवधि में पूरी हो जाती है।



स्वचालित कोच वॉशिंग प्लांट

- शौचालय के नीचे के क्षेत्र को साफ करने में सक्षम है जो अन्यथा मैन्युअल रूप से साफ नहीं किया जाता है।
- संपूर्ण प्रणाली उपयोग के अनुकूल, मजबूत बनाए रखने में आसान और किफायती है।
- इसमें गियर व छत की सफाई जैसी सुविधाएं भी हैं। न्यूनतम मानव इंटरफेस कोविड से लड़ने में भी सहायक है। ■

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे केन्द्रीय अस्पताल में बायो-मिथेन संयंत्र लगेगा

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के तहत भारतीय रेल को थोक अपशिष्ट उत्पादक के रुप में चिन्हित किया गया है तथा यह थोक अपशिष्ट उत्पादकों के दायित्वों को भी निर्धारित करता है। अपशिष्ट वर्गीकरण प्राथमिकता के क्रम में सबसे आगे है। इसके तहत रोकथाम, कटौती, दोबारा इस्तेमाल, पुन: प्राप्ति तथा निपटान पर बल देकर ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन किया जाना है। इसमें रोकथाम सबसे वरीयता प्राप्त विकल्प है तथा जमीन भरने के लिए निपटान सबसे आखिरी विकल्प है।

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे टर्मिनलों पर उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए पर्यावरण हितैषी प्रारूप में कई परियोजनाओं की शुरुआत की गई है। कामाख्या कोचिंग डिपो में यांत्रिक लॉन्ड्री में एक भट्टी की स्थापना की गई है। विभिन्न रेलवे प्रतिष्ठानों तथा कॉलोनियों में बड़ी मात्रा में बायो-डिग्रेडेबल अपशिष्ट की उत्पत्ति को ध्यान में रखते हुए गुवाहाटी एवं मालीगांव में बायो-डिजॉस्टर संयंत्रों की स्थापना की गई है।

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे केन्द्रीय अस्पताल, मालीगांव में एक बायो-मिथेनेशन संयंत्र की स्थापना की जा रही है तथा इसे यथाशीघ्र ही शुरू करने की योजना है।

अपशिष्ट तब तक अपशिष्ट नहीं है जब तक कि वह नष्ट न हो, इस धारणा को ध्यान में रखते हुए 'स्वच्छ भारत मिशन' की ओर योगदान देने तथा अपशिष्ट से ऊर्जा दोहन के मद्देनजर इस संयंत्र की स्थापना की जा रही है। प्रस्तावित अपशिष्ट संयंत्र की डिजाइन तथा संरचना सीएसआईआर-एनआईआईएसटी प्रौद्योगिकी के आधार पर किया गया है। इस प्रक्रिया का मूल मंत्र है, ड्राई डायजेशन। रिएक्टर टैंक में उच्च रुप से सक्रिय घनी माइक्रोबियल कल्चर (स्लज/गाद) यांत्रिक रुप से पीसे हुए अपशिष्ट के साथ मिल जाता है तथा अनुकूल बायो-मिथेनेशन प्रक्रिया के लिए पर्याप्त धारण समय प्रदान किया गया है। यह तेल तथा वसा, नींबू, प्याज के छिलकों, हड्डियों इत्यादि सहित किसी भी तरह के खाद्य अपशिष्ट को संसाधित करने में सक्षम है। यह थोक अपशिष्ट से कुछ खास खाद्य पदार्थों के अंश को पृथक करने में होने वाली स्वाभाविक कठिनाइयों को दूर करता है।

प्रतिदिन औसत बायो गैस का उत्पादन 50 किग्रा क्षमता के प्रति संयंत्र के लिए 9.0 घन मी. होगा तथा 100 किग्रा संयंत्र के लिए कुल बायो गैस उत्पादन 18.0 घन मी. होगा, जो आधे एलपीजी कमर्शियल सिलेंडर के बराबर है तथा इसका इस्तेमाल विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है।

इसके अलावा, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के 10 स्थानों यानि कटिहार, न्यूजलपाईगुड़ी, रंगिया, कामाख्या, गुवाहाटी, लामडिंग, डिमापुर, न्यू तिनसुकिया, डिब्रूगढ़ तथा सिलचर में विविध ठोस अपशिष्टों का संगठित पृथक्कीकरण का कार्य जारी है। ■

यात्री सुविधाएं बढ़ाने के लिए पैदल ऊपरी पुल के गर्डर की स्थापना

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे ने कोविड-19 महामारी की परिस्थिति के कारण लॉकडाउन अवधि के दौरान कई नए एवं लंबित कार्यों का निष्पादन किया है।

गत 23 जुलाई, 2020 को पू.सी.रेलवे के कटिहार मंडल के अधीन बरसोई स्टेशन पर 6.0 मीटर चौड़ा एफओबी (पैदल ऊपरी पुल) गर्डर की स्थापना की गई। यह नया पैदल ऊपरी पुल बरसोई स्टेशन आने-जाने वाले यात्रियों की दीर्घकालीन मांग को पूरा करेगा। वर्तमान एफओबी के एनजेपी छोर पर होने के कारण यह नया एवं चौड़ा एफओबी प्लेटफॉर्मों के कटिहार छोर की ओर से आने वाले यात्रियों को प्लेटफॉर्म को पार करने में आसानी होगी। 200 टन ढुलाई क्षमता वाली रोडक्रेन की सहायता से प्रत्येक 17.5 टन वजन तथा 37500 मिमी लंबे 4 गर्डरों की शुरुआत की गई। गर्डरों की सुरक्षित तथा सफलतापूर्वक शुरुआत



के लिए पूर्वाह्न 11.05 से अपराह्न 14.05 बजे तक 3.00 घंटे का ट्रैफिक एवं पॉवर ब्लॉक लिया गया। ■

रांची रेलवे स्टेशन पर कोविड केअर वेंडिंग मशीन की स्थापना

दिनांक 30 जुलाई, 2020 को रांची रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर-1 पर कोविड केअर वेंडिंग मशीन लगाई गई। इस मशीन के द्वारा यात्री शुल्क देकर मास्क, सैनिटाइजर एवं ग्लव्स प्राप्त कर सकते हैं। 3 लेयर वाले मास्क, सैनिटाइजर तथा हैंड ग्लव्स उचित मूल्य पर उपलब्ध होंगे। कोरोना वायरस के इस संक्रमण काल में जब मास्क लगाना एवं सैनिटाइजर का प्रयोग करना अति आवश्यक है, इस स्थिति में राँची रेलवे स्टेशन पर लगी यह मशीन यात्रियों के लिए बहुत ही उपयोगी है। ■



बांकुड़ा-सोनामुखी विद्युतीकरण का कार्य सम्पूर्ण

दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा मंडल के बांकुड़ा-सोनामुखी खंड का विद्युतीकरण कार्य पूरा हो गया है। बांकुड़ा-सोनामुखी खंड बांकुड़ा-मसाग्राम विद्युतीकरण परियोजना का एक हिस्सा है। बांकुड़ा से मसाग्राम तक विद्युतीकरण परियोजना की कुल लंबाई 118 किमी है और अनुमानित लागत 106.45 करोड़ रुपये है।

वर्तमान में, लगभग 41 किमी बांकुड़ा-सोनामुखी खंड का विद्युतीकरण कार्य लगभग रु 41.8 करोड़ की लागत से पूरा किया गया है। बांकुड़ा और सोनामुखी के बीच कुल 8 पैसेंजर हाल्ट हैं। सोनामुखी और मसाग्राम के बीच परियोजना के शेष हिस्से का कार्य, जो 77 किमी का है, जल्द ही पूरी हो जाएगा। बांकुड़ा से मसाग्राम तक कुल विद्युतीकरण कार्य पूरा होने से इस खंड में निर्बाध संचालन में मदद मिलेगी। विद्युतीकरण कार्य से ऊर्जा दक्षता और प्रदूषण मुक्त परिवहन सेवा प्रदान की जा सकेगी। इससे बेहतर कनेक्टिविटी और समय की पाबंदी भी सुनिश्चित होगी। ■



बांकुड़ा-सोनामुखी खंड में संपन्न विद्युतीकरण कार्य

दक्षिण पूर्व रेलवे : रांची रेलवे स्टेशन पर ऑटोमेटिक टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सेस मशीन की स्थापना

दिनांक 26 जुलाई 2020 को रांची रेलवे स्टेशन पर एक ऑटोमेटिक टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सेस मशीन लगाई गई। इस मशीन के द्वारा बिना किसी चीज को छुए यात्री की थर्मल स्क्रीनिंग की जा सकती है तथा रेलवे स्टाफ और यात्री एक-दूसरे से बिना नजदीक आए बात कर सकते हैं।

कोरोनावायरस के इस संक्रमण काल में जब सामाजिक दूरी का पालन करना अति आवश्यक है तथा संक्रमण से बचने के लिए किसी भी अनावश्यक वस्तुओं को नहीं छूना है। इस स्थिति में यह मशीन बहुत ही उपयोगी है। इस मशीन के द्वारा यात्रियों एवं रेलवे स्टाफ, दोनों की सुरक्षा होगी। ■



आरडीएसओ-वर्चुअल वेंडर मीट-2020 का आयोजन



भारतीय रेल के रिसर्च विंग आरडीएसओ ने देश के उत्तरी भागों में स्थित उद्योगों के हितार्थ 11 अगस्त, 2020 को एक वर्चुअल वेंडर मीट का आयोजन किया। इस मीट को उद्योग जगत् और इसमें शामिल हुए 150 से अधिक प्रतिनिधियों की ओर से शानदार प्रतिक्रिया मिली। वेब प्लेटफॉर्म की बाध्यता के चलते अनेक अन्य लोगों को भी ऐसी ही आगामी बैठकों में भाग लेने का सुझाव दिया गया। आरडीएसओ के महानिदेशक, श्री वीरेन्द्र कुमार और विशेष महानिदेशक (वेंडर डेवलेपमेंट) श्री ए.के. पांडे ने वेंडर मीट का कार्यक्रम बनाया गया है। अखिल भारतीय स्तर पर बैठकों का समन्वय श्री गोपाल कुमार, पीईडी, क्वालिटी एशोरेंस (मैकेनिकल) और श्री शमिन्दर सिंह, पीईडी, क्वालिटी एशोरेंस (सिग्नल एवं दूरसंचार) द्वारा किया जा रहा है।

बैठक में श्री ए.के. पांडे ने कहा कि अनुमोदन प्रक्रिया को सरल करने और अनुसंधान को बेहतर बनाने के लिए अनेक प्रयास किए गए हैं। श्री लोकेश सिंह, कार्यकारी निदेशक, क्वालिटी एशोरेंस (मैकेनिकल) और श्री पराग कुमार गोयल, कार्यकारी निदेशक, क्वालिटी एशोरेंस (संकेत एवं दूरसंचार) ने ऑनलाइन वेंडर अनुमोदन प्रक्रिया और व्यापार में सुगमता के उपायों तथा 5 से कम स्रोतों वाली मदों के विवरण का विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया। प्रतिनिधियों को यह भी बताया गया कि 5 स्रोतों से कम वाली आरडीएसओ नियंत्रित मदों के लिए वेंडर्स को स्वयं ही पंजीकृत करने में प्रोत्साहन देने के लिए पहले ही अनेक उपाय किए गए हैं। 5 स्रोतों से कम वाली मदों के लिए पंजीकरण प्रभार मध्यम/लघु उद्योगों के लिए 1,50,000 रुपये से घटाकर 10,000 रुपये और अन्यों के लिए 2,50000 रुपये से घटाकर 50,000 रुपये कर दिया है। सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन हैं। घरेलू विनिर्माताओं को प्राथमिकता दी जाएगी। सामग्री की खरीद डिजिटल प्लेटफॉर्म से की जाती है। विवरणों, ड्राइंग, तकनीकी दस्तावेजों की सूची इत्यादि सभी दस्तावेज आरडीएसओ की वेबसाइट पर निःशुल्क उपलब्ध हैं पंजीकरण, परीक्षण, परामर्श प्रभार इत्यादि के लिए भुगतान केवल ऑनलाइन है। इसके अलावा प्रोटो टाइप परीक्षण प्रभारों को सभी वेंडर्स के लिए 50% अथवा अधिक तक कम किया गया। ■

भोपाल मंडल द्वारा टीटीई लॉबी भोपाल ऐप विकसित किया गया

प्रधानमंत्री के 'डिजिटल इण्डिया' के सपने को साकार करने के उद्देश्य से भोपाल मंडल द्वारा 'टीटीई लॉबी भोपाल' नाम से एक एंड्रायड मोबाइल ऐप विकसित किया गया है। फ्रंट लाइन स्टाफ को ड्यूटी आने-जाने के दौरान बहुत सारे रजिस्टरों में एंट्री करनी पड़ती है, जिससे संक्रमण की अधिक संभावना होती है। संक्रमण से बचने के लिए टीटीई लॉबी मोबाइल ऐप के माध्यम से संबंधित स्टाफ अपने स्वयं के मोबाइल से सारी एंट्री कर सकता है। यह ऐप मूलतः दो भागों में बना हुआ है। पहला जिसमें मोबाइल एप्लीकेशन है, जिसमें एमेनिटी/उड़नदस्ता/स्टेशन स्टॉफ अपने कार्य के अनुसार अपने विवरण दर्ज कर सकें, पोर्टल को सरल बनाने के उद्देश्य से स्टाफ के कार्य के हिसाब से ही बनाया गया है। उदाहरण के तौर पर, यदि स्टॉफ एमेनिटी वर्किंग में है तो एमेनिटी स्टाफ को जो-जो विवरण प्रस्तुत करने होते हैं वे ही उसके ऐप में मिलेंगे।



दूसरा भाग रिपोर्ट से संबंधित है, जिसमें प्रत्येक स्टाफ का डेटा सेव होता है और आवश्यकतानुसार उसे मोबाइल पर या कम्प्यूटर पर ट्रांसफर करके मनचाहे तौर पर अभिलेख के रूप में प्रयोग किया जाता है।

मण्डल द्वारा इन ऐप में निम्न एंट्री के कॉलम रखे गये हैं:-

- **साइन ऑन पेज** - इसमें स्टॉफ साइन ऑन करने के लिए समय, ट्रेन नम्बर, स्टेशन और निजी राशि की घोषणा करेगा।
- **अर्निंग रिपोर्ट** - इसमें कार्य समाप्ति पर अर्जित की गई आय के पूरे विवरण (बिना टिकट, अनियमित यात्रा) जीएसटी एम आर नम्बर सहित दर्ज करेंगे।
- डीएमआर कोच मेंड रिपोर्ट।
- **मंथली अर्निंग रिपोर्ट** - यदि स्टॉफ प्रतिदिन नियमित रूप से विवरण दर्ज करते हैं तो मासिक रिपोर्ट स्वतः ही तैयार हो जाएगी।
- **प्रोफाइल** - इसमें कर्मचारियों को अपने कार्य के विवरण दर्ज करने की सुविधा है, जो एक प्रकार से उनकी डायरी का काम करेगी। इसमें टीए के लिए टाइम दर्ज करने की सुविधा भी है।

कुल मिलाकर देखा जाए तो अनावश्यक मानव श्रम और समय को बचाने की दृष्टि से हमने यह प्रयास शुरू किया है एवं भविष्य की मांग के हिसाब से इसमें यथेष्ट परिवर्तन किया जाएगा। ■

ऊर्जा बचत के लिए पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा प्लेटफॉर्म लाइटिंग का ऑटोमेशन

पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर एवं नरसिंहपुर स्टेशन में प्लेटफॉर्म लाइट्स को नियंत्रित करने के लिए विद्युत विभाग द्वारा ऊर्जा बचत के लिए जबलपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक-1 एवं नरसिंहपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक-1 एवं 2 में सिग्नल प्रणाली पर आधारित स्वचालित प्लेटफॉर्म लाइट नियंत्रक सिस्टम दिनांक 4 जुलाई, 2020 से लगाया गया है।

इसी तारतम्य में दिनांक 9 जुलाई, 2020 से कोटा मंडल के रामगंजमंडी एवं भवानीमंडी स्टेशनों पर भी सिग्नल प्रणाली पर आधारित स्वचालित प्लेटफॉर्म लाइट नियंत्रक सिस्टम लगाया गया है। जैसे ही गाड़ी प्लेटफॉर्म पर पहुंचेगी, प्लेटफॉर्म की शत-प्रतिशत लाइटें चालू हो जाएंगी और जैसे ही प्लेटफॉर्म को पार करेगी, 70 प्रतिशत लाइटें बंद हो जाएंगी एवं यात्री सुविधा एवं सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक 30 प्रतिशत लाइटें ही चालू रहेंगी।

इस प्रणाली को अपनाने से प्रतिवर्ष नरसिंहपुर स्टेशन में लगभग 6,800 यूनिट यानि 55,000 रुपये एवं जबलपुर स्टेशन पर लगभग 15,500 यूनिट यानि 1,24,000 रुपये रेल राजस्व की बचत होगी।

इससे पहले भोपाल मण्डल पर पायलट प्रोजेक्ट के तहत् हरदा स्टेशन पर हाल में ही इसका सफल प्रयोग किया जा चुका है। इससे उत्साहित होकर भोपाल मंडल के भोपाल स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर-1 पर भी सिग्नल प्रणाली पर आधारित स्वचालित प्लेटफॉर्म लाइट नियंत्रक सिस्टम की व्यवस्था की गई है। ■

रेल कोच फैक्ट्री ने जुलाई माह में किया एलएचबी कोचों का सर्वाधिक उत्पादन

रेल कोच फैक्ट्री, कपूरथला ने जुलाई, 2020 में एलएचबी डिब्बों के निर्माण में एक नया कीर्तिमान हासिल करते हुए 151 एलएचबी कोचों का निर्माण किया है जो सन् 2002 में भारतीय रेल द्वारा एलएचबी कोचों के उत्पादन की शुरुआत किए जाने से लेकर अब तक किसी भी उत्पादन इकाई का सर्वाधिक मासिक उत्पादन है। जून महीने में आरसीएफ ने 107 एलएचबी डिब्बे बनाए थे। पिछले वर्ष जुलाई महीने में आरसीएफ ने 65 एलएचबी डिब्बों का निर्माण किया था।

इस वित्तीय वर्ष के पहले 4 महीनों में आरसीएफ ने कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन के चलते 310 कोचों का उल्लेखनीय निर्माण किया है जिसमें से 307 एलएचबी डिब्बे हैं।

आरसीएफ ने लगातार अपनी उत्पादन प्रक्रिया में नीतिगत परिवर्तन करके कोचों की गुणवत्ता तथा उत्पादन क्षमता को बढ़ाया है। वर्ष 2002 में मैसर्स एलस्टॉम, जर्मनी से एलएचबी टेक्नॉलाजी आरसीएफ ने प्राप्त की थी। 23 जून, 2003 को आरसीएफ से पहला एलएचबी युक्त डिब्बों का राजधानी रेक तैयार कर रवाना किया गया था। तब से आरसीएफ ने अब तक 6,500 से अधिक एलएचबी डिब्बों का निर्माण किया है। इन डिब्बों को पहले पहले भारत की प्रीमियम गाड़ियों, जैसे राजधानी, शताब्दी, दुरन्तो, डबल डैकर में लगाया जाता रहा मगर इन डिब्बों की उपयोगिता देखकर इन्हें लम्बी दूरी की मेल



एक्सप्रेस गाड़ियों तथा अन्य सामान्य गाड़ियों में भी लगाया जा रहा है। स्टेनलेस स्टील से बने ये डिब्बे तेज गति से चलने में सक्षम हैं। इनकी सीटिंग/बर्थ कैपेस्टी भी आईसीएफ टाइप डिब्बों से अधिक है। इन डिब्बों में विश्वस्तरीय मानकों के अनुसार कई ऐसी विशेषताएं शामिल की गई हैं जोकि यात्रा को अत्यंत सुविधाजनक बनाती हैं। इन डिब्बों में यात्रियों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे और फायर अलार्म भी लगाए गए हैं।

भारतीय रेल के नवीनीकरण के लिए सबसे पहले आरसीएफ ने एलएचबी टेक्नोलॉजी को अपनाया और इसके बाद इंटिग्रल कोच फैक्ट्री, चेन्नई और मॉडर्न कोच फैक्ट्री, रायबरेली ने भी इनका नियमित उत्पादन शुरू किया। ■

रेल कोच फैक्ट्री कम वजन वाले एलएचबी डिब्बों के निर्माण की तैयारी में

आरसीएफ ने जुलाई में डिब्बों का उत्पादन बढ़ाने के लिए बेहद कम लागत वाली जिग्ग का निर्माण किया, जिससे प्रतिदिन 7 से 8 डिब्बों का निर्माण संभव हो सकेगा। निर्माण क्षमता बढ़ाने हेतु जहाँ अनेक नीतिगत परिवर्तन किए जा रहे हैं वहीं रेल डिब्बों के विकास में भी कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसी के तहत रेल कोच फैक्ट्री द्वारा कम वजन वाले एलएचबी डिब्बों के निर्माण के लिए डिजाइन तैयार किए जा रहे हैं।

विभिन्न एलएचबी डिब्बों का वजन 46 टन के करीब होता है, जिसे कम करने के लिए कोच की शेल, फर्निशिंग और इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स में कई डिजाइन सुधार किए जा रहे हैं। एसी एलएचबी डिब्बों की सीट और बर्थ में व्यापक बदलाव किए जाएँगे, जिससे एसी फर्स्ट, एसी 2 टियर और एसी 3 टियर में क्रमशः 3 क्विंटल, 6 क्विंटल और 6.7 क्विंटल वजन की कमी होगी। इसके इलावा इन डिब्बों के एसी पैकेज यूनिट के मैटीरीयल में बदलाव लाकर 3 क्विंटल वजन कम किया जाएगा। स्लीपर और जनरल डिब्बों में पार्टीशन फ्रेम की जगह हल्के हनी कांब पार्टीशन फ्रेम लगाने से वजन में कमी आएगी। इसके इलावा विभिन प्रकार के डिब्बों में बायो टैंक, ट्रांसफॉर्मर, स्विचबोर्ड कैबिनेट इत्यादि उपकरणों के जरिये वजन में कटौती का प्रावधान है।



आरसीएफ ने इस वर्ष से उच्च क्षमता वाली पार्सल वैन का निर्माण प्रारम्भ किया है। ये डिब्बे लम्बी दूरी की गाड़ियों में लगाये जा रहे हैं जिससे सामान की आपूर्ति में तेजी संभव हो। स्टेनलेस स्टील से बने इन डिब्बों की सामान वहन क्षमता 24 टन है। इन डिब्बों के लगेज रैक, पैनल और फ्लोरिंग आदि के सामान में तब्दीली लाकर लगभग 1.5 टन वजन कम किया जाएगा। इससे इन वैनों की सामान वहन क्षमता और बढ़ेगी।

हल्के होने से न सिर्फ इन डिब्बों को खींचने की लागत में कमी आएगी बल्कि ट्रेनों में कोचों की संख्या भी बढ़ाई जा सकती है। इसके इलावा डिब्बों की कुशलता में सुधार होगा तथा इनकी इंटीरियर लुक की खूबसूरती में भी बढ़ोत्तरी होगी और गति बढ़ाने के लक्ष्य की प्राप्ति संभव होगी। ■

आध्यात्मिक नगरी अयोध्या रेलवे स्टेशन के सर्वांगीण एवम् संरचनात्मक विकास की दिशा में उत्तर रेलवे के निरन्तर बढ़ते कदम

आस्था, भक्ति एवम् आध्यात्म की पावस धरा तथा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या नगरी युगों से सम्पूर्ण विश्व के मध्य भक्ति एवम् आस्था का केंद्र बिंदु रही है। कदाचित् इस नगरी की यही महत्ता ईश्वर के अनुरागियों एवम् श्रद्धालुओं को बरबस अपनी ओर आकृष्ट करती है एवम् इस पावन भूमि पर नित्यप्रति पूरे विश्व से असंख्य भक्तगणों का इस नगर में आगमन होता है। अपनी इसी महत्ता के कारण अयोध्या नगरी का रेलवे स्टेशन भी भारतीय रेल पर अपना एक विशेष स्थान रखता है एवम् प्रतिदिन अपनी सुगम रेल परिचालन व्यवस्था के द्वारा अनेक गाड़ियों को संचालित करते हुए यात्रियों के लिए इस नगर में सुविधाजनक आवागमन में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका एवम् उत्तरदायित्वों का पूर्ण प्रतिबद्धता से निर्वहन करता है। अपनी इसी निष्ठा का अनुसरण करते हुए एवम् वर्तमान अयोध्या के परिवेश को दृष्टिगत रखते हुए तथा भविष्य में अयोध्या की महत्ता को ध्यान में रखते हुए मंडल द्वारा अयोध्या रेलवे स्टेशन के संरचनात्मक स्वरूप, यात्री सुविधाओं, स्वच्छता, सौंदर्य तथा विभिन्न वांछित सुविधाओं को उच्च गुणवत्ता के मानकों के साथ उपलब्ध कराने की दिशा में निरन्तर सार्थक प्रयास करते हुए इस स्टेशन को नव स्वरूप से सुसज्जित करने की प्रक्रिया अविराम जारी है। उल्लेखनीय है कि अयोध्या स्टेशन की नवीनतम एवं आधुनिक यात्री सुविधाओं से सुसज्जित भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इस भवन हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में ₹ 80 करोड़ की स्वीकृति दी गई थी जिसे वर्तमान में बढ़ाकर ₹ 104.77 करोड़ कर दिया गया है। इस स्टेशन भवन का निर्माण रेलवे के राइट्स (RITES) उपक्रम द्वारा किया जा रहा है।

इस भवन का निर्माण दो चरणों में होगा। प्रथम चरण में प्लेटफॉर्म संख्या-1 व 2/3 में विकास कार्य, वर्तमान सर्कुलेटिंग एरिया का विकास व होल्डिंग एरिया का विकास। दूसरे चरण में नए स्टेशन भवन का निर्माण व अन्य सुविधाओं का निर्माण कार्य। इन सुविधाओं के अन्तर्गत स्टेशन के आंतरिक एवम् बाह्य परिसर का नवीनीकरण करते हुए स्टेशन पर उपलब्ध सुविधाओं में वृद्धि, जैसे टिकट काउंटर की संख्या विस्तार, प्रतीक्षालय सुविधा विस्तार, 3 वातानुकूलित विश्रामालय, 17 बेड वाली पुरुष डॉरमेट्री प्रसाधन, 10 बेड वाली महिला डॉरमेट्री प्रसाधन, एक अतिरिक्त फुट ओवर ब्रिज, फूड प्लाजा, दुकानें, अतिरिक्त शौचालय सहित अन्य वांछित सुविधाओं को उपलब्ध कराने की दिशा में निरन्तर प्रगति कार्य जारी है। इसके अतिरिक्त स्टेशन पर पर्यटक केंद्र, टैक्सी बूथ, शिशु विहार, वी.आई.पी. लाउंज, सभागार तथा विशिष्ट अतिथि गृह समेत अनेक अन्य वांछित सुविधाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करते हुए निरन्तर निर्माण एवम् विकास कार्य प्रगति पर है। इन समस्त विकास एवम् प्रगति कार्यों को संपादित किया जा रहा है एवम् समय-समय पर विकास कार्यों का जायजा लेते हुए समीक्षा की जाती है तथा यथासमय उच्च गुणवत्ता के साथ कार्य को पूरा करने के निर्देश भी पारित किए जाते हैं।

उत्तर एवं उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक श्री राजीव चौधरी ने इस विषय में अवगत कराया कि भगवान राम की पावस चरणधूलि से सुशोभित अयोध्या की पवित्र नगरी का अलौकिक महत्त्व है एवम् भविष्य में इस नगरी की महत्ता को ध्यान में रखते हुए मंडल द्वारा अयोध्या रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण करते हुए एक नवीन स्वरूप प्रदान करने की दिशा में निरन्तर प्रयास चल रहे हैं ताकि आगामी समय में सम्पूर्ण विश्व से इस स्टेशन पर आने वाले श्रद्धालुओं एवम् पर्यटकों को उच्च मानकों से सुसज्जित आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। ■



आध्यात्मिक नगरी अयोध्या

श्री अनिल सक्सेना

अयोध्या भारत के प्राचीनतम शहरों में शुमार है और करोड़ों भारतीयों के आराध्य भगवान श्रीराम की जन्मस्थली के रूप में विख्यात है। अयोध्या अपने धार्मिक स्वरूप और धार्मिक पराकाष्ठा के कारण आम हिंदू जनमानस के बीच आस्था के केंद्र के रूप में विख्यात है। इसे हम इस नजरिए से भी देख सकते हैं कि सादात अली खान ने भगवान श्रीराम के बाद अयोध्या को ही अवध की राजधानी बनाया, पर एक ईरानी होने के नाते वर्तमान अयोध्या नगर से तकरीबन 10 किमी दूर जाकर अपनी फारसी जुबान में उसे फैजाबाद के नाम से स्थापित किया, जिसका अर्थ कुछ विद्वान ऐसे शहर के रूप में निकालते हैं जहां पर सब बराबर हैं।

कोई भेदभाव नहीं है। यह एक तरह से महाकवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित 'श्रीरामचरितमानस' में वर्णित रामराज्य की अवधारणा से मेल खाता है। फैजाबाद एक बहुत ही खूबसूरत और ऐतिहासिक शहर है। लखनऊ के बाद यह दूसरा शहर है जिसकी इमारतें नवाबकालीन दौर को फिर से जीवन्त कर देती हैं। इस शहर को बहुत से साहित्यकारों, कवियों और स्वतंत्रता सेनानियों की जन्मभूमि और कर्मभूमि होने का गौरव प्राप्त है। 'रामायण' का पहली बार उर्दु में तर्जुमा करने वाले महान उर्दू कवि और पेशे से वकील पंडित ब्रजनारायण चकबस्त की जन्मस्थली और कर्मस्थली भी फैजाबाद ही थी।

- अयोध्या भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक अति प्राचीन धार्मिक नगर है।
- प्राचीन उल्लेखों के अनुसार तब इसका क्षेत्रफल 96 वर्ग मील था।
- वर्तमान अयोध्या के प्राचीन मंदिरों में सीतारसोई तथा हनुमानगढ़ी मुख्य हैं। 18वीं तथा 19वीं शताब्दी में बने कुछ मंदिर दर्शनीय हैं।



रामकोट : शहर के पश्चिमी हिस्से में स्थित रामकोट अयोध्या में पूजा का प्रमुख स्थान है। यहां भारत और विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं का साल भर आना-जाना लगा रहता है। मार्च-अप्रैल में मनाया जाने वाला रामनवमी पर्व यहां बड़े जोश और धूमधाम से मनाया जाता है।

हनुमान गढ़ी : नगर के केन्द्र में स्थित इस मंदिर में 76 कदमों की चाल से पहुँचा जा सकता है। अयोध्या को भगवान राम की नगरी कहा जाता है। मान्यता है कि यहां हनुमान जी सदैव वास करते हैं। इसलिए अयोध्या आकर भगवान राम के दर्शन से पहले भक्त हनुमान जी के दर्शन करते हैं। रामलला के दर्शन से पहले यहां आना जरूरी माना जाता है।

यहां आज भी छोटी दीपावली के दिन आधी रात को संकटमोचन का जन्म दिवस मनाया जाता है। पवित्र नगरी अयोध्या में सरयू नदी में पाप धोने से पहले लोगों को भगवान हनुमान से आज्ञा लेनी होती है। यह मंदिर अयोध्या में एक टीले पर स्थित होने के कारण मंदिर तक पहुंचने के लिए लगभग 76 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। इसके बाद पवनपुत्र हनुमान की 6 इंच की प्रतिमा के दर्शन होते हैं, जो हमेशा फूल-मालाओं से सुशोभित रहती है। मुख्य मंदिर में बाल हनुमान के साथ अंजनी माता की प्रतिमा है। श्रद्धालुओं का मानना है कि इस मंदिर में आने से उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मंदिर परिसर में मां अंजनी व बाल हनुमान की मूर्ति है जिसमें हनुमानजी अपनी मां अंजनी की गोद में बालक के रूप में विराजमान हैं।

नागेश्वर नाथ मंदिर : कहा जाता है कि नागेश्वर नाथ मंदिर को भगवान राम के पुत्र कुश ने बनवाया था। माना जाता है जब कुश सरयू नदी में नहा रहे थे तो उनका बाजूबंद खो गया था। बाजूबंद एक नाग कन्या को मिला, जिसे कुश से प्रेम हो गया। वह शिवभक्त थी। कुश ने उसके लिए यह मंदिर बनवाया। कहा जाता है कि यही एकमात्र मंदिर है जो विक्रमादित्य के काल के पहले से है।



नागेश्वर नाथ मंदिर

राघवजी का मन्दिर : यह मन्दिर अयोध्या नगर के केन्द्र में स्थित बहुत ही प्राचीन भगवान श्री रामजी का स्थान है, जिसको हम 'राघवजी का मंदिर' के नाम से भी जानते हैं। मन्दिर में स्थित भगवान राघवजी अकेले ही विराजमान हैं। यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें भगवान श्रीराम जी के साथ माता सीताजी की मूर्ति बिराजमान नहीं है।

कनक भवन : हनुमान गढ़ी के निकट स्थित कनक भवन अयोध्या का एक महत्त्वपूर्ण मंदिर है। यह मंदिर सीता और राम के सोने का मुकुट पहनी प्रतिमाओं के लिए लोकप्रिय है। इसी कारण बहुत बार इस मंदिर को 'सोने का घर' भी कहा जाता है। यह मंदिर टीकमगढ़ की रानी ने सन् 1891 में बनवाया था।



कनक भवन

आचार्यपीठ श्री लक्ष्मण किला : महान संत स्वामी श्री युगलानन्यशरणजी महाराज की तपस्थली यह स्थान देश भर में रसिकोपासना के आचार्यपीठ के रूप में प्रसिद्ध है। श्री स्वामीजी चिरान्द (छपरा) निवासी स्वामी श्री युगलप्रिया शरण 'जीवाराम' जी महाराज के शिष्य थे। ईसवी सन् 1818 में ईशराम पुर (नालन्दा) में जन्मे स्वामी युगलानन्यशरण जी का रामानन्दीय वैष्णव-समाज में विशिष्ट स्थान है।

जैन मंदिर : हिन्दुओं के मंदिरों के अलावा अयोध्या जैन मंदिरों के लिए भी खासा लोकप्रिय है। जैन धर्म के अनेक अनुयायी नियमित रूप से अयोध्या आते रहते हैं।

स्मरणीय सन्त : प्रभु श्रीराम की नगरी होने से अयोध्या उच्चकोटि के सन्तों की भी साधना-भूमि रही। यहाँ के अनेक प्रतिष्ठित आश्रम ऐसे ही सन्तों ने बनाए।

दुनिया का तीसरा बड़ा मंदिर होगा अयोध्या राम मंदिर। जानें, इससे भी बड़े मंदिर कहां हैं स्थित

अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर का नक्शा करीब 37 साल पहले बनाया गया था। इस मंदिर को और अधिक भव्य और बड़ा बनाने के लिए इसमें थोड़ा बदलाव किया जा रहा है, पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि विश्व का सबसे बड़ा और भव्य मंदिर भारत में नहीं बल्कि विदेश में है। यह कंबोडिया में स्थापित अंकोरवाट मंदिर है। करीब 67 एकड़ में प्रस्तावित अयोध्या के राममंदिर का दायरा भी अब 100 से 120 एकड़ तक हो सकता है। ऐसे में यह बड़े मंदिरों की श्रेणी में तीसरे स्थान पर आएगा। आइए, एक नजर डालते हैं विश्व के सबसे बड़े मंदिरों पर।

अंकोरवाट मंदिर : कम्बोडिया स्थित अंकोरवाट मंदिर के शिखर की ऊंचाई 213 फीट है। अंकोरवाट दुनिया का सबसे

बड़ा धार्मिक स्मारक है, जो करीब 162.6 हेक्टेयर यानी 401 एकड़ में फैला है। इसे मूल रूप से खमेर साम्राज्य में भगवान विष्णु के मंदिर के रूप में बनाया गया था। मीकांग नदी के किनारे सिमरिप शहर में बना यह मंदिर आज भी संसार का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है।

श्रीरंगनाथ मंदिर : तमिलनाडु स्थित त्रिची में बना श्रीरंगनाथ मंदिर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है। यह विष्णु मंदिर है जो लगभग लगभग 155.9 एकड़ में फैला हुआ है।

अक्षरधाम मंदिर : देश की राजधानी दिल्ली में बना अक्षरधाम मंदिर स्वामीनारायण संप्रदाय के सबसे बड़े प्रतीकों में शुमार है। यह लगभग 2,40,000 वर्गमीटर (लगभग 59.3 एकड़) एरिया में बना हुआ है।

थिल्लईनटराज-मंदिर : तमिलनाडु के चिदंबरम में बना 'चिदंबरम मंदिर' भगवान शिव की आस्था के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। यह लगभग 1,60,000 (लगभग 39 एकड़) वर्गमीटर के क्षेत्र में बना हुआ है।

बेलूरमठ : कोलकाता के हुगली नदी के किनारे स्थापित बेलूर मठ को दुनिया के विशालतम मंदिरों में गिना जाता है। यह स्वामी विवेकानंद के बुनियादी सिद्धांतों को आगे बढ़ाने का काम आज भी कर रहा है। यहां मां आद्याकाली की पूजा होती है। यह लगभग 39 एकड़ के क्षेत्र में फैला है।

बृहदेश्वर-मंदिर : तमिलनाडु के तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर भी विशालकाय मंदिरों में शुमार है। यह शिव मंदिर करीब 1,000 साल पहले राजाराज चोला प्रथम के नेतृत्व में बनाया गया था। यह लगभग लगभग 25 एकड़ में स्थित है।

अन्नामलाईयर-मंदिर : तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई में स्थित भगवान शिव का यह मंदिर अपने ऊंचे स्तम्भों के कारण बहुत लोकप्रिय है। यह लगभग 24.9 एकड़ में फैला हुआ है।

अयोध्या : वैभव, ऐश्वर्य व ज्ञान की पौराणिक नगरी

भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या रघुवंशी राजाओं की राजधानी थी। इसका अर्थ है - अ-युद्ध यानि जहाँ कभी युद्ध नहीं होता। यह कौशल जनपद की राजधानी थी। 'वाल्मीकि रामायण' के पांचवें सर्ग में अयोध्या का वर्णन विस्तार से है।

7 पवित्र नगरों में पहले स्थान पर है अयोध्या

अयोध्या की गणना भारत की प्राचीन सप्तपुरियों में प्रथम स्थान पर की गई है। हिन्दू पौराणिक इतिहास में पवित्र 7 नगरों में अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, उज्जैन और द्वारका को शामिल किया गया है।

अयोध्या मथुरा माया काशी काञ्ची अवन्तिका।
पुरी द्वारावती चौव सप्तैता मोक्षदायिका:

(अर्थ : अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, काञ्चीपुरम, उज्जैन, और द्वारिका - ये 7 पुरियाँ नगर मोक्षदायी हैं)

भगवान विष्णु के चक्र पर विराजी है अयोध्या

'स्कन्दपुराण' के अनुसार, अयोध्या भगवान विष्णु के चक्र पर विराजी है। जब मनु ने ब्रह्माजी से अपने लिए के एक नगर बसाने की बात कही तो वे उन्हें विष्णु जी के पास ले गए। विष्णु जी ने साकेत धाम (अयोध्या) में स्थान बताया जहां विश्वकर्मा ने नगर बनाया।

इश्वाकु कुल का राज, दशरथ 63वें राजा

इस नगर को विवस्वान (सूर्य) के पुत्र वैवस्वत मनु ने संपन्न किया। मान्यता है कि ब्रह्माजी के पुत्र मरीचि से कश्यप, कश्यप से विवस्वान और ऊनके पुत्र वैवस्वत थे। उनके 10 पुत्र-इल, इस्वकू, कुशनाम, अरिष्ट, घृष्ट, नरिश्यंत, करुष, महाबली, शर्याति और प्रिशध थे। सबसे ज्यादा विस्तार इश्वाकु कुल का हुआ। इसी वंश के राजा दशरथ अयोध्या के 63वें शासक थे। उसके बाद महाभारत काल तक इसी वंश का शासन रहा।

स्वर्ग से की गई है सम्पन्नता की तुलना

अयोध्या को 'अथर्ववेद' में 'इश्वर का नगर' कहा गया है और इसकी सम्पन्नता की तुलना स्वर्ग से की गई है।

अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या।
तस्यां हिरण्मय: कोश: स्वर्गो ज्योतिषावृत:
(अथर्ववेद - 10.2.31)



अयोध्या नगरी दीपोत्सव की अद्भुत छटा से दैदीप्यमान



भगवान श्रीराम के जन्मभूमि मन्दिर का भूमि पूजन करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द मोदी एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति

'स्कन्दपुराण' के अनुसार अयोध्या शब्द 'अ' कार ब्रह्मा, 'य' कार विष्णु है तथा 'ध' कार रुद्र का स्वरूप है। मान्यता है कि राम के पुत्र कुश ने अयोध्या का पुनर्निर्माण करवाया था।

ऋषभ देवजी समेत 5 तीर्थंकरों का जन्मस्थान

लाला सीताराम भूप की किताब – 'अयोध्या का इतिहास' और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इतिहासविद् डॉ. हेरम्ब चतुर्वेदी के मुताबिक 24 जैन तीर्थंकरों में से पहले ऋषभ देव समेत 5 तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या में ही हुआ था। यह भी कहा जाता है कि वे इश्वाकु कुल से ही सम्बंधित हैं। अयोध्या-ए-हिंदू यरूशलम के लेखक हैंस बेकर के मुताबिक, अयोध्या में 7 तीर्थंकर जन्मे थे।

अयोध्या को साकेत भी कहा जाता था। गौतम बुद्ध का इस नगर से विशेष सम्बन्ध था। उल्लेखनीय है कि गौतम बुद्ध के इस नगर से विशेष सम्बन्ध की ओर लक्ष्य करके 'मज्झिमनिकाय' में उन्हें 'कोसलक' (कोशल का निवासी) कहा गया है। प्राचीन, भारतीय साहित्य संसार में बौध ग्रंथा में साकेत के रूप में अयोध्या का महत्त्वपूर्ण उल्लेख किया गया है। बुद्ध के समय के 6 प्रमुख नगरों में साकेत की गिनती होती थी। विख्यात बौद्ध भिक्षु सारिपुत्र एवम अनिरुद्ध के अयोध्या में ठहरने की बात प्रमाण सहित मिलती है। मान्यता है कि भगवान बुद्ध अयोध्या में 16 साल रहे थे। यहाँ पर सातवीं शताब्दी में चीनी यात्री ह्वेनसांग आया था। उसके अनुसार यहाँ 20 बौद्ध मंदिर थे तथा 3,000 भिक्षु रहते थे।

अयोध्या में धार्मिकता के साथ पहले स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे और अशफाक उल्ला खान के बलिदान का एक रंग भी घुला है। मंगल पांडे और अशफाक उल्ला यहीं के थे और पहले दोनों को फांसी हुई तो बाद में अंग्रेजों द्वारा इनका जो भी परिजन मिला, उसे तोप के आगे बांधकर उड़ा दिया गया। 'बकौल शहरनामा' के लेखक यतीन्द्र मिश्र 'बलिदान का यह रंग शहर के वर्तमान को संवारता और वैभवशाली बनाता है।'

अयोध्या हिंदुओं की धार्मिक नगरी तो है ही, यह शहरे औलिया और खुर्द मक्का भी है। यहां वलियों की दरगाहें हैं। इस्लाम में फकीरी लाइन के लोग भी हिन्दू साधु संतों-फकीरों से संवाद करते और 40 दिन अयोध्या वास करते थे। यहां गुरुद्वारे हैं तो गिरजाघर भी हैं।

अयोध्या में नया युग

सगुन होंहिं सुन्दर सकल मन प्रसन्न सब केर।
प्रभु आगमन जनाव जनु नगर रम्य चहुँ फेर॥

अर्थात् भगवान श्री रामचंद्रजी के अयोध्या में आने के संकेत मात्र से सारे शगुन सुन्दर होने लगे। सबके मन प्रसन्न हो गए। नगर चारों ओर से रमणीक हो गया।

शांतिपूर्ण और भावपूर्ण माहौल में हुआ राम मंदिर का शिलान्यास

500 साल की आस पूरी हुई। लंबी राजनीतिक, सांस्कृतिक लड़ाई व आंदोलन, जिसमें आरोप-प्रत्यारोप भी हुए, लेकिन इसके बाद जिस तरह शांतिपूर्ण और भावपूर्ण माहौल में शिलान्यास हुआ, वह अपने आप में इस बात को बयां करता है कि भारत अब आगे बढ़ने को तैयार है। लोकतांत्रिक और सौहार्दपूर्ण तरीके से राममंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया। यह कहा जा सकता है कि एक नए युग की शुरुआत हो गई है, जो अब हर पल रामराज्य के लिए प्रेरित करेगी। अयोध्या में भूमिपूजन के कार्यक्रम का मुहूर्त तय होते ही श्रीराम की उस प्रतिमा पर काम शुरू हो गया है जो अयोध्या ही नहीं, भारत को विश्व के पटल पर सबसे ऊंचा स्थान दिलाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में भगवान श्री राम की 251 मीटर ऊंची प्रतिमा लगाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस प्रतिमा को बनाने का जिम्मा एक बार फिर देश के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार राम सुतार को सौंपा गया है। इससे पहले भी राम सुतार ने गुजरात में सरदार पटेल की 183 मीटर ऊंची प्रतिमा डिजाइन की थी, जिसने नए कीर्तिमान रचे।

ऐसे बदलेगी अयोध्या की आर्थिक स्थिति

अयोध्या में श्रीराम का मंदिर इस जिले की विकास की कुंजी है। धार्मिक पर्यटन यहां रोजगार की असीम संभावनाएं लेकर आएगा। 8 बड़े होटल बनने जा रहे हैं। पर्यटकों से इस जनपद की चौतरफा आय होगी। गाइड्स को रोजगार मिलेगा। धर्म से जुड़ी व्यावसायिक गतिविधियों से बड़ी आय होगी। नव अयोध्या भी लोगों का आकर्षण बढ़ाएगी और यहां की हाईटेक टाउनशिप और रिवर साइड रिसॉर्ट बहुतों को रोजगार देंगे। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और अत्याधुनिक बस अड्डे भी आय में वृद्धि करेंगे। काशी की तर्ज पर जिले की आर्थिक उन्नति बढ़ेगी। फूड इंडस्ट्री, हॉस्पिटेलिटी इंडस्ट्री और विशेष रूप से एक जिला एक उत्पाद के तहत चयनित सामानों को अंतरराष्ट्रीय बाजार मिलेगा। ये सब अयोध्या की कायापलट कर देंगे।

भविष्य की अयोध्या अध्यात्म, संस्कृति और आधुनिकता का अद्भुत संगम

भविष्य की अयोध्या अध्यात्म, संस्कृति और आधुनिकता का अद्भुत संगम होगी और धार्मिक पर्यटन में विश्व में सबसे बड़े केंद्र के रूप में इसकी पहचान होगी। प्रत्यक्ष-परोक्ष रूप से स्थानीय के साथ देश की आर्थिकी में इसकी हिस्सेदारी बढ़ेगी।

- नई अयोध्या में पहुंच आसान होगी। श्रीराम एयरपोर्ट की तैयारी है। रेलवे स्टेशन व बस अड्डे का आधुनिकीकरण हो रहा है।
- राम मंदिर निर्माण के समानांतर ही इस दिशा में कार्य शुरू किया गया है। 251 मीटर की श्रीराम प्रतिमा और नव्य अयोध्या इस नगरी का प्रमुख आकर्षण होगी।

नव्य अयोध्या: 400 हेक्टेयर में बसाई जाने वाली यह नगरी अयोध्या का आधुनिक चेहरा होगी और विदेशी पर्यटकों को केंद्र में रखते हुए बसाई जाएगी। यह अयोध्या से 10 किमी दूर शाहनेवाजपुर ग्राम के निकट बसेगी। नव्य अयोध्या में 500 एकड़ में हाईटेक टाउनशिप बसेगी, जिसमें फाइव स्टार होटल्स, रिवरसाइड रिजार्ट, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, आवासीय और व्यावसायिक प्लॉट्स, बेहतरीन सड़कें, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम और अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी वायर होंगे।

- सरयू किनारे बनेंगे स्टूडियो अपार्टमेंट। जीवन के आखिरी समय में लोग इन अपार्टमेंट्स में रहना पसंद करेंगे। कुछ खास धनराशि देकर लोग फ्लैट अपने नाम पर ले सकेंगे, जो उनके निधन के बाद ट्रस्ट की संपत्ति होगी। सरयू में क्रूज भी चलेंगे।
- यह प्रोजेक्ट पूरा करने में लगभग 1,200 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।
- राम वन गमन मार्ग से लिंक होना, अयोध्या आने वालों के लिए अतिरिक्त आकर्षण होगा।
- लखनऊ से गोरखपुर मार्ग 6 लेन होने जा रहा है, जो अयोध्या से होकर जाएगा।
- शहादतगंज से अयोध्या तक 4 लेन होगा। अभी तक अयोध्या में एक भी 4 लेन मार्ग नहीं है।
- ओवरब्रिज के माध्यम से अयोध्या सीधे हाइ-वे से जुड़ेगी।

भव्यता

- मंदिर 360 फीट लंबा और 235 फीट चौड़ा होगा। इसकी ऊंचाई 161 फीट होगी।
- क्षेत्रफल 84,600 वर्ग फीट होगा।
- मंदिर में तीन लाख टन लाल बलुआ पत्थर लगेगा ।
- गर्भगृह और रंगमंडप के बीच गूढ़ मंडप होगा। दाएं-बाएं अलग-अलग कीर्तन व प्रार्थना मंडप होगा।
- साढ़े नौ किलो चांदी से निर्मित सिंहासन पर विराजमान होंगे राम लला। भाइयों के लिए भी रजत सिंहासन बनेगा।
- दुनिया में सबसे 'ऊंचे' होंगे मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम।

फिलहाल चीन में गौतम बुद्ध की मूर्ति दुनिया में सबसे ऊंची मानी गई है। इसकी ऊंचाई 208 मीटर है, लेकिन अयोध्या में भगवान राम की जो प्रतिमा स्थापित होगी, वो 251 मीटर ऊंची होगी। यानि इसके निर्माण के साथ ही यह दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी। इस प्रतिमा में 20 मीटर ऊंचा घेरा होगा और प्रतिमा 50 मीटर ऊंचे बेस पर खड़ी होगी। आधार के नीचे एक भव्य संग्रहालय भी होगा, जहां भगवान विष्णु के सभी अवतारों को तकनीकी माध्यम से दिखाया जाएगा। यहां एक डिजिटल म्यूजियम, फूड प्लाजा, लैंड स्केपिंग, लाइब्रेरी और रामायण काल की गैलरी भी बनाई जाएगी। ■



श्री रामजन्मभूमि मन्दिर निर्माण कार्य के शुभारंभ की पूर्व संध्या पर सज-धज कर तैयार अयोध्या नगरी का दृश्य

आम आदमी, खास काम

डॉ. बरुण कुमार

भारत के गणतंत्र बनने के बाद देश में विभिन्न क्षेत्रों में यथा कला, समाज सेवा, लोक सेवा, विज्ञान एवं इंजीनियरी, व्यापार उद्योग, चिकित्सा, साहित्य शिक्षा, खेल-कूद, जन सेवा इत्यादि के लिए निःस्वार्थ भाव से अतुलनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों को किसी रंग, लिंग, धर्म, जाति के भेदभाव के बिना प्रत्येक वर्ष पद्मविभूषण, पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा जाता है।

पिछले कुछ वर्षों से ये पुरस्कार ऐसे व्यक्तियों को प्रदान किए जा रहे हैं जो स्वयं गुमनामी में रहकर विपरीत परिस्थितियों में समाज सेवा कर रहे हैं। यहां पद्म पुरस्कारों से पुरस्कृत ऐसे ही दस गुमनाम साधारण व्यक्तियों का परिचय दिया जा रहा है, जिन्होंने बिना किसी प्रतिफल के देश की सेवा में अपना असाधारण योगदान दिया है।

डॉ. दिगंबर बेहरा (पद्मश्री)



डॉक्टर बेहरा उड़ीसा में कटक के एक गांव में अत्यंत गरीब परिवार में जन्मे। इनके मां-बाप अनपढ़ थे। उनका स्कूल घर से 4 किमी दूर था और मुफलिसी में नंगे पांव पढ़ने जाया करते थे, क्योंकि उनके पास जूते नहीं होते थे। पढ़ाई के साथ ही यह अपने पिताजी के साथ खेती में भी हाथ बँटाते थे। जब पीजीआई चंडीगढ़ में अध्ययन कर रहे थे, तो वे ठंड से बचने के लिए कोट उधार लिया करते थे। इन्होंने तपेदिक उन्मूलन, धूम्रपान के खिलाफ अभियान छेड़ा है और इन्होंने ओडिशा के गरीब मछुआरों की धूम्रपान की आदत छुड़ाकर पुण्य का कार्य किया है। यह 67 वर्ष के हैं और अभी भी सक्रिय हैं।

तुलसी गौड़ा (पद्मश्री)

कर्नाटक के होन्नाल्लि गांव की 72 वर्षीया तुलसी गौड़ा हल्ला आदिवासी हैं। अशिक्षित व गरीबी में जीवन यापन करने के बावजूद इन्होंने पिछले 60 वर्षों में लाखों की संख्या में न सिर्फ पेड़-वनस्पति लगाए बल्कि उनकी परवरिश भी की और बंजर भूमि को उपजाऊ बना दिया। पर्यावरण प्रेमी उनके पेड़ पौधों के ज्ञान से आश्चर्यचकित रह जाते हैं। उन्हें 'इनसाइक्लोपीडिया ऑफ जंगल' भी कहा जाता है।



मनोहर देवदास (पद्मश्री)

तमिलनाडु के मनोहर देवदास एक नामचीन कलाकार हैं जिन्होंने कई ऐतिहासिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक कलाकृतियों को अंजाम दिया। 5 वर्ष पूर्व इनकी आंखों की रौशनी चली गई, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और मद्रास, मदुरै की लैंडमार्क से संबंधित पेंटिंग-चित्रकारी बना रहे हैं।



हरेकला हजब्बा
(पद्मश्री)



कर्नाटक के हरेकला हजब्बा एक अशिक्षित फल विक्रेता हैं, जो प्रतिदिन न्यू पेडुप्पु गांव से 25 किमी चलकर मंगलुरु में संतरे बेचने जाते हैं। श्री हजब्बा के जीवन में उस समय मोड़ आया जब एक विदेशी जोड़े ने उनसे अंग्रेजी में संतरे खरीदने की बात कही। उन्हें अंग्रेजी नहीं आती थी और केवल स्थानीय बोली, तुलु और बियरी ही बोल सकते थे। तब से उन्होंने निश्चय किया कि वे स्वयं भी पढ़ेंगे और भावी पीढ़ियों को भी पढ़ाएंगे। समाज में उनका मजाक उड़ाया जाता था। उनके बच्चे बीड़ी बनाकर बेचते थे। इस अल्प अर्जन से उन्होंने स्कूल बनवाए और सबसे गरीब बच्चों को शिक्षा मुहैया कराई। इनका अगला उद्देश्य एक प्री-यूनिवर्सिटी स्थापित करना है।

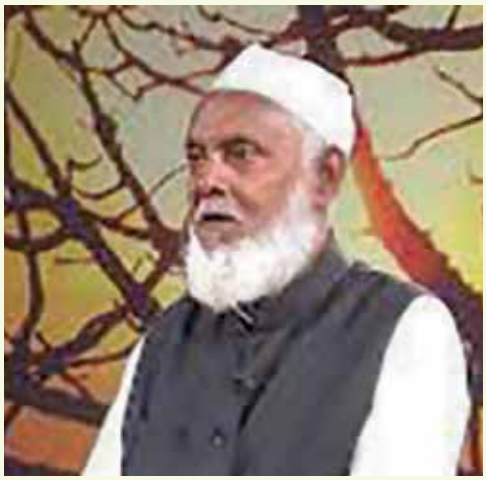


जगदीश लाल आहूजा (लंगर बाबा)
(पद्मश्री)

'लंगर बाबा' के नाम से मशहूर पंजाब के 84 वर्षीय जगदीश लाल आहुजा वर्ष 1980 से लगातार गरीब लोगों को मुफ्त में भोजन मुहैया कराते हैं। चंडीगढ़ में पीजीआई के सामने तथा एक अन्य अस्पताल के बाहर प्रतिदिन 2,000 से ज्यादा लोगों को भोजन के साथ कपड़े, कंबल आदि भी देते हैं। इसके अलावा वित्तीय मदद भी करते हैं। लोगों की नि:स्वार्थ भाव से सेवा के लिए इन्होंने अपनी जमीन-जायदाद तक बेच दी। विभाजन के बाद अत्यंत विपरीत परिस्थितियों में इनके पिताजी सड़क पर ठेला लगाकर सामान बेचा करते थे और ये स्वयं फुटपाथ पर जा-जाकर लोगों को दाल-चावल आदि के छोटे-छोटे पैकेट बनाकर बेचा करते थे।

मोहम्मद शरीफ
(पद्मश्री)

80 वर्षीय 'चाचा शरीफ' के नाम से मशहूर मोहम्मद शरीफ उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले के निवासी हैं। पेशे से साइकिल मैकेनिक चाचा शरीफ अत्यंत गरीब हैं और उनके परिवार का खर्चा मुश्किल से चलता है। 1992 के दंगे में उनके बेटे का इंतकाल हो गया था। उसके बाद से वे बिना भेदभाव के गरीब मजलूमों की लावारिस लाशों का उनके धर्मानुसार अन्तिम संस्कार करवाते हैं। आमिर खान के टीवी के धारावाहिक 'सत्यमेव जयते' में भी इन्होंने शिरकत की थी।



जावेद अहमद टाक
(पद्मश्री)

कश्मीर के अनंतनाग जिले के 46 वर्षीय जावेद अहमद टाक 1997 में आतंकी गोली लगने के चलते दिव्यांग हो गए, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी दिव्यांगता को ही अपना हथियार बना लिया। पिछले 2 दशकों से मानवता कल्याण संगठन और जैबा आपा स्कूल के जरिए कश्मीर के बच्चों को मुख्यधारा में लाने का कार्य कर रहे हैं। सिरफिरे लोगों को काम पर लगा रहे हैं और सैकड़ों बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा मुहैया करा रहे हैं तथा कई ग्रामीण परियोजना को कार्यान्वित किया है।





सुश्री उषा चौभार
(पद्मश्री)

राजस्थान की उषा चौभार सड़कों पर झाड़ू लगाती थीं और हाथों से कूड़ा उठाकर साफ-सफाई करती थीं। इनका काम इतना गंदा था कि कभी-कभार ये अपना खाना तक नहीं खा पाती थीं। एक स्वयंसेवी संगठन की मदद से इन्हें एक सम्मानजनक जीवन जीने का मौका मिला। इन्होंने अपनी लगन से सिलाई, फूड प्रोसेसिंग, मेहंदी आदि लगाने का काम सीखा और आत्मनिर्भर बनीं। इन्होंने हाथ से मैला ढोने की प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई और सैकड़ों महिलाओं को इस काम से निजात दिलाई। वर्तमान में ये सुलभ अंतरराष्ट्रीय सामाजिक सेवा संगठन की अध्यक्षा हैं।



एस. रामाकृष्णन
(पद्मश्री)

तमिलनाडु के श्री एस. रामाकृष्णन ने गर्दन से नीचे तक लकवाग्रस्त, दिव्यांग होने के बावजूद भी व्हीलचेअर से ही ग्रामीण इलाकों में जाकर सामाजिक कार्य किया और पोलियो शिविर लगवाए। दिव्यांगों के लिए इंटीग्रेटेड स्कूल खोले और 'अमर सेवा संगम' संस्था का गठन किया और स्वयं दिव्यांग व लकवाग्रस्त होने के बावजूद व्हीलचेअर से दिव्यांगों को सक्षम बनाने में लगे हुए हैं।

इंद्रादस्स नायके
(पद्मश्री)

भारत में जन्मी लखनऊ विश्वविद्यालय की छात्रा रह चुकी इंद्रादस्स नायके ने श्रीलंका में हिंदी के प्रयोग-प्रसार के क्षेत्र में अतुलनीय कार्य किया। श्रीलंका के शिक्षण संस्थानों में हिंदी विषय लागू करवा कर अपना अहम योगदान दिया है। ये केलानिया विश्वविद्यालय में हिंदी की विभागाध्यक्षा रह चुकी हैं और इनके सतत् प्रयासों से श्रीलंका के 6 विश्वविद्यालयों तथा 80 से अधिक शिक्षण संस्थानों में हिंदी पढ़ाई जाती है।



औषधि - वाटिका

डॉ. प्रसून कुमार त्रिपाठी

आधुनिकता के नाम पर अपनी परंपरागत विचाराधाराएं त्याग कर नए ढंग अपनाने की होड़ लगी है। हम लोगों ने जिन मौलिक चीजों का त्याग किया, उनमें से एक है जड़ी-बूटियां, औषधि वनस्पति आदि, लेकिन आधुनिक विज्ञान तथा रोग-चिकित्सा पद्धति की मर्यादा धीरे-धीरे स्पष्ट होने लगी हैं। ऐसी अवस्था में हमें पारम्परिक चिकित्सा पद्धति तथा पुनः प्रकृति की ओर के मंत्र पर निर्भर होना पड़ेगा अर्थात् औषधि वनस्पतियों के गुणों को पहचानना पड़ेगा। इन वनस्पतियों को आप अपने घरों में छोटी-सी वाटिका के रूप में या गमलों में आसानी से लगा सकते हैं। ये पौधे सामान्य रोगों के उपचार में बहुत लाभदायक हैं। तो आइए, औषधीय पौधों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं।

कलिहारी

स्थानीय नाम - कलिहारी

वानस्पतिक नाम - Gloriosa Superba

औषधीय गुण एवं उपयोग - यह शोध, कंठमाल, गठिया व बाह वेदना, कुष्ठ तथा अर्श में टॉनिक के रूप में उपयोगी होता है। यह मूढ़ गर्भपातन में भी उपयोगी है। इसका पंचाग (जड़, तना, फूल, फल व पत्ती) बहुत उपयोगी होता है।



ईसबगोल

स्थानीय नाम - ईसबगोल

वानस्पतिक नाम - Plantago Ovata

औषधीय गुण एवं उपयोग - ईसबगोल उच्च कोलेस्टॉल, अल्सरी, पेचिश, खुश्क आंत एवं आंत से सम्बन्धित अन्य विकारों में एक अच्छी औषधि मानी जाती है। पाचन तंत्र की बीमारियों में ईसबगोल एक कारगर औषधि के रूप में प्राचीन काल से उपयोग में लाई जाती है। इसकी भूसी जहां एक ओर दस्त एवं आंत की समस्या से राहत देती है, वहीं कब्ज एवं रुके हुए मल को सहज ढंग से सम्पन्न करने में अत्यन्त उपयोगी है। भूसी में अपने वजन का कई गुना पानी सोखने की क्षमता होती है। ईसबगोल अमीनो एसिड एवं लिनोलिक एसिड का भी अच्छा स्रोत है।



नीम

स्थानीय नाम - नीम

वानस्पतिक नाम - Azadirachta India

औषधीय गुण एवं उपयोग - परामपरागत रूप से नीम का उपयोग विभिन्न रोगों, जैसे त्वचा के रोग, दांत के रोग, फोड़े -फुंसी, मधुमेह, जोड़ों के दर्द इत्यादि में प्रयोग किया जाता है।



मीठा नीम

स्थानीय नाम - मीठा नीम

वानस्पतिक नाम - Murraya Koenigii

औषधीय गुण एवं उपयोग - मीठे नीम की पत्तियां अतिसार रोधी, शक्तिवर्धक, मधुमेह इत्यादि में लाभदायक होती हैं। यह एण्टीऑक्सीडेंट के रूप में भी कार्य करती हैं।



अमृता

स्थानीय नाम – गुर्च

वानस्पतिक नाम – Tinospora cordifolia

औषधीय गुण एवं उपयोग – सभी प्रकार के पुराने बुखार में, यकृत जन्य बीमारियों, जैसे भूख न लगना, पीलिया, मधुमेह में, चर्म रोगों में, जैसे खुजली, फोड़ा-फुन्सी, मासिक धर्म के विकार जैसे अधिक/कम खून आना। गुर्च की बेल (पत्ती रहित) को पीसकर रस निकालकर 1-1 चम्मच रस शहद के साथ या केवल रस का सेवन खाली पेट सुबह करें। डाली को कूट-पीसकर सुखाकर रख लें। इसको 5-5 बूंद सुबह-शाम शहद के साथ लें।



बेल

स्थानीय नाम – बिल्व या बेल

वानस्पतिक नाम – Aegle marmelos

औषधीय गुण एवं उपयोग – इसका फल एवं औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके उपयोग से पुरानी पेचिश, आंव (संग्रहणी) ठीक हो जाती है। इसके पत्तों का रस दस दिन तक लगातार सेवन करने से मधुमेह/डायबिटीज में फायदा होता है।



बहेडा

स्थानीय नाम – बहेडा या विभीतक

वानस्पतिक नाम – Terminalia bellerica

औषधीय गुण एवं उपयोग – प्रसिद्ध त्रिफला चूर्ण का यह तीसरा घटक है, जिसे प्राचीन काल से कई रोगों को दूर करने में अकेले भी प्रयोग किया जाता है। आयुर्वेदीय ग्रंथों में शोथहर यानी सूजन व दर्द को कम करने वाला तथा श्लेष्म हर यानी कफ को निकालने वाला माना गया है। इसका उपयोग सूजन, कफ खांसी, कब्ज, बवासीर तथा चर्म विकार में किया जाता है।



शतावर

स्थानीय नाम – शतावर, शतावरी

वानस्पतिक नाम – Asperagus racemosus

औषधीय गुण एवं उपयोग – इसका उपयोग श्वेत प्रदर, पेशाब में खून आना, अनिद्रा, कमजोरी में किया जाता है। शतावर की सूखी जड़ को पीसकर 2-2 चम्मच चूर्ण दूध से सुबह-शाम पीने से दूध पिलाने वाली माताओं के दूध में वृद्धि होती है एवं शरीर बलवान रहता है। श्वेत प्रदर में सूखी जड़ का 5 से 10 ग्राम चूर्ण एंव जीरा चूर्ण 10 ग्राम एक कप दूध के साथ सुबह खाली पेट पीने से तनाव-कमजोरी से होने वाला श्वेत प्रदर ठीक हो जाता है।



तुलसी

स्थानीय नाम – तुलसी

वानस्पतिक नाम – Ocimum sanctum

औषधीय गुण एवं उपयोग – इसका उपयोग खांसी, बुखार, दमा, जुकाम, गले में खराश आदि में किया जाता है। जुकाम, खांसी या ज्वर में सुबह खाली पेट तुलसी के पत्तों का 1-1 चम्मच रस शहद में चाटें। पुरानी खांसी में पत्तों का रस अदरक के रस के साथ सुबह-शाम शहद से लेने पर लाभ होता है। गले की खराश में पंचाग का काढ़ा पीने या गरारे करने से खराश ठीक हो जाती है।



नींबू घास

स्थानीय नाम – नींबू घास

वानस्पतिक नाम – Cymbopogon flexuosus

औषधीय गुण एवं उपयोग – इसके तेल का उपयोग धोने वाले साबुन तथा दूसरे घरेलू उत्पादों को सुगन्धित बनाने में किया जाता है। सिट्रल से एल्फा और बीटा आयोनोन तैयार किए जाते हैं।



ब्राह्मी

स्थानीय नाम – ब्राह्मी

वानस्पतिक नाम – Bacopa monnieri

औषधीय गुण एवं उपयोग – इसका उपयोग स्मरण शक्ति बढ़ाने में, मन्द बुद्धि, अनिद्रा व तनाव आदि में किया जाता है। स्मृति शक्ति हेतु ब्राह्मी के पंचाग का 1 से 2 चम्मच रस घी में मिलाकर अथवा सूखा हुआ पंचाग 2 रत्ती से 5 रत्ती तक एक कप दूध के साथ लिया जा सकता है। मानसिक तनाव में सुबह-शाम 5 ग्राम ब्राह्मी चूर्ण गाय के घी से लेने पर लाभ होता है।



पिप्पली

स्थानीय नाम – पिप्पली छोटी पीपल

वानस्पतिक नाम – Piper longum

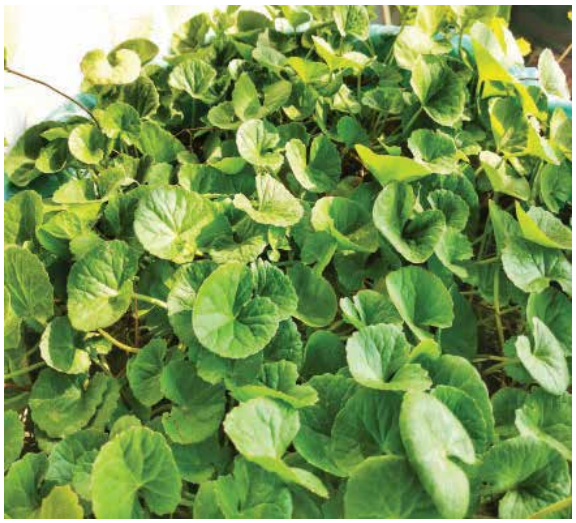
औषधीय गुण एवं उपयोग – इसका उपयोग खांसी, बुखार, सांस फूलना या दमा, पेट के रोग, वात जनित दर्द में किया जाता है। बराबर मात्रा में छोटी पिप्पली, काली मिर्च व सोंठ को पीसकर मिश्रण (त्रिकूट या त्रिकटु) बना लें। 8 वर्ष के बच्चे को एक चुटकी (200-300 मिलीग्राम), बडों को 1-2 ग्राम त्रिकटु शहद के साथ सुबह-शाम खाली पेट देने से 4-5 दिन में खांसी से लाभ होता है। इसे लेने से आधे घंटे पहले और बाद में कुछ भी खाना-पीना नहीं चहिए। हल्के पुराने बुखार के लिए ऊपर बताई गई मात्रा 5-10 बूंद घी में मिलाकर लें।



मण्डूकपर्णी

स्थानीय नाम – मण्डूकपर्णी / ब्राहमी (हरिद्वारी)
वानस्पतिक नाम – Centella asiatica

औषधीय गुण एवं उपयोग – इसका उपयोग मन्द बुद्धि, अनिद्रा, स्मृति ह्रास, चर्म रोग, अपच, बदहजमी में किया जाता है। स्मृति ह्रास व मन्द बुद्धि व्यक्तियों हेतु ताजे पत्तों का 1-2 चम्मच रस शहद से सुबह खाली पेट लगातार लें। अनिद्रा या अपच में पंचाग को छाया में सुखाकर चूर्ण बनाकर रखें। इसको 2-3 ग्राम सुबह-शाम शहद से लें।



भुई आंवला

स्थानीय नाम – भुई आंवला
वानस्पतिक नाम – Phyllanthus amarus

औषधीय गुण एवं उपयोग – इसका उपयोग पीलिया, बदहजमी, जी मिचलाना, भूख न लगना, फोड़े-फुंसी व खुजली में किया जाता है। ताजे पंचाग का 1-2 चम्मच रस सुबह-शाम शहद के साथ लेने पर पीलिया या यकृत जन्य रोगों में हफ्ते भरे में अमूल परिवर्तन होते हैं। खुजली या फोड़ा-फुंसी में पूरे पौधे को पीस कर रोगग्रस्त भाग में लगाने व रस पीने में लाभ होता है।



अश्वगंधा

स्थानीय नाम – अश्वगंधा, असगंधा
वानस्पतिक नाम – Withania somnifera

औषधीय गुण एवं उपयोग – यह एक उच्च कोटि का रसायन, बलवर्धक एवं बाजीकरण औषधि मानी जाती है। इसके अतिरिक्त इसका उपयोग, आमवात (गठिया), नाडी बल्य, दीपन पाचन, उन्माद एवं अवस्मार आदि व्याधियों में किया जाता है। यह लगभग 150 से भी ऊपर विभिन्न आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधियों के निर्माण में घटक द्रव्य के रूप में किया जाता है।



मोथा

स्थानीय नाम – मोथा
वानस्पतिक नाम – Cyperus rotunudus

औषधीय गुण एवं उपयोग – यह गठिया, रियूमटाइड (आम वात) तथा आस्टियो आर्थराइटिस (संधिवात) तथा आंव के कारण उत्पन्न गठिये में लाभकारी है। मोथा घास के जड़ से लगी छोटी-छोटी गांठें निकालकर, स्वच्छ कर सुखाकर चूर्ण बना लेते हैं। इस चूर्ण का जल से सेवन किया जाता है।



सदाबहार

स्थानीय नाम – सदाबहार, सदाफुल, सदासुहागन
वानस्पतिक नाम – Catharanthus roseus

औषधीय गुण एवं उपयोग – पत्तियों से प्राप्त एल्केलायडस विनब्लास्टिन और विनक्रिस्टीन का उपयोग एंटीकैंसर के रूप में किया जाता है। जड़ से प्राप्त श्राराभो का उपयोग हृदय एवं उच्च रक्तचाप का बीमारियों में किया जाता है।



हरड़

स्थानीय नाम – हरीतकी या हरण
वानस्पतिक नाम – Terminalia Chebula

औषधीय गुण एवं उपयोग – यह पाचक रसों को अधिक सक्रिय बनाकर मेटाबॉलिक ट्रांसफॉरमेशन में सहायता देकर क्षुधा, बल और बुद्धि की वृद्धि करती है। इसका उपयोग कब्ज में या अन्य उदर रोगों में किया जाता है।



वच

स्थानीय नाम – घोडवच, वच
वानस्पतिक नाम – Acorus calamus

औषधीय गुण एवं उपयोग – कफ और वात का शमन करने तथा पित्त को बढ़ाने वाली वच, वाणी एवं बृद्धि में निखार लाती है। यह मिरगी, स्मृतिनाश, बच्चों का हकलाना, भूख न लगना व पेट दर्द तथा मोटापा दूर करने में भी लाभदायक है।



आंवला

स्थानीय नाम – आंवला या आमलकी
वानस्पतिक नाम – Emblica officinalis

औषधीय गुण एवं उपयोग – यह वात, पित्त, कफ, त्रिदोष शामक होने के कारण विशेष लाभकारी है। यह शरीर की शक्ति बढ़ाता है प्रसिद्ध त्रिफला चूर्ण का यह दूसरा महत्त्वपूर्ण घटक है। इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिससे इसके सेवन से रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा होती है।



अडूसा

स्थानीय नाम – वासा

वानस्पतिक नाम – Adhatoda Vasica

औषधीय गुण एवं उपयोग – हर प्रकार की खांसी में ताजे पत्तों का 1/2 चम्मच रस शहद या गुड़ से सुबह-शाम लेने पर लाभ होता है। इसके पंचाग (जड़, तना, फूल, फल एवं पत्ती) का 4-4 चम्मच काढ़ा सुबह-शाम शहद के साथ लेने से दमा में लाभ होता है।



काल मेघ

स्थानीय नाम – काल मेघ

वानस्पतिक नाम – Andrographis paniculata

औषधीय गुण एवं उपयोग – इसका पंचांग (जड़, तना, फूल, फल एवं पत्ती) पुराने बुखार, चर्म रोग, पेट के कीड़े, एलर्जी एवं घाव में उपयोग किया जाता है। साधारणतया इसके पत्तों का रस निकालकर शहद के साथ चाटा जाता है। ताजे पत्तों को पीस कर, रस निकालकर करीब 1-1 चम्मच रस शहद से लिया जाता है।



घृत कुमारी

स्थानीय नाम – घीकवार

वानस्पतिक नाम – Aloe vera

औषधीय गुण एवं उपयोग – घृतकुमारी के मोटे पत्तों को काटकर, उसका गूदा निकालकर मिश्री की चाशनी बनाकर उसका पाक बना लें। इस पाक का सुबह शाम 1-1 चम्मच सेवन करें। गूदे के एक टुकड़े को सुबह खाली पेट खाने से कब्ज व उदर विकार अच्छा हो जाता है। चोट या जलने पर गूदे को चीरकर जले-कटे स्थान पर हल्दी चूर्ण के साथ लगाएं। इसका उपयोग जलने पर, बवासीर में, कटने पर, चेहरे/शरीर का सौन्दर्य निखारने में, कफ में, मासिक धर्म की गड़बड़ियों में तथा पीलिया व यकृत विकार में किया जाता है।



ज्वाराकुश

स्थानीय नाम – ज्वाराकुश

वानस्पतिक नाम – Cymbopogon Jwarankusha

औषधीय गुण एवं उपयोग – इसका उपयोग ज्वर, जुकाम, खांसी, सिरदर्द, सांस की परेशानी में किया जाता है। आमतौर पर इसके पत्तों को सुबह-शाम चाय में डालकर लगातार पीने से सर्दी-जुकाम से बचा जा सकता है। पत्तियों का 1-1 चम्मच रस शहद से लेने पर खांसी या गले की खराश ठीक हो जाती है।



उप-महानिदेशक (उद्यान), केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, नई दिल्ली

किरदार भी, इन्सान भी

श्री अविनाश त्रिपाठी

90 के दशक की बात रही होगी। स्कूल के कड़े अनुशासन से कॉलेज के खुले माहौल में पहुंचा ही था कि फ्रेशर पार्टी की तैयारी शुरू हो गई। सौभाग्य से फ्रेशर पार्टी के संचालन की महती जिम्मेदारी मुझे दी गई। प्रोग्राम शुरू होने से लेकर अंत तक जो गाने गाए गए उसमें 90 प्रतिशत किशोर दा के थे। किसी फ्रेशर विद्यार्थी ने अपनी सहपाठी को देख प्रेम निवेदन किया हो 'दिल क्या करे जब किसी से, किसी को प्यार हो जाए' के रूप में या 'मेरे सपनों के रानी कब आएगी तू', सब किशोर के गीत से अपनी भावनाएं जोड़ रहे थे। उस दिन पहली बार अहसास हुआ कि इस कमाल शख्स के पास हर मर्ज का इलाज है।

बारिशों के महीने में पानी बादलों में भरकर, सूरज के ताप को हल्का कर देता है। यही पानी जब बरसता है तो कई लोग अपने गम को आंसुओं को इन्हीं पानी की ओट में छुपा लेते हैं। ऐसे ही भीगे-भीगे मौसम में भारत के दिल मध्य प्रदेश में आवाज पर नक्काशी करने वाला एक कलाकार पैदा हुआ।

खंडवा के बड़े वकील के घर पैदा हुए आभास कुमार गांगुली ने किशोर कुमार बनने तक का सफर खेलते-कूदते तय कर लिया। बड़े भाई अशोक कुमार की तरह फिल्मों में अभिनय से शुरुआत तो की, लेकिन अपने नाम के आगे हिन्दुस्तान के सबसे पॉपुलर गायक का खिताब जोड़कर अपनी शख्सियत को इतने रंग दे दिए कि आने वाली पीढ़ियां किसी एक इंसान में इतनी खूबी को लेकर सिर्फ अचरज कर सकेंगी। फिल्म 'शिकारी' से अभिनय की शुरुआत करके जल्दी ही उन्होंने विमल रॉय जैसे बड़े डाएरेक्टर की फिल्म हासिल कर ली। विमल दा की फिल्म 'नौकरी' में बेरोजगार युवक की भूमिका में अभिनय का उजला पक्ष दिखाने वाले किशोर कुमार सिर्फ इतने से ही संतुष्ट होने वाले नहीं थे। खेमचंद प्रकाश के निर्देशन में





गायकी की शुरुआत के कुछ सालों तक अपनी इस प्रतिभा को गंभीरता से न लेने के कारण कभी-कभार ही गाने वाले किशोर की असली प्रतिभा को एस.डी. बर्मन ने परखा। तब तक अपने आदर्श के एल सहगल को कॉपी करते किशोर अपने अलग अंदाज से नावाकिफ थे। बर्मन दा ने उन्हें असली किशोर से मिलवाया जिसकी आवाज में मिठास के साथ, युवा उर्जा तथा पुरुषत्व से भरपूर भारीपन था। हालाँकि बचपन में किशोर की आवाज खासी पतली थी और वो जब सुर लगाते, घर वाले उनकी फटी आवाज का मजाक उड़ाते। इंदौर के क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ाई का सुर साधते किशोर अक्सर कैंटीन में पाए

जाते। क्लास और कैंटीन, दोनों की टेबल का इस्तेमाल किशोर अपनी हथेली की धमक यानी तबले के रूप में इस्तेमाल करते। इसी कैंटीन का 5 रुपया 12 आने का उधार किशोर ने अपने गीत में उतार दिया था। अपनी जिन्दगी में बीते ढेर सारे सच और घटनाओं को किशोर अपने गीत में पिरो देते और वो गीत सच और फसाने के बीच झूलता बेहद कामयाब हो जाता। अपने मजाकिया और खिलंदड़े स्वभाव की वजह से किशोर आवाज में जो अभिनय भरते थे उसका कोई सानी नहीं था। 'हाफ टिकट' का वो यादगार गाना : 'आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटारिया' का पुरुष और महिला, दोनों स्वरों में बखूबी गाना सिर्फ किशोर जैसा जीनियस ही कर सकता था। इसके पीछे भी कहानी है कि संगीत निर्देशक सलिल चौधरी इस गीत को मेल और फीमेल किशोर और लता की आवाज में रेकॉर्ड करना चाहते थे। लता मंगेशकर के शहर से बाहर होने की वजह से किशोर का यह आइडिया सलिल चौधरी को पसंद आया और फिर इतिहास हो गया। उम्र बढ़ने के साथ किशोर कुमार के हुनर में भी गजब की कशिश बढ़ती चली गई। आर. डी. बर्मन के संगीत और गुलजार की कलम ने किशोर को उनके उरूज पर बैठा दिया। 'हजार राहें मुड़ के देखीं' या फिर 'तुम आ गए हो नूर आ गया है' जैसे गानों ने किशोर कुमार को गायकी का सबसे चमकता नक्षत्र बना दिया। जिन्दगी का कोई गहरा फलसफा हो तो किशोर 'जिन्दगी का सफर, ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं', जैसे गीतों से जीवन दर्शन को बेहद सादगी से रख देते। प्यार के पारदर्शी सफेद शामियाने में, मोहब्बत सी भरी कोई शाम सजानी हो तो किशोर 'ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए' गुनगुनाते। किसी को दिल का हाल बताना हो तो 'पल-पल दिल के पास तुम रहती हो', का राग छेड़ देते। बनते-बिगड़ते रिश्तों को 'तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो चरागों से लौ जा रही थी', से संवारना हो या दिल टूटने के बाद होंठों पर खुद ही बद्दुआ आ जाय 'मेरी भीगी-भीगी सी पलकों पे रह गए जैसे मेरे सपने बिखर के', किशोर ने हर भाव को अपने दिल के सबसे महीन राग पर रख दिया। भाव, गले के नक्काशीदार रास्तों गुजर, होंठों तक आते मनोभाव जब स्वर के माध्यम से दिलो-दिमाग में उतरते तो हर हिंदुस्तानी उनका मुरीद बन जाता। गाने के साथ अभिनय में भी बेहद पारंगत किशोर, किरदार को अपने चेहरे और जिस्म के साथ, अपना खास लहजा और एक पागलपन दे देते। एक शूट में वो कार में बैठे और डायरेक्टर के 'कट' न कहने पर कार से चलकर पनवेल तक जा पहुंचे। अपने अभिनय और गायन, दोनों में अपने मेहनताने को लेकर बेहद सजग किशोर कुमार ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध निर्देशक सत्यजीत रे की फिल्म 'चारुलता' के लिए किसी भी पारिश्रमिक से इंकार कर दिया था। यही नहीं, अपनी विश्व प्रसिद्ध फिल्म 'पाथेर पांचाली' के वक्त आई आर्थिक समस्या से उबारने में भी किशोर कुमार ने अहम् योगदान दिया। किशोर ने अपनी तरफ से 5,000 रुपये देकर रे के बंद पड़े प्रोडक्शन में दोबारा जान फूंक दी थी। भारतीय संस्कृति में रचे बसे किशोर कुमार को विदेशी मुख्यत: हॉलीवुड फिल्मों से भी बेहद लगाव था। मशहूर सिंगर एक्टर डैन्नी को बेहद पसंद करने वाले किशोर ने अपनी खास यूडलिंग को भी हॉलीवुड सिंगर टैक्स मोर्तो और जिम्मी रोजर से प्रभावित होकर सीखा। बिना किसी शास्त्रीय या पाश्चात्य संगीत की विधिवत् शिक्षा लिए किशोर अपने गले में जो हरकत लाते,



सुनने वाला हतप्रभ खड़ा उनकी ईश्वरीय देन पर चकित होता रहता। किशोर गाने में सुर और ताल का ही नहीं, बल्कि गाना जिस अभिनेता पर फिल्माया जाने वाला है, उसके मैनरिज्म का भी खास खयाल रखते। राजेश खन्ना का रोमानी मखमली अंदाज हो, तो किशोर अपनी आवाज की टिम्बर पर, इश्क की कढ़ाई कर देते, देवानंद का चिर युवा और खिलंदड़ अंदाज हो तो किशोर के सुर में बेफिक्री चहलकदमी करने लगती। अमिताभ की बुलंद शख्सियत के हर हिस्से पर किशोर मरदाना आवाज की गहराई इस तरह टांक देते कि मोहब्बत की पुकार में रोमानियत के साथ-साथ एक दृढ़ता और मजबूती भी झलकती। अभिनेता के शख्सियत को अपनी आवाज के अभिनय से निखारते किशोर खुद आला दर्जे के अभिनेता थे, लेकिन बहुमुखी प्रतिभा का कलाकार अक्सर बेहद मूडी होता था। कहा जाता है हृषिकेश मुखर्जी की बहुचर्चित फिल्म 'आनंद' की पहली पसंद किशोर कुमार थे। उसी समय एक और बंगाली प्रोड्यूसर, किशोर को अपनी फिल्म में लेना चाहता था, लेकिन बेहद मनमौजी किशोर उसके साथ काम नहीं करना चाहते थे। हृषिकेश जब किशोर कुमार के बंगले पर पहुंचे, तो किशोर के वॉचमैन ने उन्हें वही बंगाली प्रोड्यूसर समझ लिया और इस गलतफहमी के तहत् हृषि दा किशोर से मिल नहीं पाए और अंतत: 'आनंद' राजेश खन्ना के पास चली गई। इन्हीं राजेश खन्ना को पहले स्टार और फिर सुपरस्टार बनाने में किशोर की रूमानी आवाज ने बेहद अहम् भूमिका निभाई। यही नहीं, हृषि दा किशोर की प्रतिभा और उनकी जिन्दगी से इतना प्रभावित थे कि उनकी फिल्म 'अभिमान' भी किशोर और उनकी पहली पत्नी रुमा गुहा ठाकुरता की जिन्दगी के कई हिस्सों पर आधारित थी। अपनी निजी जिन्दगी में कभी बेहद रूमानी, कभी मनमौजी किशोर ने 4 बार दिल लगाया। रुमा, मधुबाला, योगिता बाली और लीना चंद्रावरकर के साथ सात फेरे घूम चुके किशोर, अपनी पत्नियों को मजाक में 'बंदरिया' कहते थे और इसकी वजह वो उन सबका संबंद्ध मुंबई के बांद्रा से होना बताते थे। अपने गाने से हर बड़े स्टार को और बड़ा स्टार बनाने वाले किशोर ने निर्देशन, संगीत निर्देशन, अभिनय, फिल्म लेखन सहित लगभग सभी विधाओं में न सिर्फ काम किया बल्कि कामयाबी की नई इबारत लिखते चले गए।

आवाज के बहुत से जादूगर आये लेकिन, टिम्बर, थ्रो, लर्जिश, वेरिएशन और रेंज का इतना बड़ा हुनरबाज कोई दूसरा आएगा, इस पर हमेशा संदेह रहेगा। ■

पर्यावरण संरक्षण पर इतना काम, भारतीय रेल को सलाम

डॉ. आशीष दुबे

विश्व के हर मंच पर ग्लोबल वार्मिंग की चिंता जताई जा रही है। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम करने की शपथ ली जा रही है। साथ ही, कई उपाय/योजनाओं पर अमल करने की पहल की जा रही है। इन्हीं चिंताओं व पहल के बीच 15 फरवरी, 2020 को ट्रेन से नागपुर से कानपुर के प्रवास के दौरान एक पत्रिका मैंने पढ़ी। इस पत्रिका में पर्यावरण पर बढ़ते खतरों से अवगत कराया गया था। यह भी बताया गया था कि कि इन खतरों व चुनौतियों से जल्द नहीं निपटा गया तो पृथ्वी पर भारी संकट आने से रोका नहीं जा सकता। पत्रिका में लिखे लेख को पढ़ने के साथ ही मस्तिष्क में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के प्रश्नपत्र एक में लगातार तीन वर्ष स्वच्छता, ऊर्जा व पर्यावरण संवर्धन की दिशा में भारतीय रेल द्वारा की गई पहल व तैयार की गई उपाय योजना से जुड़े सवाल की याद आई।



मन में जिज्ञासा हुई कि क्यों न ऊर्जा व पर्यावरण की दिशा में भारतीय रेल द्वारा की गई पहल, बनाई गई योजना व उठाए गए कदमों के संबंध में पढ़ा जाए। कुछ ताजा जानकारी हासिल की जाए। पहली जानकारी जो प्रत्यक्ष में मेरे सामने आई, वह थी बॉयो टॉयलेट्स की, जोकि देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से को जोड़ने वाली ट्रेनों में लगाए गए हैं। जानकारी के दूसरे चरण में मुझे 'पर्यावरण दिवस' के अवसर पर जारी की गई भारतीय रेल की पर्यावरण प्रबंधन उपलब्धियों के बारे में पर्यावर्णीय स्थिरता रिपोर्ट 2018-19 पढ़ने का मौका मिला। इस रिपोर्ट में ऊर्जा का मुख्य उपभोक्ता होने के नाते रेलवे द्वारा ऊर्जा दक्षता और ऊर्जा संरक्षण सुधारने की दिशा में शुरू गए कार्यक्रम की जानकारी दी गई थी। रिपोर्ट से जो जानकारी मिली, उसके मुताबिक रेलवे ने हरित भवन की पहल के कार्यक्रम के रूप में 8 उत्पादन इकाइयों और 12 प्रमुख कार्यशालाओं को आईएफओ 14001 प्रमाणित किया है। 38 डीजल शेड, 8 इलेक्ट्रिक लोको शेड, 3 एमईएमयू/डीईएमयू कार शेड, 2 इंजीनियरिंग कार्यशालाएं और एक स्टोर डिपो को भी प्रमाणित किया जा चुका है। कई स्टेशनों पर सैनिटरी नेपकिन वेंडिंग मशीनें और इनसिनेरेटर भी लगाए जा रहे हैं। कार्बन सिंक बढ़ाने के लिए रेलवे की खाली पड़ी भूमि पर पेड़ लगाने के लिए राज्यों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। 20 माइक्रोन से कम मोटी प्लास्टिक की पैकिंग पर प्रतिबंध लगाया गया है। 128 स्टेशनों पर प्लास्टिक की बोतलें तोड़ने वाली 166 मशीनें लगाई गई हैं। वॉटर रिसाइकिलिंग संयंत्रों और वर्षा के पानी के संचयन के अलावा अनेक पुराने और बेकार जल निकायों को दोबारा ठीक किया गया है।

वास्तव में, इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद मन में यह जानने की जिज्ञासा हुई कि क्या इससे पूर्व भी भारतीय रेल ने स्वच्छता, ऊर्जा व पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कोई कार्य किया था? इस सवाल का जवाब खंगालने के बाद जो जानकारी हाथ लगी, वह वाकई में भारतीय रेल को लेकर हर किसी व्यक्ति की सोच बदलने वाली थी। 17 सितंबर, 2019 को आरंभ किए गए व्यापक श्रमदान के कार्यों की जानकारी मिली। विशेष तौर पर सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करने को लेकर विशेष बल दिया गया था। यह भी स्पष्ट किया गया था कि कार्यक्रम के तहत सभी रेलवे परिसरों से प्लास्टिक कचरे के संग्रह के माध्यम से स्वच्छता को बढ़ावा दिया जाएगा। स्टेशनों पर जाने के संपर्क मार्गों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। हकीकत में देखा जाए तो आज देश में इस बात की बेहद जरूरत है। पर्यावरण संवर्धन की दिशा में भारतीय रेल का भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के साथ हरित पहलों को आगे बढ़ाने के लिए किया गया समझौता भी काबिले तारीफ लगा। हरित विद्युतीकृत रेलवे, नवीकरणीय ऊर्जा, पवन व सौर ऊर्जा से जुड़ी परियोजनाओं को अपने आप में पर्यावरण के प्रति भारतीय रेल की चिंता को दर्शाती नजर आई।

इस बीच एक अखबार में भारतीय रेल द्वारा कचरे से ऊर्जा उत्पादन हेतु देश के पहले सरकारी संयंत्र की स्थापना ईस्ट कोस्ट रेलवे में भुवनेश्वर के मानचेस्वर कैरिज रिपेयर वर्कशॉप में किए जाने से संबंधित खबर को पढ़ने का मौका मिला। खबर में बताया गया था कि यह संयंत्र विभिन्न तरह के कचरे को हाइड्रोकार्बन तरल ईंधन, गैस, कार्बन और पानी में बदल देता है। पॉलीक्रैक संयंत्र में सभी तरह के प्लास्टिक, पेट्रोलियम अपशिष्ट, 50 प्रतिशत तक की नमी वाले मिले हुए ठोस कचरे एमएसडब्ल्यू (नगरपालिका ठोस कचरा), ई-कचरा, ऑटोमोबाइल कचरा, बांस, बगीचे के कचरे इत्यादि सहित सभी जैविक कचरे और जेट्रोफा फल डाले जा सकते हैं। मानचेस्वर कैरिज रिपेयर वर्कशॉप, कोच डिपो और भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से निकले कचरे इस संयंत्र के लिए फीडर मैटेरियल होंगे।

इन सारी जानकारी को पाने के बाद मन से सही मायने में रेलवे के लिए यह उद्‌गार निकले कि पर्यावरण संरक्षण पर इतना काम, भारतीय रेल को सलाम। ■

वरिष्ठ पत्रकार, नागपुर

रेल, पर्यटन व साहित्य को एक साथ संजोए
रेल मंत्रालय द्वारा प्रकाशित एक मात्र हिन्दी मासिक पत्रिका



भारतीय रेल



की सदस्यता अब ऑनलाइन भी उपलब्ध

www.irctctourism.com/IRBRMag

सदस्यता शुल्क

(1 अक्टूबर, 2020 से प्रभावी)

मद		ऑफलाइन सदस्यता शुल्क (₹)	ऑनलाइन सदस्यता शुल्क (₹)
एक प्रति (मासिक अंक)		20	–
एक प्रति (विशेषांक)		70	–
वार्षिक सदस्यता (सर्व साधारण)	एक वर्ष	250	263
	दो वर्ष	460	483
	तीन वर्ष	675	709
वार्षिक सदस्यता (रेलकर्मी)	एक वर्ष	200	210
	दो वर्ष	370	389
	तीन वर्ष	540	567
वार्षिक सदस्यता (विदेशी) सी-मेल द्वारा		1250	1313
वार्षिक सदस्यता (विदेशी) एयर-मेल द्वारा		2500	2625

(वार्षिक सदस्यता शुल्क विशेषांक के साथ)

भुगतान का माध्यम

ऑनलाइन सदस्य www.irctctourism.com/IRBRMag पर सदस्यता शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।

ऑफलाइन डी.डी./चेक/म.ओ./पो.ओ./नगद **देय** – 'व्यापार प्रबंधक, भारतीय रेल, नई दिल्ली'

सदस्यता फॉर्म

नाम .....

पता .....

पोस्ट..... जिला.....

राज्य..... पिन कोड .....

मोबाइल ..... ई-मेल .....

रेल कर्मचारी : हाँ / नहीं वर्तमान सदस्यता (हो तो) संख्या ..... तारीख .....

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें : व्यापार प्रबंधक, कमरा नं. 310, रेल भवन, रायसीना रोड, नई दिल्ली-110001,
टेलीफोन: 011-47845378, 23382531, 45380 (रेलवे) **bmpr310rb@gmail.com**

प्रिय विज्ञापनदाता

रेल मंत्रालय द्वारा प्रकाशित एक मात्र मासिक हिन्दी पत्रिका

भारतीय रेल

में अपना विज्ञापन देकर लाखों उपभोक्ताओं तक अपने उत्पादों की पहुंच बनाएं

भारतीय रेल की विज्ञापन दरें (रुपये में)

विवरण	सामान्य दरें	अनुबंधित दरें
सेकण्ड कवर	10,450/-	9500/-
थर्ड कवर	9500/-	8550/-
पूरा पृष्ठ (विशेष स्थिति जैसे टेक्स्ट से पूर्व व बाद में)	8550/-	7600/-
पूरा पृष्ठ (सामान्य)	7600/-	6650/-
आधा पृष्ठ	5130/-	4180/-
सेन्टर स्प्रेड	15,000/-	13,300/-
सेन्टर स्प्रेड (स्पेशल पोजिशन)	16,500/-	14,700/-

(विज्ञापन चार कलर में)

तीन महीने या ज्यादा समय के लिए लगातार अथवा बारी–बारी विज्ञापन देने पर ही अनुबंधित दरें लागू होंगी

तकनीकी विवरण

पत्रिका का आकार	28 से.मी. x 20.5 से.मी.	छपाई क्षेत्र	23 से.मी. x 16.5 से.मी.

★ पत्रिका का प्रसार **समग्र देश में** ★

विज्ञापन सामग्री – ई–मेल, आर्टपुल, सीडी

संपर्क करें : व्यापार प्रबंधकः प्रशांत कुमार पट्टनायक, मोबाइल :
310, रेल भवन, रायसीना रोड, नई दिल्ली–110001
टेलीफोन : 011–23382531, 23303665, 23304456
Email : bmpr310rb@gmail.com

पंजीयन संख्या : दिल्ली पोस्टल नं. डी.एल. (एन.डी.)-11/6031/2018-19-20
आर.एन.आई. रजिस्टर्ड नं. 14427/1960
आई.एस.एस.एन. 2457-0001
दिनांक 08 को प्रकाशित तथा दिनांक 10-11 को प्रेषित



Electric Locomotives

Traction Motors

Traction Transformers

Pantographs

Harmonic Filters

Driver Cab Air Conditioners

Diesel Locomotives

Traction Alternators

Traction Motors

Radiator Cooling Fans

Dynamic Brake Grids

Dynamic Brake Blower Motors

Auxiliary Generators

Dustbin Blower & Motor

Driver Cab Air Conditioners

Coaches & Trainsets

Air Conditioners with Micro-processors

Bio Vacuum Toilet Systems

FRP Toilet Cubical

Side Panels and Roof Panels for Coach Interiors

Seats and other Accessories for Coach Interiors

Daulat Ram
ENGINEERING

10/2, NH-12, Simrai, Post Obedullahganj, Dist. Raisen, Near Bhopal 464 993 INDIA
Tel.: +91 7480 231400 / 252 / 253, 8889000732 / 34 / 35 / 36. Fax: +91 7480 231250
e-mail: info@daulatram.org • web: daulatram.com

मुद्रक व प्रकाशक : **प्रशान्त कुमार पट्टनायक** द्वारा रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के लिए मैसर्स जे.के. ऑफसेट ग्राफिक्स प्रा.ली., बी-278, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेस-1, नई दिल्ली-20 में मुद्रित व 310, रेल भवन, रायसीना रोड, नई दिल्ली से प्रकाशित। संपादक : **योगेश अवस्थी**